20 जनवरी, 2021* वर्ष-30, पृष्ठ संख्या 60, अंक-1

राजस्थान सुजस

नव वर्ष-2021

नया साल-नया संकल्प

नववर्ष की शुभकामनाएं

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने प्रदेशवासियों को नववर्ष की हार्दिक बधाई देते हुए उनकी सुख-समृद्धि की कामना की है। श्री गहलोत ने कहा है कि नया साल नए लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए नई सोच और नई ऊर्जा के साथ काम करने का अवसर है। उन्होंने ईश्वर से कामना की है कि नए वर्ष में देश और प्रदेश को कोविड-19 महामारी एवं आर्थिक संकट सहित अन्य चुनौतियों से मुक्ति मिले और हम सभी के जीवन में खुशहाली एवं सकारात्मकता आए।

मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार प्रदेश को निरंतर उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ाने के लिए अनेक जनकल्याणकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों का संचालन कर रही है। हमारा प्रयास है कि हम हर क्षेत्र में कुशल प्रबंधन कर प्रदेश के विकास की नई तस्वीर पेश करें।

श्री गहलोत ने इस अवसर पर लोगों से अपील की है कि मास्क अवश्य लगाएं एवं कोरोना से बचाव के लिए हैल्थ प्रोटोकॉल का पालन करें ।

मुख्यमंत्री ने निराश्रित लोगों को बांटे कम्बल

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने नववर्ष की पूर्व संध्या पर जेएलएन मार्ग पर जेकेलोन अस्पताल एवं रामनिवास बाग के पीछे बने नगर निगम के अस्थायी रैन बसेरों में असहाय एवं निराश्रित लोगों को कम्बल बांटे।

श्री गहलोत ने रैन बसेरों में सो रहे लोगों से बड़ी आत्मीयता से बात की और उनके हालचाल पूछे। मुख्यमंत्री ने जेकेलोन अस्पताल के पास स्थित चाय की थड़ी पर चाय पी और वहां लोगों से बातचीत भी की। इस अवसर पर स्थानीय विधायक एवं जनप्रतिनिधिगण उपस्थित थे।

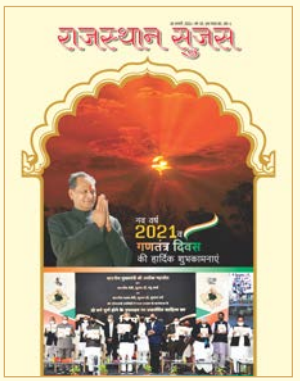

प्रधान सम्पादक
महेन्द्र सोनी, आईएएस
आयुक्त, सूचना एवं जनसम्पर्क

•

सम्पादक
डॉ. लोकेश चन्द्र शर्मा

•

उप सम्पादक
आशाराम खटीक

•

कला
विनोद कुमार शर्मा

•

आवरण छाया
राजेन्द्र शर्मा/सुजस

राजस्थान सुजस में प्रकाशित सामग्री में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं एवं आंकड़े परिवर्तनशील हैं। आवश्यक नहीं कि शासन उनसे सहमत हो। सुजस में प्रकाशित सामग्री का विभाग किसी भी रूप में उपयोग कर सकेगा।

ग्राफिक डिजाइनिंग
प्रिण्ट 'ओ' लैण्ड

सम्पर्क
सम्पादक
राजस्थान सुजस (मासिक)
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग
सचिवालय परिसर
जयपुर - 302 005
e-mail :
editorsujas@gmail.com
Website :
www.dipr.rajasthan.gov.in

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान का मासिक

वर्ष : 30 अंक : 01 **जनवरी, 2021**

इस अंक में

दो वर्ष जन सेवा के

05

सामयिकी

16

सशक्त मतदाता

40

नव वर्ष - 2021...	02
सम्पादकीय	04
रिफाइनरी से होगा...	34
प्रदेश में नए आयाम...	37
नवाचारों से बढ़ा...	38
अपना पोषण - अपना आंगन...	42
जैसलमेर में चिकित्सा...	44
खेत तलाई योजना...	46
किसानों को राहत...	47
रोशन हुई ढाणियां...	48
ई-मित्र कियोस्क...	50
श्रमिक कल्याण...	51
सफलता की कहानी...	52
इंदिरा रसोई योजना...	54
समावेशी शिक्षा...	55
आयुष्मान भारत...	58
टीकाकरण प्रबंधन...	59

राजस्थान सुजस के आगामी अंक के लिए मौलिक, अप्रकाशित सामग्री भिजवायें। कृपया अपने आलेख एवं फोटोग्राफ सम्पादक को e-mail : editorsujas@gmail.com पर अथवा डाक से भेजें।

मीडिया संवाद

12

साक्षात्कार

32

वैक्सीन अभियान

56

जन सेवा के लिए प्रतिबद्ध राज्य सरकार

राजस्थान सरकार ने दो वर्ष के कार्यकाल पूरे होने पर 1362 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास कर जन सेवा के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है। राज्य सरकार ने कोरोना वैश्विक महामारी से बचाव के लिए बेहतर प्रबन्धन किया। अब नववर्ष 2021 में राज्य सरकार का संकल्प है कि कोरोना प्रबन्धन की तरह ही वैक्सीनेशन अभियान में भी राजस्थान देश में मॉडल बने।

कोविड-19 टीकाकरण स्वास्थ्य प्रतिरक्षा की दिशा में एक मजबूत कदम है। 16 जनवरी से राज्य के सभी 33 जिलों में 167 लोकेशन पर एक साथ टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो गई है। टीकाकरण के प्रथम चरण जनवरी माह में केवल हैल्थ केयर वर्कर्स को ही वैक्सीन लगाई जायेगी। इसके बाद चरणबद्ध तरीके से फ्रंट लाइन वर्कर्स, 50 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोग और फिर 50 वर्ष से कम उम्र परन्तु को-मोर्बिड (अन्य बीमारियों से ग्रसित व्यक्तियों) को वैक्सीन लगाई जायेगी। कोविड-19 से बचाव के लिए टीकाकरण में लगाई जा रही वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है। टीकाकरण के लिए पंजीकरण कराना अनिवार्य है। टीकाकरण के संबंध में किसी भी भ्रामक सूचना पर ध्यान न दें।

राज्य सरकार ने बिजली, पानी, सड़क, मकान, चिकित्सा एवं शिक्षा जैसी सभी आधारभूत व्यवस्थाओं का आमजन की सुविधा के अनुरूप विस्तार किया है। राजस्थान सोलर क्रांति की ओर बढ़ रहा है। प्रदेश में अमन, चैन और खुशहाली के साथ राज्य सरकार का यह भी दृढ़ संकल्प है कि प्रदेश का अन्नदाता किसान खुशहाल और समृद्ध बने। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के निर्देश पर सभी पुलिस जिलों में कई नवाचारों के साथ ही महिला अपराधों को रोकने के लिए विशेष इकाई का गठन किया जा चुका है। राज्य सरकार का प्रयास है कि राजस्थान कानून व्यवस्था में देश का सबसे सुरक्षित राज्य बने। शिक्षा के क्षेत्र में भी राज्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। जिला स्तर के बाद अब ब्लॉक स्तर पर भी अंग्रेजी माध्यम के सरकारी स्कूल खोल कर गुणवत्तायुक्त शिक्षा की व्यवस्था को भी राज्य सरकार ने सुनिश्चित किया है।

उद्योगों से जुड़ी समस्याओं के सिंगल विंडो समाधान के लिए वन स्टॉप शॉप व्यवस्था लागू की गई है। एम.एस.एम.ई. उद्योग लगाने पर तीन साल तक किसी अनुमति व निरीक्षण से मुक्ति का कानून प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए महत्त्वपूर्ण कदम है। साथ ही राजस्थान सौर ऊर्जा नीति-2019 व राजस्थान पवन एवं हाईब्रिड ऊर्जा नीति-2019 भी पर्यावरण संरक्षण, उद्योगों में निवेश और रोजगार की दिशा में बेहतरीन प्रयास हैं।

राजस्थान सुजस का यह अंक नये वर्ष 2021 का प्रथम अंक है। यह प्रसन्नता की बात है कि इस अंक से राजस्थान सुजस ने अपने प्रकाशन के 30वें वर्ष में प्रवेश कर लिया है। 29 वर्षों तक किसी पत्रिका के प्रकाशन का सफर अनेक उतार-चढ़ाव और चुनौतियों के दौर का भी होता है। लेकिन यह पत्रिका निरन्तर पाठकों के लिए उपयोगी एवं रुचिकर बनी हुई है। 30वें वर्ष के प्रथम अंक के प्रकाशन पर राजस्थान सुजस से जुड़े सभी लोग बधाई के पात्र हैं।

सभी पाठकों को नव वर्ष – 2021 और गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं।

(महेन्द्र सोनी)
आई.ए.एस.
आयुक्त, सूचना एवं जनसम्पर्क

दो वर्ष जन सेवा के

जनता की उम्मीदों पर खरी उतर रही राज्य सरकार

11 हजार 230 करोड़ के 1362 विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कहा कि लगातार विभिन्न चुनावों के कारण आचार संहिता, कोविड-19 महामारी तथा अर्थव्यवस्था की चुनौतियों के बावजूद राज्य सरकार जनता की आकांक्षाओं और उम्मीदों पर खरी उतरी है। विषम हालातों में भी राज्य सरकार ने मात्र दो साल में ही जन घोषणा पत्र के 50 प्रतिशत से अधिक वादों को पूरा कर दिखाया है। अब प्रयास है कि विकास की गति को आगे बढ़ाते हुए जनता से किए तमाम वादों को पूरा कर राजस्थान को सुशासन के मॉडल के रूप में स्थापित किया जाये।

राज्य सरकार के दो वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर 18 दिसम्बर को मुख्यमंत्री निवास पर राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री व मंत्रीगण ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 11 हजार 230 करोड़ रुपए की लागत के 1362 विकास कार्यों का लोकार्पण, शिलान्यास एवं शुभारंभ किया।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर 25 अप्रैल को रीट परीक्षा के आयोजन की घोषणा की। इस परीक्षा के माध्यम से 31 हजार तृतीय श्रेणी शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। उन्होंने ई-गवर्नेंस की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण पहल के रूप में सभी विभागों की योजनाओं एवं कार्यक्रमों की जानकारी देने वाले जनकल्याण पोर्टल को आमजन को समर्पित किया। इसके साथ ही आमजन को राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने के उद्देश्य से सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग द्वारा राज्य सरकार के दो वर्ष पर प्रकाशित साहित्य राजस्थान सुजस का विशेषांक और दो वर्ष जन सेवा के पुस्तिका का विमोचन भी किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि करीब 22 साल पहले जब वे पहली बार मुख्यमंत्री बने तो राज्य सरकार ने चुनावी घोषणा पत्र को नीतिगत दस्तावेज का रूप देने की शुरुआत की। किसी भी सरकार का अपने वादों को पूरा करने के लिए दर्शायी गई प्रतिबद्धता का यह पहला उदाहरण था। इस बार भी जन घोषणा पत्र को राज्य सरकार ने नीतिगत दस्तावेज का रूप दिया है।

श्री गहलोत ने कहा कि कोविड-19 महामारी ने राजस्थान के साथ-साथ पूरे देश एवं विश्व की तमाम अर्थव्यवस्थाओं एवं विकास कार्यों पर गहरा असर डाला है। इसके बावजूद राज्य सरकार कुशल प्रबंधन कर हर वर्ग को राहत पहुंचाने का काम कर रही है। इस आपदा को अवसर में बदलते हुए दूरगामी सोच के साथ प्रदेश के मेडिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया है। वैक्सीन के सुरक्षित परिवहन, भंडारण एवं वैक्सीन सेंटर्स को लेकर हम पुख्ता इंतजाम कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आजादी के समय प्रदेश में जहां बिजली नहीं के बराबर थी वहीं आज हम ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गए हैं। अब राजस्थान सोलर क्रांति की ओर बढ़ रहा है। आगामी वर्षों में हम राज्य में 30 हजार मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन की ओर मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। यह एक ऐसा सेक्टर है जिसमें सर्वाधिक निवेश राजस्थान में आएगा। इसी तरह राज्य सरकार के प्रयासों से सूरतगढ़ तथा छबड़ा में स्थापित 660-660 मेगावाट की सुपर क्रिटिकल इकाइयों से ऊर्जा के क्षेत्र में राज्य नए कीर्तिमान की ओर अग्रसर है।

श्री गहलोत ने कहा कि गांव-ढाणियों तक स्वच्छ पेयजल आपूर्ति के लिए मास्टर प्लान बनाया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को उनकी उपज का यथोचित मूल्य दिलाने तथा उनकी चिंताओं को दूर करने के लिए विधानसभा में तीन कानून पारित किए हैं। राज्य सरकार का दृढ़ संकल्प है कि प्रदेश का अन्नदाता किसान खुशहाल और समृद्ध बने।

श्री गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार ने थानों में अपराधों का रजिस्ट्रेशन बढ़ने की चिंता किए बगैर अनिवार्य रूप से एफआईआर दर्ज करने का साहसिक फैसला लिया है। साथ ही महिला अत्याचार पर प्रभावी रोकथाम तथा उनसे जुड़े अपराधों के त्वरित अनुसंधान के लिए हर जिले में उप-अधीक्षक का नया पद सृजित किया है। जघन्य अपराधों को रोकने के लिए एक विशेष इकाई का गठन किया जा रहा है। थानों में उचित माहौल में फरियादी की सुनवाई के लिए स्वागत कक्ष बनाए जा रहे हैं। हमारा प्रयास है कि राजस्थान कानून व्यवस्था के मामले में देश का सबसे सुरक्षित राज्य बने।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश तेजी से आगे बढ़ा है। आज एम्स, आईआईटी, आईआईएम, ट्रिपल आईटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थान राजस्थान में स्थापित हो चुके हैं। विगत दो वर्ष में सरकारी क्षेत्र में करीब 90 नए कॉलेज प्रारंभ किए हैं। ब्लॉक स्तर पर अंग्रेजी माध्यम के सरकारी स्कूल भी खोले गए हैं। शिक्षकों की कमी को दूर किया जा रहा है। राज्य सरकार का प्रयास है कि प्रदेश में गांव-ढ़ाणी तक बच्चों को गुणवत्तायुक्त शिक्षा मिले।

श्री गहलोत ने कहा कि उद्योगों की सुगम स्थापना के लिए वन स्टॉप शॉप, एमएसएमई एक्ट, रिप्स-2019, पर्यटन नीति, राजस्थान औद्योगिक विकास नीति-2019, राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति-2019 जारी करने के साथ ही अन्य कई नीतिगत निर्णय लिए गए हैं। आगे भी प्रयास रहेगा कि राज्य सरकार लगातार नीतिगत सुधार करते हुए राजस्थान में उद्योगों को अनुकूल माहौल प्रदान करे ताकि अर्थव्यवस्था पर आये मंदी एवं कोरोना के असर को कम किया जा सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्राम से लेकर जिला स्तर तक आमजन की प्रभावी सुनवाई के लिए कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया गया है। मंत्री तथा अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि आमजन की समस्याओं का त्वरित निराकरण हो। उन्होंने कहा कि कोरोना के बाद प्रदेशभर में प्रशासन शहरों के संग एवं प्रशासन गांवों के संग अभियान चलाकर मौके पर ही विभिन्न विभागों से संबंधित लोगों के जरूरी काम एक स्थान पर किए जा सकेंगे।

सूचना एवं जनसम्पर्क मंत्री डॉ. रघु शर्मा ने कहा कि बीते दो साल में राज्य सरकार ने पूरी शिद्दत से जनता के दु:ख-दर्द को दूर करने का काम किया है और हम सुशासन देने में सफल रहे हैं। जनसम्पर्क विभाग सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को जन-जन तक पहुंचा रहा है।

उन्होंने कहा कि कोविड-19 की चुनौती के बीच हमने गांव-ढाणी तक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत किया है। बीते दो साल में राज्य सरकार के प्रयासों से 15 नए मेडिकल कॉलेजों को राज्य में स्वीकृति मिली है। हाल ही में करीब 2000 चिकित्सकों की नियुक्ति की गई है। चिकित्सा के क्षेत्र में मानव संसाधन की कोई कमी नहीं रहेगी।

शिक्षा राज्यमंत्री श्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि महिलाओं, पिछड़ों, गरीबों तथा शिक्षित बेरोजगारों सहित समाज के हर

वर्ग को लाभान्वित करने के लिए सरकार लगातार एक से बढ़कर एक कल्याणकारी फैसले ले रही है। किसानों की कर्जमाफी के वादे को सरकार ने निभाया है। पांच साल तक कृषि कनेक्शन पर टैरिफ नहीं बढ़ाने जैसा निर्णय किया है। किसानों को दिन में बिजली मिल सके, इसके लिए विद्युत तंत्र को सुदृढ़ करने का काम किया गया है। उन्होंने कहा कि हमने अदालतों में अटकी भर्तियों की बाधाएं दूर कर शिक्षा सहित अन्य सभी विभागों में नियुक्तियों की राह आसान की है।

मुख्य सचिव श्री निरंजन आर्य ने आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में मंत्रीपरिषद के सदस्य, बोर्ड, आयोगों के अध्यक्ष, विधायक सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। राज्य के सांसदगण, विधायकगण, जिला प्रमुख, नगरीय निकायों के प्रमुख तथा सरपंचों सहित सहित अन्य जनप्रतिधि, अधिकारी-कर्मचारी एवं आमजन भी वर्चुअल माध्यम से समारोह से जुड़े। फेसबुक, यू-ट्यूब एवं अन्य सोशल मीडिया माध्यमों पर समारोह का लाइव प्रसारण भी किया गया।

लोकार्पण, शिलान्यास एवं शुभारंभ

सूचना एवं जनसंपर्क विभाग

- ❖ राज्य सरकार के विकास कार्यों पर प्रकाशित साहित्य राजस्थान सुजस और दो वर्ष जन सेवा के पुस्तिका का विमोचन
- ❖ राज्य सरकार की दो वर्ष की उपलब्धियों पर वर्चुअल प्रदर्शनी का उद्घाटन

आयोजना विभाग

- ❖ जन कल्याण पोर्टल का लोकार्पण

गोपालन विभाग

- ❖ अजमेर दुग्ध डेयरी के अन्तर्गत 8 लाख लीटर दुग्ध का प्रोसेसिंग प्लान्ट एवं 30 मीट्रिक टन मिल्क पाउडर प्लान्ट का लोकार्पण

पशुपालन विभाग

- ❖ 33 जिलों में 679 पशु चिकित्सालय एवं सब सेन्टर का लोकार्पण एवं 10 जिलों में 55 सब सेन्टर का शिलान्यास (कुल लागत 116.50 करोड़ रुपये)

मत्स्य विभाग

- ❖ बीसलपुर (टोंक) में रंगीन मछली एक्वेरियम गैलेरी एण्ड ब्रीडिंग यूनिट का लोकार्पण

सहकारिता विभाग

- ❖ श्रीगंगानगर जिले की 11 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में 1.14 करोड़ रुपये की लागत से 11 आरओ प्लान्ट का लोकार्पण
- ❖ भगवानपुरा, ग्राम सेवा सहकारी समिति (कोटा) में 70.70 लाख रुपये की लागत से ग्रेडिंग, क्लिीनिंग व पैकिंग प्लान्ट एवं गोदाम का शिलान्यास

कृषि विभाग

- ❖ राज्य कृषि प्रबंध संस्थान टोंक के ऑडिटोरियम का लोकार्पण (लागत 16.21 करोड़ रुपये)
- ❖ सेंटर ऑफ एक्सीलेन्स फॉर सीताफल, चित्तौड़गढ़ का लोकार्पण (लागत 5.42 करोड़ रुपये)

तकनीकी शिक्षा (कृषि) विभाग

- ❖ राज्य कृषि विश्वविद्यालयों क्रमशः जोबनेर एवं कोटा के प्रशासनिक भवनों का लोकार्पण
- ❖ कृषि महाविद्यालय, कुम्हेर के भवन एवं कृषि महाविद्यालय, श्रीगंगानगर का लोकार्पण (कार्यों की कुल लागत 44.81 करोड़ रुपये)

कृषि विपणन बोर्ड

- ❖ कृषि उपज मण्डी समिति, कोटा, निवाई एवं उदयपुर में एग्रोट्रेड टावर्स का लोकार्पण
- ❖ कृषि उपज मण्डी समिति, बारां एवं गंगापुरसिटी में आंतरिक सीमेन्ट कंक्रीट सड़कों का शिलान्यास
- ❖ कृषि उपज मण्डी समिति, भीलवाड़ा, जोधपुर (फल-सब्जी), जोधपुर (अनाज) एवं गौण मण्डी प्रांगण, ओसियां में निर्मित आधारभूत संरचनाओं का लोकार्पण (कार्यों पर कुल लागत 42.32 करोड़ रुपये)

चिकित्सा शिक्षा विभाग

- ❖ सवाई मानसिंह चिकित्सालय जयपुर में 50 बेडों का एडवांस मेडिकल आईसीयू , ट्रोमोटोलॉजी एवं अस्थि रोग संस्थान में 16 बेडों का ट्रोमा आईसीयू एवं स्किल डेवलपमेंट लैब का लोकार्पण
- ❖ राज्य में चिकित्सा महाविद्यालयों में 5 स्थानों पर ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का लोकार्पण।
- ❖ आरयूएचएस जयपुर में 1200 बेड के कोविड केयर अस्पताल में लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण।
- ❖ आरएनटी मेडिकल कॉलेज उदयपुर में1100 सीट की क्षमता के ऑडिटोरियम का लोकार्पण
- ❖ राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन(एनएचएम) में कुल 114 चिकित्सा संस्थानों से संबंधित लोकार्पण
- ❖ 16 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट के निर्माण कार्यों का लोकार्पण
- ❖ 17 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 54 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 15 उप स्वास्थ्य केन्द्र एवं एक शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का लोकार्पण। अपग्रेडेशन कार्य 50 बेड से 100 बेड एमसीएच यूनिट का लोकार्पण
- ❖ एएनएम ट्रेनिंग सेंटर छात्रावास भवन, ब्यावर (अजमेर) का विस्तार एवं दो आवास उप जिला चिकित्सालय, केकड़ी (अजमेर) व नेछवा(सीकर) का लोकार्पण।
- ❖ 15 जिला चिकित्सालयों में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट स्थापित करने के कार्य का लोकार्पण।
- ❖ राजकीय जयपुरिया चिकित्सालय जयपुर में ऑक्सीजन मैनिफोल्ड एवं सेन्ट्रल ऑक्सीजन गैस पाइपलाइन तथा जनरल वार्ड को उच्चीकृत कर 20 बेड के नये गहन चिकित्सा इकाई में स्थापित करने के कार्य का लोकार्पण। (कुल लागत 216.28 करोड़ रुपये)

आयुष एवं भारतीय चिकित्सा विभाग

- ❖ 16 जिलों में 38 आयुर्वेद औषधालय के निर्माण कार्यों का लोकार्पण (लागत 9.99 करोड़ रूपये)।
- ❖ दौसा जिले में आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी चांदेरा का शिलान्यास (लागत 15 लाख रूपये)

गृह विभाग एवं सूचना प्रौद्योगिकी व संचार विभाग

- इमरजेंसी रेस्पांस सपोर्ट सिस्टम (ईआरएसएस) 112 के लिए (एसओपी) फेज-1 का लोकार्पण
- 5 अभय कमाण्ड एवं कन्ट्रोल सेंटर (सवाई माधोपुर, झालावाड़, चूरू, चित्तौड़गढ़ एवं राजसमन्द) का लोकार्पण
- राजस्थान पुलिस हेल्पडेस्क ट्विटर हैंडल का शुभारंभ
- व्हाट्सएप हेल्पलाइन, राजस्थान सरकार का शुभारंभ
- महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए साइबर फॉरेंसिक ट्रेनिंग लैब का आरपीए, जयपुर में लोकार्पण

राजस्व एवं बंदोबस्त विभाग

- ई-साइन के साथ नामान्तरण प्रतिलिपि (पी-21) सुविधा का शुभारंभ

वन विभाग

- वृक्षारोपण निगरानी हेतु फॉरेस्ट मैनेजमेंट एण्ड डिसीजन सपोर्ट सिस्टम (एफएमडीएसएस) का ऑनलाइन लोकार्पण

उद्योग विभाग

- वन स्टॉप शॉप का शुभारंभ एवं निवेश पोर्टल का लोकार्पण
- औद्योगिक क्षेत्र तिवरी (जोधपुर) और खोड़ा (अजमेर) का लोकार्पण
- राजकीय कन्या महाविद्यालय, तिवरी (जोधपुर) के भवन का शिलान्यास

ऊर्जा विभाग

- सूरतगढ़ सुपर क्रिटिकल पावर स्टेशन (सातवीं यूनिट) का लोकार्पण 660 मेगावाट
- 220 केवी - 02 ग्रिड सब स्टेशन का लोकार्पण
- 132 केवी - 09 ग्रिड सब स्टेशन का लोकार्पण
- 33 केवी -157 सब स्टेशनों का लोकार्पण
- 220 केवी - 02 ग्रिड सब स्टेशन का शिलान्यास
- 132 केवी - 26 ग्रिड सब स्टेशन का शिलान्यास
- 33 केवी - 45 सब स्टेशन का शिलान्यास

सार्वजनिक निर्माण विभाग

- दूदू-नरैना-सांभर सड़क (एलसी-05) पर आरओबी का लोकार्पण
- भाडौती से बस्सी वाया लालसोट-तूंगा (एस.एच-24) किमी के सुदृढ़ीकरण कार्य का लोकार्पण

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग- देवनारायण योजना

- देवनारायण आवासीय विद्यालय, केकड़ी का लोकार्पण
- बयाना (भरतपुर) में राजकीय महिला कॉलेज छात्रावास भवन का लोकार्पण

शिक्षा विभाग

- 4 जिलों बारां (किशनगंज), बाड़मेर (बालोतरा), जैसलमेर (फतेहगढ़) एवं जोधपुर (बाप एवं शेरगढ़ (साई)) के 5 ब्लॉक में स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूल परिसर में बालिका

छात्रावास निर्माण कार्य का लोकार्पण (लागत 8.68 करोड़ रुपये)।

- ❖ 4 जिलों जोधपुर (बाप,जाम्बा), नागौर (मकराना, बोरावड़), टोंक (पीपलू) एवं सवाईमाधोपुर (गंगापुर, खानपुर बड़ौदा) एवं बामनवास (बरनाला) के 5 ब्लॉक में कस्तूरबा गांधी विद्यालय निर्माण का शिलान्यास (लागत 10.50 करोड़ रुपये)
- ❖ होनहार राजस्थान पुस्तिका का विमोचन।

अल्पसंख्यक विभाग

- ❖ 3 जिलों अलवर (डोगरा), झुंझुनूं (नवलगढ़) एवं बांसवाड़ा के 3 ब्लॉक में राजकीय अल्पसंख्यक बालक छात्रावास एवं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में निर्माण कार्य का लोकार्पण (लागत 4.57 करोड़ रुपये)
- ❖ अजमेर (मसूदा), भरतपुर (कामां), बांसवाड़ा एवं नागौर (मकराना) के 4 ब्लॉक में राजकीय आवासीय एवं कॉन सर्विस सेन्टर में निर्माण कार्य का शिलान्यास (लागत 46.40 करोड़)

श्रम विभाग एवं तकनीकी शिक्षा

- ❖ बाड़मेर पेट्रोलियम रिफाइनरी के लिए दक्ष कार्मिक तैयार करने हेतु आईटीआई जोधपुर में स्ट्रक्चरल वेल्डर एवं बालोतरा में स्ट्रक्चरल फिटर व्यवसाय के लघु अवधि पाठ्यक्रम का शुभारंभ।

नगरीय विकास विभाग

- ❖ प्रताप नगर चौराहा उदयपुर पर फ्लाईओवर कार्य का लोकार्पण
- ❖ न्यास की दक्षिण विस्तार योजना उदयपुर में पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने का कार्य का शिलान्यास राशि रुपये 16.60 करोड रुपये
- ❖ मुख्यमंत्री जन आवास योजना के अंतर्गत जेडीए द्वारा जयपुर में 1448 आवास का शिलान्यास (आनन्द विहार, सूर्य नगर वाटिका, खेड़ा जगन्नाथपुरा)
- ❖ मुख्यमंत्री जन आवास योजना के अंतर्गत राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा जयपुर में 3289 आवासों का शिलान्यास (वाटिका हाउसिंग स्कीम, प्रताप नगर सेक्टर 3 व 28, इंदिरा गांधी नगर सेक्टर-7)
- ❖ राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा शिलान्यास कार्यक्रम
  1- निवाई हाउसिंग स्कीम, टोंक -479 आवास
  2- साउथ एक्सटेंशन स्कीम, उदयपुर-112 आवास
  3- मुख्यमंत्री संबल आवासीय योजना, बडली, फेज - 2, जोधपुर-152 आवास

स्वायत्त शासन विभाग

- ❖ 107.98 करोड रुपये के 13 कार्यों का शिलान्यास
- ❖ जयपुर शहर में ठोस कचरा प्रबंधन हेतु 25 रिफ्यूज्ड कॉम्पेक्टर का लोकार्पण एवं ब्यावर शहर में अमृत योजनान्तर्गत सीवरेज परियोजना का लोकार्पण (कुल लागत 148 करोड रूपये)

पर्यटन विभाग

- ❖ लक्ष्मणगढ़ ईकोलॉजिकल पार्क का शिलान्यास

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग

- ❖ बांसवाड़ा-प्रतापगढ़ पेयजल परियोजना का लोकार्पण (लागत 560 करोड़ रुपये, 334 गांव लाभान्वित)

- ❖ जवाई पाली योजना, फेज-द्वितीय, पार्ट-द्वितीय का लोकार्पण (लागत 154.90 करोड़ रुपये, 108 गांव एवं 58 ढ़ाणी लाभान्वित)
- ❖ 90 एमएलएडी क्षमता के तख्त सागर फिल्टर प्लांट जोधपुर सिटी का लोकार्पण (लागत 48.27 करोड़ रुपये)
- ❖ बूंदी कलस्टर पेयजल परियोजना (विस्तार चंबल भीलवाडा परियोजना से) का लोकार्पण (लागत 80.80 करोड़ रुपये, 34 गांव व 25 ढाणी लाभान्वित)
- ❖ बोरावास पदमपुरा पेयजल परियोजना जिला कोटा का लोकार्पण (लागत 118.04 करोड़ रुपये, 60 गांव व 21 ढाणी लाभान्वित)
- ❖ अटरू शेरगढ़ पेयजल परियोजना का लोकार्पण (लागत 89.69 करोड़ रूपये, 26 गांव, 3 कस्बे व 07 ढाणी लाभान्वित)
- ❖ प्रतापगढ़ शहर की विद्यमान पेयजल सप्लाई योजना के पुनर्गठन के कार्य का लोकार्पण (लागत 94.07 करोड़ रुपये)

जल संसाधन विभाग

- ❖ राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना के अन्तर्गत 7 कार्यों राशि रू.101.18 करोड़ का जीर्णोद्धार कार्य का लोकार्पण
- ❖ राजस्थान जल क्षेत्र पुनः संरचना परियोजना मरूक्षेत्र के अन्तर्गत 8 कार्यों राशि रू. 369.87 करोड़ का जीर्णोद्धार कार्य का लोकार्पण ।
- ❖ गुराडिया लघु सिंचाई परियोजना झालावाड़ का निर्माण कार्य राशि रू. 67.97 करोड़, 1704 हैक्टेयर कमान्ड क्षेत्र का सृजन, हाईड्रोलोजी एवं वाटर मैनेजमेंट इन्स्टीट्यूट बीकानेर के भवन निर्माण राशि रू. 25.00 करोड़ व बीसलपुर बांध पर स्काडा (कम्प्यूटरीकृत स्वचालन) स्थापित करने का कार्य राशि रू. 3.19 करोड़ का लोकार्पण।
- ❖ राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना के अन्तर्गत 12 कार्यों राशि रू. 58.23 करोड़ का जीर्णोद्धार कार्यों का शिलान्यास।
- ❖ राजस्थान जल क्षेत्र पुनः संरचना परियोजना मरुक्षेत्र के अन्तर्गत 9 जिलों यथा बूंदी, कोटा, बांरा, सवाई माधोपुर, अजमेर, टोंक, डूंगरपुर, बांसवाड़ा एवं उदयपुर जिलों में जल संरक्षण के 20 कार्य राशि रू. 184.16 करोड़ के कार्य तथा 7 बांधों यथा बीसलपुर, छापी ,जवाई, सूकली सेलवाडा, माही, गम्भीरी एवं मातृकुण्डिया बांध के 151 करोड़ रुपये के जीर्णोद्धार कार्यों का शिलान्यास।
- ❖ इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के द्वितीय चरण में 5 कार्यों राशि रू. 134.07 करोड़ द्वारा नहरों के नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण कार्यों का शिलान्यास।

पंचायतीराज विभाग

- ❖ 6 जिलों की 8 पंचायत समितियों के नवीन भवनों का लोकार्पण (लागत 19.40 करोड़ रुपये)
- ❖ पूरा काम-पूरा दाम फोल्डर का विमोचन एवं रथ की रवानगी। ●

राज्य सरकार के दो वर्ष

मुख्यमंत्री का मीडिया से संवाद

मीडिया संवाद के प्रमुख बिन्दु

➢ सुशासन

- वर्षों पहले राजस्थान से ही सूचना के अधिकार की पहल हुई थी और राजस्थान देश के उन पहले राज्यों में था, जिसने अपने लोगों को कानून बनाकर सूचना का अधिकार प्रदान किया।
- इस बार भी सूचना के अधिकार को और अधिक सशक्त बनाने के लिये जनसूचना पोर्टल बनाया है। जिसके जरिए आमजन को सरकारी विभागों, प्राधिकरणों, निगमों से सम्बन्धित सूचनाएं आसान तरीके से उपलब्ध हो रही हैं।
- पारदर्शिता बढ़ाने के लिए राज्य सरकार की योजनाओं के सभी लाभार्थियों की सूची सार्वजनिक तौर पर जनसूचना पोर्टल पर उपलब्ध करवाई है।
- सुशासन के लिए जनकल्याण पोर्टल (पब्लिक वेलफेयर पोर्टल) लांच किया है। इसमें राज्य सरकार द्वारा जनहित में चलाई जा रही सभी योजनाओं, कार्यक्रमों, नीतियों, और दस्तावेजों को एक ही स्थान पर उपलब्ध करवाया जा रहा है।
- सूचना के अधिकार के तहत सूचना उपलब्ध करवाने के लिए आरटीआई पोर्टल शुरू किया गया है। अब तक करीब 42 हजार आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें से 36 हजार का निस्तारण कर दिया गया है।
- कोरोना के इस समय में आमजन मुख्यमंत्री तक सीधी अपनी बात पहुंचा सके, इसके लिए writetocm@rajasthan.gov.in ई-मेल सुविधा शुरू की गई है।

➢ फसली ऋण माफी

- 17 दिसम्बर 2018 को श्री अशोक गहलोत द्वारा मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद 19 दिसम्बर, 2018 को ही किसानों के ऋण माफ करने का वादा पूरा करते हुए सहकारी बैंकों के 30 नवम्बर, 2018 तक के सभी बकाया फसली ऋण माफ करने के आदेश दिए गए। अब तक कुल 20 लाख 55 हजार किसानों का कर्ज माफ किए गए हैं। इसमें से करीब 9 हजार किसानों के 2 लाख रूपये से ज्यादा के कर्ज माफ हुए हैं।
- विधानसभा चुनाव 2018 से पहले 50 हजार रुपये तक की ऋण माफी की घोषणा की थी, लेकिन पर्याप्त वित्तीय प्रावधान नहीं थे। किसानों के हित में वर्तमान राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त व्यय भी वहन किया गया और सितम्बर 2018 से पूर्व के 6 हजार करोड़ रूपये के कर्ज भी माफ किए गए।

- जिन किसानों के लोन एनपीए हो चुके थे और उनकी जमीन बैंक ने गिरवी रख ली थी, ऐसे 29 हजार किसानों के 2 लाख रुपये तक के अवधिपार लोन (एनपीए) चुका दिए गए हैं और 1.24 लाख बीघा भूमि गिरवी से मुक्त हो चुकी है।
- इस तरह कुल 14 हजार करोड़ रुपये के किसानों के कर्ज राज्य सरकार ने माफ किए हैं।
- जिन किसानों के कर्ज माफ हुए हैं, उन किसानों को दोबारा ऋण मिल सके, इसकी व्यवस्था भी राज्य सरकार ने की है।

➢ नई MSME पॉलिसी

- राज्य में एमएसएमई उद्योगों के विकास के लिये एमएसएमई एक्ट लाया गया है। इससे उद्यमों को तीन साल तक राज्य के विभिन्न विभागों की स्वीकृतियों एवं निरीक्षणों से मुक्त किया गया है।
- ऐसा अधिनियम लागू करने वाला राजस्थान पहला राज्य है।
- निवेशकों को आवश्यक अनुमतियां एक ही स्थान पर देने के लिए ''वन स्टॉप शॉप'' प्रणाली की स्थापना की गई है।
- ''वन स्टॉप शॉप'' प्रणाली हेतु ''राज निवेश'' पोर्टल शुरू किया गया है। एक ही छत के नीचे सभी सुविधाएं सुलभ होने से राजस्थान निवेशकों की पहली पसंद बन सकेगा।
- इससे राज्य में उद्योगों का विकास होगा और रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे।

➢ क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटियों पर नियंत्रण

- लोगों की खून-पसीने की कमाई हड़पने वाली क्रेडिट को-

ऑपरेटिव सोसायटियों पर नियंत्रण के लिए कानूनी प्रावधानों का अध्ययन कर उनमें बदलाव किया जाएगा। इससे निवेशकों को न्याय और अपराधियों को सजा मिल सकेगी।

- प्रदेश में ऐसा सिस्टम विकसित किया जायेगा, जिससे अनरेगुलेटेड (अनियमित) जमा स्कीम्स को हतोत्साहित किया जा सकेगा, ताकि कोई भी अवैध सोसायटी अधिक ब्याज का लालच देकर लोगों से पैसा न हड़प सके।

- राज्य सरकार के प्रयासों के कारण केन्द्र ने मल्टी स्टेट क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटियों के विरुद्ध दर्ज शिकायतों में इस्तगासे पेश करने के लिए राज्य सरकार के रजिस्ट्रार, सहकारी समितियों को अधिकृत कर दिया है। इससे केन्द्रीय रजिस्ट्रार के यहां पंजीकृत मल्टी स्टेट सोसायटियों पर राज्य में भी कार्यवाही की जा सकेगी।
- कानूनी प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए डेजीगनेटेड कोर्ट का गठन किया गया है। इन अदालतों में राज्य सरकार द्वारा दायर किए जाने वाले प्रकरणों में पैरवी करने के लिए लोक अभियोजक/राजकीय अभिभाषकों को निर्देशित किया गया है।
- राजस्थान पुलिस द्वारा 1500 से अधिक मुकदमें दर्ज कर दोषियों को सजा दिलवाने की कार्यवाही प्रारंभ की गई है।
- राज सहकार पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की सुविधा विकसित की गई है। अब तक 75 हजार से अधिक शिकायतें प्राप्त हो चुकी हैं।

➢ बेहतर कोरोना प्रबंधन

- राजस्थान के कोरोना प्रबंधन की मिसाल पूरे देश में दी जा रही है। मुख्यमंत्री द्वारा 200 से ज्यादा वीसी के जरिए नियमित समीक्षा बैठक की गई और समाज के हर तबके को साथ लिया गया ।
- राजस्थान ऐसा राज्य है जहां कोविड जांच शत-प्रतिशत पूर्ण विश्वसनीय आरटीपीसीआर पद्धति से की जा रही है।
- कोरोना की जांच से लेकर इलाज तक निःशुल्क उपलब्ध करवाया जा रहा है।
- लॉकडाउन के समय प्रवासियों एवं श्रमिकों के आवागमन को सुगम बनाने के लिए पूरी व्यवस्था की गई।

➢ कानून-व्यवस्था

- थाने पर एफ.आई.आर. दर्ज नहीं होने की स्थिति में पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एफ.आई.आर. दर्ज करवाने की व्यवस्था की गई है और पुलिस थाने में एफ.आई.आर. दर्ज न करने वाले थानाधिकारी पर कार्यवाही सुनिश्चित होगी।
- प्रदेश की कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने और प्रत्येक पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए राज्य में पुलिस थानों में एफ.आई.आर. दर्ज करना अनिवार्य किया गया है। इससे भले ही राज्य में अपराध दर्ज होने के आंकड़े बढ़े हों लेकिन आमजन का पुलिस पर भरोसा बढ़ा है।
- पुलिस सहायता तेजी से सुलभ हो सके इसलिए 112 ERSS SYSTEM शुरू किया गया है। साथ ही पुलिस सहायता के लिए ट्विटर हैंडल राजस्थान पुलिस हेल्पडेस्क शुरू किया गया है।
- हर फरियादी को सम्मान के साथ अपनी बात कहने का मौका मिल सके, इसलिए पुलिस थानों में स्वागत कक्ष बनाए जा रहे हैं।
- मॉब लिंचिंग और ऑनर किलिंग को रोकने के लिए कानून बनाया गया है।

➢ अन्य महत्त्वपूर्ण निर्णय

- आमजन के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए 18 दिसम्बर,

2019 से निरोगी राजस्थान अभियान का शुभारम्भ किया गया।

- इस अभियान को सफल बनाने के लिए करीब 93 हजार स्वास्थ्य मित्रों का चयन किया गया है।
- 2 साल में 90 नये कॉलेज खोले गए हैं। साथ ही 201 सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले गए हैं।
- राजस्थान पहला राज्य है जहां प्रत्येक शनिवार को ''नो बैग डे'' शुरू किया गया है।
- 2 हजार करोड़ रुपये का कृषक कल्याण कोष का गठन किया गया है।
- पदक विजेता खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न आधार पर डीएसपी रैंक तक की नौकरियां दी गई हैं।
- ग्रामीण क्षेत्र में अपराधों की रोकथाम व अन्य कार्यों में पुलिस का सहयोग करने के उद्देश्य से राजस्थान पुलिस द्वारा प्रत्येक थानान्तर्गत स्थित राजस्व ग्राम में 33,847 ग्राम रक्षक सूचीबद्ध किये जा चुके हैं।
- राज्य में फ्री इंटरनेट हेतु दिसंबर, 2018 से अब तक लगभग 7000 वाईफाई हॉटस्पॉट उपलब्ध करवाये जा चुके हैं। अब तक कुल 9513 वाईफाई हॉटस्पॉट उपलब्ध करवाये जा चुके हैं।
- MSME को 3 वर्ष तक निरीक्षण/अनुमति से मुक्ति और उद्योगों की सुगमता के लिए वन स्टॉप शॉप।
- मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना के तहत 2 लाख 45 हजार 270 बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ते के तौर पर करीब 741 करोड़ रूपये का भुगतान किया जा चुका है।
- चिकित्सा व्यवस्था को और अधिक मजबूत करने के लिए 15 नये मेडिकल कॉलेज खोलने की स्वीकृति प्रदान की गई है। अब प्रदेश के 33 में से 30 जिलों में मेडिकल कॉलेज आने वाले वर्षों में स्थापित हो जाएंगे। शेष तीन जिले जालौर, प्रतापगढ़ और राजसमंद में सरकारी कॉलेज खोलने के लिए केन्द्र सरकार से मंजूरी मांगी गई है।
- इंदिरा रसोई योजना से प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में जरुरतमंदों को 8 रुपये में भोजन की व्यवस्था की गई है। अब तक 1 करोड़ 12 लाख भोजन की थाली उपलब्ध कराई गई

है। राज्य सरकार द्वारा 12 रुपये का अनुदान प्रति थाली पर दिया जा रहा है।

➢ पत्रकार कल्याण

- राजस्थान वरिष्ठ अधिस्वीकृत पत्रकार सम्मान योजना आरम्भ की गई है। 60 साल से अधिक उम्र के पात्र अधिस्वीकृत पत्रकारों की सम्मान राशि (पेंशन) 5 हजार से बढ़ाकर 10 हजार रुपये की गई है।
- पूर्व में पत्रकार और उसके परिवार को बीमारी के इलाज के लिए दी जा रही आर्थिक सहायता केवल 6 गम्भीर बीमारियों के लिए ही थी। राज्य सरकार ने अब 24 दिसम्बर, 2020 को जारी अधिसूचना में वर्णित कैंसर, कुष्ठ रोग, वॉल्व रिप्लेसमेंट, एन्जियोप्लास्टी सहित सभी गम्भीर बीमारियों के लिए सहायता देने की व्यवस्था की है।
- इलाज के लिए वर्तमान में देय एक लाख रुपये की आर्थिक सहायता राशि में वृद्धि कर इसे 2 लाख रुपये तक बढ़ा दिया है।
- अधिस्वीकृत पत्रकारों को जारी मेडिकल डायरी सुविधा अब गैर अधिस्वीकृत सवैतनिक पत्रकारों को भी देय कर दी गई है।

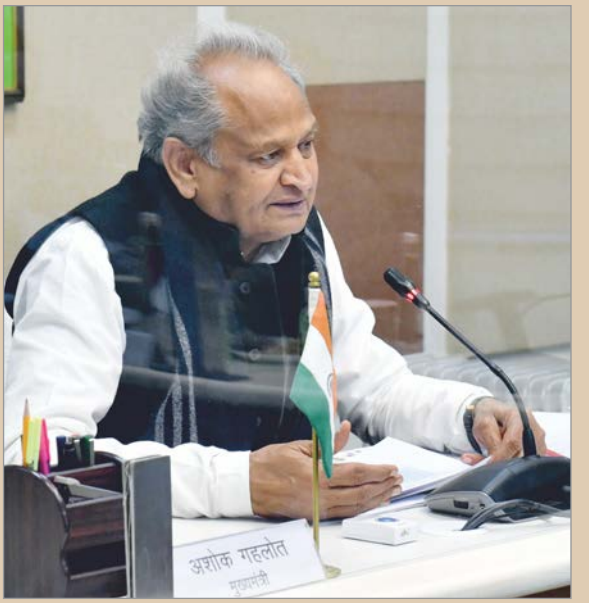

कलक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस

गुड गवर्नेंस में लापरवाही बर्दाश्त नहीं

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कहा है कि संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेह सुशासन राज्य सरकार का मूल मंत्र है। हर अधिकारी और कर्मचारी इस सूत्र वाक्य को आत्मसात् कर जनता से जुड़े कामों में किसी तरह की कमी नहीं रखें। उन्होंने निर्देश दिए कि कार्मिक विभाग में एक अलग प्रकोष्ठ बनाया जाए, जिसमें ऐसे अधिकारी-कर्मचारी जो काम में लापरवाह हैं तथा जिनके विरूद्ध भ्रष्टाचार की शिकायतें हो या आदतन रूप से अनुशासनहीनता करते हों, उनके प्रकरण भिजवाए जाएं। राज्य सरकार उन प्रकरणों पर विचार कर दोषी कार्मिक के विरूद्ध सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करेगी।

श्री गहलोत 13 जनवरी को मुख्यमंत्री निवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जिला कलक्टर्स के साथ मुख्यमंत्री सहायता कोष, सिलिकोसिस योजना, राजस्व मामलों तथा मुख्यमंत्री कार्यालय एवं सम्पर्क पोर्टल पर प्राप्त प्रकरणों सहित आमजन से जुड़े अन्य विषयों पर समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि लोगों के वाजिब काम समय पर पूरे करना सरकार का दायित्व है। अगर किसी व्यक्ति का काम समय पर नहीं होता है, तो उस व्यक्ति को होने वाली पीड़ा के लिए सम्बन्धित अधिकारी और कर्मचारी जिम्मेदार होंगे। उन्होंने कहा कि गुड गवर्नेंस की दिशा में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

आमजन को राहत के लिए प्रशासन गांवों के संग अभियान की तैयारी शुरू करें

मुख्यमंत्री ने कहा कि आम तौर पर देखा जाता है कि लोगों को छोटे-छोटे राजस्व वादों के निस्तारण के लिए भी लम्बे समय तक चक्कर काटने पड़ते हैं। नामान्तरण, सीमा ज्ञान, पत्थरगढ़ी, भू-संपरिवर्तन सहित अन्य राजस्व सम्बंधी मामलों का समय पर निस्तारण नहीं होने से आमजन अपने अधिकार से वंचित रहता है। उन्होंने कहा कि जिला कलक्टर, एसडीएम, तहसीलदार, पटवारी एवं अन्य संबंधित अधिकारी और कार्मिक इन कार्यों को पूरी संवेदनशीलता के साथ समय सीमा में पूरा करें। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आमजन के ऐसे जरूरी कामों को मौके पर ही करने के लिए जल्द ही प्रशासन गांवों के संग अभियान चलाएगी। इसके लिए संबंधित विभाग अभी से तैयारी शुरू कर दें। उन्होंने कहा कि काश्तकारों को खेत का रास्ता देने के लिए हमारी पिछली सरकार के समय कानून में संशोधन किया गया था। लेकिन दुर्भाग्य से उस मंशा के अनुरूप काम नहीं हुआ। उन्होंने जिला कलक्टरों को निर्देश दिए कि काश्तकारों को खेतों तक रास्ता देने के लिए अभियान चलाएं।

भू-अभिलेखों के डिजिटाइजेशन को तरजीह दें

श्री गहलोत ने भू-अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण तथा तहसीलों को ऑनलाइन करने के काम को प्राथमिकता से पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बाड़मेर के पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर भू-संपरिवर्तन की प्रक्रिया को भी ऑनलाइन किया जाए। ऑनलाइन माध्यम से जमाबन्दी, गिरदावरी एवं नामान्तरकरण की प्रतिलिपि जैसी सुविधाओं से आमजन को लाभान्वित किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक कलक्टर व्यक्तिगत रूप से ध्यान देकर अपवादित खातों एवं लम्बित तरमीमों का निस्तारण शीघ्र कराएं। साथ ही, भू-अभिलेख के कम्प्यूटरीकरण का काम त्रुटिरहित हो, ताकि भविष्य में राजस्व रिकॉर्ड से सम्बन्धित विवाद पैदा न हों। मुख्यमंत्री ने गैर खातेदारी से खातेदार अधिकार प्रदान करने के लम्बित मामलों में भी प्रभावी कार्यवाही करने तथा नियमों में जरूरी बदलाव करने के निर्देश दिए।

पीड़ितों को तत्काल मिले सहायता

श्री गहलोत ने कहा कि दुर्घटना के प्रकरणों में मुख्यमंत्री सहायता कोष से सहायता देने में देरी होने से पीड़ित को तत्काल सहायता का औचित्य ही समाप्त हो जाता है। उन्होंने निर्देश दिए कि जिला कलक्टर इन मामलों में पूरी गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ पीड़ित परिवार को तुरन्त प्रभाव से सहायता उपलब्ध कराएं। उन्होंने सिलिकोसिस योजना के तहत प्रमाणीकरण के लम्बित प्रकरणों में त्वरित कार्यवाही करने के निर्देश भी दिए।

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में प्रदेश को बनाएं अव्वल

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आवास निर्माण में तेजी लाकर राजस्थान को इस योजना में देश में अव्वल बनाएं। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि योजना के

सफल क्रियान्वयन से राजस्थान देश में चौथे स्थान पर है। फिर भी हमें इसी से संतुष्ट नहीं होना है और लगातार मॉनिटरिंग से अव्वल स्थान हासिल करना है।

देरी के तीन मामलों में जिम्मेदारी तय करने के निर्देश

श्री गहलोत ने कहा कि मुख्यमंत्री कार्यालय एवं सम्पर्क पोर्टल पर आने वाली आमजन की समस्याओं का पूरी गंभीरता के साथ समय पर समाधान हो। उन्होंने जयपुर जिले से सेवानिवृत्त एक पटवारी के पेंशन प्रकरण में देरी, जालौर में गार्गी पुरस्कार के चैक का समय पर वितरण नहीं होने तथा प्रतापगढ़ में म्यूटेशन के प्रकरण में अनावश्यक देरी पर जिला कलक्टरों को संबंधित अधिकारी एवं कार्मिक की जिम्मेदारी तय करने के निर्देश दिए।

वैक्सीनेशन में भी रखें प्रदेश को अव्वल

मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस तरह सभी जिला कलक्टरों ने कोरोना का कुशल प्रबंधन किया, उसी भावना के साथ काम कर राजस्थान को वैक्सीनेशन के काम में हमें अव्वल रखना है। उन्होंने कहा कि आमजन में यह विश्वास बनाए रखने की जरूरत है कि वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित और लोगों की जान बचाने के लिए है।

राजस्व मंत्री श्री हरीश चौधरी ने कहा कि राजस्व रिकॉर्ड में इंद्राज और मौके पर रास्ते की स्थिति को लेकर कई बार विवाद की स्थिति बनी रहती है। मनरेगा के तहत सहमति से निकाले जाने वाले रास्तों, कदमी रास्तों आदि का राजस्व रिकॉर्ड में इंद्राज सुनिश्चित हो ताकि भविष्य में विवाद न रहे। उन्होंने राजस्व संबंधी कुछ नियमों में सरलीकरण का भी सुझाव दिया।

शिक्षा राज्य मंत्री श्री गोविन्द सिंह डोटासरा ने कहा कि सतर्कता समितियों को अधिक प्रभावी बनाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि इन समितियों की नियमित बैठकें हों तथा उनमें लिए जा रहे प्रकरणों की जिला कलक्टर के स्तर पर नियमित समीक्षा की जाए।

महिला एवं बाल विकास राज्यमंत्री श्रीमती ममता भूपेश ने कहा कि प्रशासन आमजन से जुड़े मामलों में और अधिक संवेदनशीलता से काम करें। कई बार लोग जागरूक नहीं होने के कारण योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते हैं। अधिकारी आगे बढ़कर राहत पहुंचाएं।

मुख्य सचिव श्री निरंजन आर्य ने कहा कि मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप जिला कलक्टर संवेदनशीलता, जवाबदेही, पारदर्शिता को निचले स्तर तक कार्यशैली का अंग बनाएं।

इस अवसर पर एसीएस ग्रामीण विकास श्री रोहित कुमार सिंह, प्रमुख सचिव वित्त श्री अखिल अरोरा, प्रमुख सचिव राजस्व श्री आनंद कुमार, प्रमुख सचिव सामाजिक न्याय श्रीमती गायत्री राठौड़ सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। राज्य मंत्री परिषद् के अन्य सदस्य, विभिन्न विभागों के प्रमुख सचिव एवं शासन सचिव, संभागीय आयुक्त एवं अन्य अधिकारी भी वीसी के माध्यम से जुड़े। ●

वैदिक ज्ञान को जन-जन तक पहुंचाएं

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कहा कि वेद सुशासन के सिद्धांतों का खजाना हैं, इन सिद्धांतों को अपनाकर लोक कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना को मूर्तरूप दिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार वेदों में निहित ज्ञान को जन-जन तक पहुंचाने के लिए वैदिक शिक्षा के संरक्षण तथा इसके अध्यापन के काम को और आगे बढ़ाएगी। उन्होंने कहा कि ऋषि-मुनियों के चिंतन तथा हमारे पुरातन ज्ञान-विज्ञान के अमूल्य भंडार वैदिक शिक्षा तथा देव-वाणी संस्कृत के प्रसार में सरकार कोई कमी नहीं छोड़ेगी।

श्री गहलोत 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री निवास पर 'लोक कल्याणकारी राज्य एवं सुशासन हेतु वैदिक विमर्श' विषय पर वर्चुअल रूप से आयोजित राष्ट्रीय वेद सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर वैदिक हैरिटेज एवं पाण्डुलिपि शोध संस्थान, राजस्थान संस्कृत अकादमी के पोर्टल तथा 'पानी बचाओ, बेटी बचाओ, सबको पढ़ाओ, पर्यावरण बचाओ' के संदेश पर आधारित पोस्टर का लोकार्पण किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सदियों पहले हमारे महान् विद्वानों ने वेदों के रूप में जो बेशकीमती खजाना हमें सौंपा है, उसमें पर्यावरण संरक्षण, कर्तव्य, शासन के सिद्धांत, आदर्श प्रजा, प्रजातांत्रिक मूल्य सहित सभी विषय समाहित हैं। जितनी गहराई में हम वेदों का अध्ययन करते हैं, उतना ही सुशासन देने का हमारा संकल्प और अधिक मजबूत होता है।

श्री गहलोत ने इस मौके पर स्वामी विवेकानंद का पुण्य स्मरण करते हुए कहा कि उन्होंने दुनिया में भारतीय वैदिक संस्कृति के महत्त्व को स्थापित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। मानवता तथा विश्व शांति के लिए दिया गया उनका संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है। वैदिक संस्कृति में बताए गए शांति, सद्भाव, समरसता तथा विश्व-बंधुत्व जैसे मूल्यों को अपनाकर युवा पीढ़ी सामाजिक, आर्थिक और वैचारिक रूप से सशक्त बन सकती है। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के समय विवेकानंद जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस घोषित किया गया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में आयुर्वेद एवं संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। अब वैदिक शिक्षा एवं संस्कार बोर्ड के काम को आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वैदिक साहित्य के क्षेत्र में शोध करने वाले विद्यार्थियों को राज्य सरकार प्रोत्साहन देगी। उन्होंने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से वैदिक ज्ञान का तेजी से प्रसार किया जा सकता है।

कला एवं संस्कृति मंत्री डॉ. बी.डी. कल्ला ने कहा कि राजस्थान में गुरू-शिष्य परंपरा पर आधारित 25 वेद विद्यालय तथा संस्कृत शिक्षा निदेशालय का होना यह दर्शाता है कि राज्य सरकार वैदिक परंपराओं के संरक्षण की दिशा में सकारात्मक सोच के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि वैदिक वांङ्मय में कहा गया है कि सर्वहित में ही स्वहित निहित है। यही भावना शासन का मूल मंत्र होनी चाहिए।

मुख्य सचिव श्री निरंजन आर्य ने कहा कि हमारी वर्तमान लोकतांत्रिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था की मूल अवधारणा वैदिक ज्ञान से प्रेरित है। सामाजिक जीवन के संचालन की जो विधि वेदों में बताई गई है, वही सुशासन का सार है। सांस्कृतिक और नैतिक मूल्यों के पतन को रोकने के लिए वैदिक विमर्श उपयोगी हो सकता है।

गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार के कुलपति प्रो.रूपकिशोर शास्त्री ने कहा कि सुशासन और स्वराज्य की अवधारणा का केन्द्र बिन्दु वैदिक साहित्य में मिलता है। उन्होंने कहा कि राजस्थान

डबल स्टैक कंटेनर रेलगाड़ियों का शुभारंभ

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मुख्य आतिथ्य में वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के मदार (किशनगढ़) -रेवाड़ी (हरियाणा) खंड का लोकार्पण एवं इस कॉरिडोर के न्यू अटेली (हरियाणा) और न्यू किशनगढ़ (अजमेर) से 1.5 किलोमीटर लंबी डबल स्टैक कंटेनर रेलगाड़ियों का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर राजस्थान के राज्यपाल श्री कलराज मिश्र, हरियाणा के राज्यपाल श्री सत्यदेव नारायण आर्य, मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत, हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर एवं रेलमंत्री श्री पीयूष गोयल सहित अन्य गणमान्य अतिथि मौजूद रहे।

वर्चुअल रूप से आयोजित समारोह में संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कहा कि भारतीय रेल का 170 साल का इतिहास है। आजादी के समय देश में रेलवे और इससे जुड़े क्षेत्रों में निर्माण कार्य नहीं होता था और भारत दूसरे देशों पर निर्भर था। देश के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहर लाल नेहरू ने दूर दृष्टि रखते हुए रेलवे के विकास के लिए कई कल-कारखाने लगवाए, जिससे भारत रेलवे के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सका। रेलवे का इस्तेमाल सवारियों के साथ-साथ माल ढुलाई के लिए बेहतर तरीके से किया जा सके, इसके लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह के समय वर्ष 2006 में डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (डीएफसीसीआईएल) की स्थापना की गई। डीएफसीसीआईएल द्वारा दिल्ली से मुंबई के बीच वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और पंजाब से पश्चिम बंगाल के बीच ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का एक बड़ा हिस्सा राजस्थान से गुजरता है।

श्री गहलोत ने प्रधानमंत्री से अनुरोध किया कि देश का पहला कंट्री स्पेसिफिक जापानीज इनवेस्टमेंट जोन, नीमराणा अलवर जिले में है एवं अलवर-भिवाड़ी क्षेत्र में लगभग 6521 औद्योगिक इकाइयां स्थापित हैं। जिस तरह न्यू धारुहेड़ा, हरियाणा में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (डीएफसी) रेलवे स्टेशन बनाया गया है, उसी तरह डीएफसी अलाइनमेंट पर सलारपुर औद्योगिक क्षेत्र, भिवाड़ी के पास एक और डीएफसी स्टेशन स्थापित किया जाए। इससे यहां माल ढुलाई का काम अच्छे से हो सकेगा और यहां की इकाइयों को भी लाभ मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने पश्चिमी राजस्थान की जनता की जैसलमेर-बाड़मेर को कांडला व मुंद्रा से जोड़ने के लिए लंबे समय से चली आ रही नई रेल परियोजना की मांग को प्रधानमंत्री के समक्ष रखा। **श्री गहलोत ने कहा कि जैसलमेर और बाड़मेर में तेल और गैस का उत्पादन हो रहा है। देश में कच्चे तेल के उत्पादन का लगभग 20 फीसदी कच्चा तेल यहां निकलता है। बाड़मेर में रिफायनरी का निर्माण कार्य भी शुरू हो गया है। अगर जैसलमेर-बाड़मेर को कांडला और मुंद्रा बंदरगाह से जोड़ दिया जाता है तो यह राजस्थान के हित में एक बड़ी सौगात होगी।**

श्री गहलोत ने राजस्थान में रेलवे द्वारा स्वीकृत किए गए प्रोजेक्ट जिनका काम पूर्ववर्ती सरकार के समय बंद हो गया था, उनको भी पुनः शुरू करने की मांग की। श्री गहलोत ने सरमथुरा-गंगापुर वाया करौली रेलवे लाइन, चौथ का बरवाड़ा से अजमेर वाया टोंक रेलवे लाइन, आदिवासी क्षेत्र से निकलने वाली रतलाम से डूंगरपुर वाया बांसवाड़ा रेलवे लाइन, पुष्कर-मेड़ता रोड रेलवे लाइन, मैमू रेल कोच फैक्ट्री भीलवाड़ा के काम को फिर शुरू करने और लोहारू-सीकर-रींगस रेल लाइन पर आमान परिवर्तन के पश्चात् बने ब्रॉडगेज मार्ग को देश के महानगरों और बड़े शहरों से जोड़ने की मांग भी रखी। ●

वह भूमि है, जहां वैदिक ज्ञान तथा परंपराओं के संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य हुआ है और इसे आगे बढ़ाया जा रहा है।

महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक के पूर्व प्रोफेसर बलवीर आचार्य ने कहा कि वेदों में राज्य संस्था का विकास, शासनाध्यक्ष के निर्वाचन, उसकी योग्यता तथा दायित्वों के निर्वहन की संपूर्ण व्याख्या की गई है। वसुधैव कुटुंबकम् की भावना वैदिक ज्ञान पर ही आधारित है। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर के संस्कृत विभागाध्यक्ष श्री नीरज शर्मा ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। कला, साहित्य एवं संस्कृति विभाग की सचिव श्रीमती मुग्धा सिन्हा ने कहा कि वेदों का भारतीय जन मानस पर अमिट प्रभाव रहा है। वेदों में नैतिकता के साथ संयमित एवं संतुलित जीवन जीने के सूत्र दिए गए हैं, जो हम सभी के लिए उपयोगी हैं।

राजस्थान संस्कृत अकादमी के प्रशासक डॉ. समित शर्मा ने धन्यवाद ज्ञापित किया। इस अवसर पर श्री कालाजी वैदिक विश्वविद्यालय की कुलपति डॉ. लक्ष्मी शर्मा, राजस्थान संस्कृत अकादमी के निदेशक श्री संजय झाला सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। गोविन्द गुरू जनजातीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. आईवी त्रिवेदी भी वीसी के माध्यम से जुड़े। ●

कोविड स्वास्थ्य समस्याओं का विशेष अध्ययन होगा: मुख्यमंत्री

फेफड़ों, दिमाग में संक्रमण, याददाश्त खोने, हृदय रोग जैसे लक्षण चिंता का विषय

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार कोरोना महामारी के रोगियों के ठीक होने के बाद भी स्वास्थ्य पर होने वाले दुष्प्रभावों का गहन अध्ययन एवं विश्लेषण करवाएगी। उन्होंने प्रदेशभर के विशेषज्ञ डॉक्टरों से कहा कि कोरोना वायरस के मानव शरीर पर होने वाले दुष्प्रभावों को रोकने के लिए प्रभावी प्रोटोकॉल तैयार करने के लिए विशेष टीमें बनाकर अनुसंधान किया जाए। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को 'पोस्ट-कोविड' स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में जागरूकता के लिए विशेष अभियान चलाने के लिए निर्देशित किया।

श्री गहलोत ने 2 जनवरी को मुख्यमंत्री निवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न विभागों के अधिकारियों तथा विशेषज्ञ चिकित्सकों के समूह के साथ प्रदेश में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि कोविड-19 से ठीक हुए रोगियों में फेफड़ों और दिमाग में संक्रमण, याददाश्त खोने, हृदय रोग तथा डायबिटीज बढ़ने जैसे कई तरह के शारीरिक एवं मानसिक प्रभाव सामने आ रहे हैं। यह चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि ऐसे रोगियों को भविष्य में स्वास्थ्य सम्बन्धी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े, इसके लिए पोस्ट कोविड उपचार पर विशेष जोर दिया जाए और इसके लिए कारगर गाइडलाइन तैयार की जाए।

आमजन के बीच पोस्ट कोविड समस्याओं का व्यापक प्रचार करें

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने कोविड के दुष्प्रभावों से लोगों को बचाने के लिए पोस्ट कोविड क्लिनिक की व्यवस्था की है, लेकिन जागरूकता के अभाव में लोग इनका पूरा लाभ नहीं ले पा रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी कोरोना रोगियों तक यह जानकारी पहुंचाई जाए कि वे ठीक होने के बाद भी कोई लक्षण दिखने पर समुचित इलाज के लिए डॉक्टर से संपर्क करें। कोविड के विभिन्न दुष्प्रभावों और उनके इलाज के लिए आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करने के साथ ही व्यापक प्रचार-प्रसार कर आम लोगों को जागरूक किया जाए, ताकि समय रहते जरूरी उपचार दिया जा सके।

रात्रिकालीन कर्फ्यू जैसे प्रतिबंध कुछ दिन और जारी रहेंगे

श्री गहलोत ने कहा कि रात्रिकालीन कर्फ्यू जैसे निर्णयों तथा बेहतरीन प्रबंधन के चलते प्रदेश में कोरोना की स्थिति अब काफी हद तक नियंत्रण में है। मृत्यु दर लगातार कम हो रही है, रिकवरी रेट बढ़ रही है। साथ ही, पॉजिटिव केसों की संख्या काफी कम हो गई है। उन्होंने इन निर्णयों के सकारात्मक परिणामों को दृष्टिगत रखते हुए रात्रिकालीन कर्फ्यू सहित विभिन्न गतिविधियों पर प्रतिबंध फिलहाल आगामी कुछ और दिनों तक जारी रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि थोडे समय और एहतियात

रखने से कोरोना संक्रमण को न्यूनतम स्तर तक लाने में मदद मिलेगी।

प्रदेश में वैक्सीनेशन के ड्राई रन की सफलता सुखद

मुख्यमंत्री ने कोविड के टीकाकरण के लिए प्रदेश में किए गए 'ड्राई रन' की सफलता पर प्रसन्नता जाहिर की। उन्होंने कहा कि कोविड रोगियों की संख्या कम होने के साथ ही वैक्सीनेशन की दिशा में हमारे तेजी से बढ़ते कदम सुखद संकेत हैं। हमारा प्रयास है कि प्रदेश में जल्द से जल्द वैक्सीनेशन शुरू हो और अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिले। उन्होंने वैक्सीन के परिवहन के साथ-साथ प्रशिक्षण, लोगों को इसे लगाने के लिए प्रोत्साहित करने तथा इसके संबंध में भ्रांतियों को दूर करने पर विशेष जोर दिया।

स्वास्थ्य मित्रों से सहयोग लेंगे डॉक्टर

श्री गहलोत ने कहा कि विभिन्न बीमारियों से पीड़ित रोगियों को सरकारी अस्पतालों में इलाज मिलने में सहायता के लिए राज्य सरकार ने स्वास्थ्य मित्रों का चयन किया है। ये लोग समाज सेवा के रूप में जरूरतमंद मरीजों की मदद करेंगे। उन्होंने कहा कि इसके लिए जिला अस्पतालों से लेकर स्वास्थ्य उपकेन्द्रों तक डॉक्टरों तथा स्वास्थ्य अधिकारियों को स्वास्थ्य मित्रों से सहयोग करने के लिए निर्देशित किया जाए।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ. रघु शर्मा ने बताया कि प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों में कोरोना पॉजिटिव रोगियों की संख्या कम होने के कारण ईएसआई अस्पताल को नॉन-कोविड करने तथा 100 से अधिक बेड वाले अस्पतालों में कोविड के लिए आरक्षित बेड की संख्या 40 प्रतिशत से घटाकर 30 प्रतिशत एवं 100 से कम बेड वाले अस्पतालों में 30 से घटाकर 20 प्रतिशत करने के संबंध में निर्देश दिए गए हैं।

प्रदेश के सभी जिलों में कोरोना पॉजिटिव रोगियों की संख्या कम हो रही है। कोविड वैक्सीनेशन के लिए तैयारियां तीव्र गति से चल रही है। विभिन्न स्तर पर वैक्सीन अभियान से जुड़े स्वास्थ्य कर्मियों तथा अन्य कार्मिकों को समुचित प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आमजन को वैक्सीन लगाने की तैयारी के तहत इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जनप्रतिनिधियों, संस्थाओं तथा संगठनों से सहयोग का पूरा खाका भी तैयार कर लिया गया है।

बैठक में उपस्थित विशेषज्ञ डॉक्टरों ने रात्रिकालीन कर्फ्यू तथा सार्वजनिक स्थलों पर भीड़-भाड़ को रोकने जैसे प्रतिबंधों को फिलहाल नहीं हटाने का सुझाव दिया। उनका मानना था कि सर्द मौसम और तीव्र गति से संक्रमण फैलाने वाले कोरोना वायरस के 'नए स्ट्रेन' की उपस्थिति के दृष्टिगत प्रतिबंध जारी रहने चाहिए। डॉक्टरों ने आगामी कुछ दिनों में शुरू होने वाले टीकाकरण अभियान पर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने बताया कि जो वैक्सीन उपलब्ध कराई जाएगी वह काफी प्रभावी है। लेकिन लोगों को कोविड-19 की वैक्सीन लगाने के बाद भी कई सप्ताहों तक मास्क पहनने, नियमित रूप से हाथ धोने, सामाजिक दूरी और भीड़-भाड़ से बचने जैसे हैल्थ प्रोटोकॉल की पालना करना बहुत आवश्यक है।

इस अवसर पर चिकित्सा राज्य मंत्री डॉ. सुभाष गर्ग, मुख्य सचिव श्री निरंजन आर्य, पुलिस महानिदेशक श्री एमएल लाठर, प्रमुख शासन सचिव गृह श्री अभय कुमार, शासन सचिव चिकित्सा शिक्षा श्री वैभव गालरिया, शासन सचिव स्वायत्त शासन श्री भवानी सिंह देथा, एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. सुधीर भण्डारी, चिकित्सा विशेषज्ञ डॉ. वीरेन्द्र सिंह सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. राजाबाबू पंवार तथा वरिष्ठ विशेषज्ञ डॉक्टर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़े।

विकसित करें नया भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र

निवेशकों में हो नीतियों और संसाधनों की प्रभावी ब्रांडिंग

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान में देश और दुनिया के निवेशकों को आकर्षित करने की हर क्षमता मौजूद है। जरूरत है तो बस अनुकूल माहौल तैयार करने की। उन्होंने कहा कि सोलर एवं विंड सेक्टर में ऊर्जा उत्पादन की अपार क्षमता, कुशल मानवीय संसाधन, विस्तृत लैंड बैंक, मुफीद भौगोलिक स्थिति, बेहतर कानून-व्यवस्था के साथ निवेशकों के हित में तैयार की गई नीतियां और फैसले से मजबूत पक्ष हैं, जिनकी ब्रांडिंग कर बड़ी संख्या में उद्यमियों को निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। उन्होंने निर्देश दिए कि अधिकारी राजस्थान की इन विशेषताओं तथा खूबियों को राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय निवेश सम्मेलनों, रोड-शो सहित अन्य प्लेटफॉर्म के माध्यम से शो-केस करें।

श्री गहलोत प्रदेश में निवेशकों की सुविधा के लिए लाई गई वन स्टॉप शॉप प्रणाली, दिल्ली-मुम्बई इंडस्ट्रियल कॉरीडोर (डीएमआईसी) तथा उद्योग से जुड़े विषयों की 23 दिसम्बर को समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राजस्थान के लोगों को अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराने के लिए निवेश लाना सरकार की प्राथमिकता है। इसके लिए एमएसएमई एक्ट, रिप्स-2019, सोलर एवं विण्ड पॉलिसी, वन स्टॉप शॉप प्रणाली, पर्यटन नीति, राजस्थान औद्योगिक विकास नीति जैसे महत्त्वपूर्ण नीतिगत निर्णय किए गए हैं। अधिकारी इन निर्णयों को प्रभावी रूप से लागू कर राजस्थान को निवेशकों का बेस्ट डेस्टीनेशन बनाएं।

टाउन प्लानिंग विशेषज्ञों की देख-रेख में बनाएं नया भिवाड़ी

मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र तथा डीएमआईसी का महत्त्वपूर्ण नोडल होने के साथ-साथ दिल्ली के नजदीक होने के कारण भिवाड़ी में औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार की अपार संभावनाएं मौजूद हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि टाउन प्लानिंग विशेषज्ञों की देख-रेख में एक नया भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की प्लानिंग करें। इससे हम अधिक से अधिक निवेशकों को आकर्षित कर पाएंगे। उन्होंने भिवाड़ी के वर्तमान औद्योगिक क्षेत्र में सड़क, बिजली, पानी, सीवरेज, उद्यमियों के ठहरने के लिए गेस्ट हाउस जैसी आधारभूत सुविधाओं को बेहतर करने के भी निर्देश दिए।

प्राइवेट सेक्टर के सहयोग से विकसित करें नए औद्योगिक क्षेत्र

श्री गहलोत ने कहा कि प्रदेश में औद्योगिक विकास के लिए प्राइवेट सेक्टर के सहयोग से भी औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के प्रयास किए जाएं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के ज्यादा से ज्यादा औद्योगिक क्षेत्रों को डीएमआईसी का लाभ मिल सके, इस दिशा में भी आवश्यक कदम उठाए जाएं। उन्होंने डीएमआईसी के कार्यों को और गति देने के भी निर्देश दिए।

एक ही छत के नीचे मिल सकेंगी निवेश के लिए स्वीकृति

मुख्यमंत्री ने कहा कि वन स्टॉप शॉप राज्य सरकार का महत्त्वपूर्ण नवाचार है, जिसके जरिए एक ही छत के नीचे 14 विभागों के माध्यम से उद्यमियों के निवेश प्रस्तावों को जल्द से जल्द मंजूरी दिलाने का काम किया जाएगा। अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि राज्य सरकार ने जिस मंशा से इस प्रणाली की शुरूआत की है, उसका लाभ उद्यमियों को मिले और उन्हें उद्योग की स्थापना के लिए चक्कर नहीं काटने पड़े। इस प्रणाली के माध्यम से हम ऐसी सर्विस दें कि निवेशक उद्योग की स्थापना के लिए सबसे पहले राजस्थान को चुनें।

रीको के प्रबन्ध निदेशक श्री आशुतोष एटी पेंडणेकर ने बताया कि प्रदेश में उद्योगों की स्थापना के लिए आवश्यक अनुमति एक ही स्थान से प्रदान करने के लिए वन स्टॉप शॉप प्रणाली शुरू की गई है। इसके तहत प्रथम चरण में 14 विभागों के अधिकारियों से 98 तरह की स्वीकृति देने के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। ये अधिकारी उद्योग भवन में सप्ताह में दो बार सोमवार और गुरुवार को उपस्थित रहकर उद्यमियों की मदद करेंगे।

भिवाड़ी इंटीग्रेटेड डवलपमेंट ऑथोरिटी (बीडा) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री प्रताप सिंह ने बताया कि भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र में रीको के सहयोग से 57 करोड़ रुपये की लागत से आधारभूत सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। इस पर जल्द ही काम शुरू हो जाएगा।

बैठक में उद्योग मंत्री श्री परसादी लाल मीणा, उद्योग राज्य मंत्री श्री अर्जुन सिंह बामनिया, मुख्य सचिव श्री निरंजन आर्य, प्रमुख शासन सचिव वित्त श्री अखिल अरोरा, सूचना एवं प्रौद्योगिकी आयुक्त श्री वीरेन्द्र सिंह, उद्योग आयुक्त श्रीमती अर्चना सिंह, चीफ टाउन प्लानर श्री वीके दलेला सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

वैक्सीनेशन में भी राजस्थान बने मॉडल : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कहा है कि कोविड-19 के लिए सभी लोगों का आत्म-विश्वास बढ़ाया जाना जरूरी है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे राजस्थान में सभी को कोविड वैक्सीन देने के लिए पुख्ता तैयारियां करें।

श्री गहलोत 21 दिसम्बर को मुख्यमंत्री निवास पर प्रदेश में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा बैठक को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि महामारी और उसके गम्भीर आर्थिक प्रभावों के कारण बड़ी संख्या में आबादी वैक्सीन की कीमत चुकाने की स्थिति में नहीं है। ऐसे में देश में सभी नागरिकों के लिए वैक्सीन निःशुल्क उपलब्ध करानी चाहिए। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य कार्मिकों और अति आवश्यक सेवाओं से जुड़े फ्रन्टलाइन वॉरियर्स को वैक्सीन के लिए प्राथमिकता देना उचित है। लेकिन अंततः किसी भी अन्य टीकाकरण अभियान की तरह कोविड वैक्सीन भी सभी के लिए (यूनिवर्सल) और निःशुल्क (फ्री) मिलनी चाहिए।

अधिकारी टीकाकरण पर फोकस करें

मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को प्रदेश में टीकाकरण के लिए जमीनी स्तर तक बेहतरीन प्रबंध करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कोविड-19 विश्वव्यापी महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए राजस्थान में की गई शुरूआती तैयारी के चलते प्रदेश मॉडल राज्य बना। अब तक के कोरोना प्रबंधन की तर्ज पर ही हमें वैक्सीनेशन पर फोकस कर ऐसी तैयारी करनी चाहिए कि वैक्सीन प्रबंधन में भी राजस्थान मॉडल बने।

निचले स्तर तक 'माइक्रो-प्लानिंग' की जाए

श्री गहलोत ने कहा कि टीकाकरण के लिए 'माइक्रो-प्लानिंग' के साथ असाधारण तैयारी करनी होगी। बड़ी आबादी को टीका लगाने की प्रक्रिया कम समय में पूरी करने के लिए आवश्यक है कि टीकाकरण केन्द्रों की संख्या ज्यादा हो। इसके लिए भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप वैक्सीन के सुरक्षित भण्डारण तथा अस्पतालों एवं स्वास्थ्य केन्द्रों के साथ-साथ जहां आवश्यकता हो स्कूल-कॉलेजों के भवनों को वैक्सीनेशन केन्द्र बनाने के लिए समय रहते चिह्नित किया जाए। साथ ही, वैक्सीनेशन के कार्य में अनुभवी चिकित्सा विशेषज्ञों के साथ विचार-विमर्श कर अभियान की निचले स्तर तक क्रियान्विति की रूपरेखा तैयार करें।

बड़े शहरों सहित पूरे राजस्थान में संक्रमितों की संख्या लगातार घटी

शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य श्री सिद्धार्थ महाजन ने बैठक में बताया कि प्रदेश में कोविड-19 के संक्रमण की स्थिति नियंत्रित है तथा जयपुर, जोधपुर आदि बड़े शहरों सहित पूरे राजस्थान में संक्रमित व्यक्तियों की संख्या लगातार कम हो रही है। उन्होंने बताया कि बीते सप्ताह से विभिन्न अस्पतालों में कोरोना के गम्भीर रोगियों की संख्या भी घटी है तथा ऑक्सीजन सिलेण्डर की खपत भी लगातार कम हो रही है। राजस्थान में कोरोना संक्रमितों के ठीक होने की दर लगभग 95 प्रतिशत है और मृत्यु दर केवल 0.88 प्रतिशत ही है।

श्री महाजन ने टीकाकरण की तैयारियों के संबंध में बताया कि भारत सरकार के निर्देश के अनुसार प्राथमिकता वाले वर्गों की सूचियां तैयार की जा रही हैं तथा टीकाकरण के लिए जगहों का चयन भी किया जा रहा है। मुख्य सचिव से लेकर ब्लॉक स्वास्थ्य अधिकारी के स्तर पर गठित समितियां लगातार तैयारियों की समीक्षा कर रही हैं। वैक्सीनेशन के लिए मानव संसाधन को प्रशिक्षित भी किया जा रहा है।

18 जनवरी से खुले स्कूल, कॉलेज एवं कोचिंग सेंटर व मेडिकल, डेंटल, नर्सिंग एवं पैरामेडिकल कॉलेज 11 जनवरी से खुले

नया स्ट्रेन चिंता का विषय, विशेष सतर्कता बरतें : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कहा कि देश और प्रदेश में कोविड-19 के नये स्ट्रेन के मामले सामने आना चिंता का विषय है। इसके प्रति किसी भी तरह की लापरवाही बड़ा संकट खड़ा कर सकती है। इसे देखते हुए इस वायरस से अत्यधिक प्रभावित इंग्लैण्ड सहित अन्य देशों से प्रदेश में आए यात्रियों पर विशेष नजर रखी जाए। इन यात्रियों का कोविड टेस्ट एवं सघन स्क्रीनिंग की जाए।

श्री गहलोत ने मुख्यमंत्री निवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंस से कोविड-19 की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि नये स्ट्रेन के कारण इंग्लैण्ड में भयावह स्थिति पैदा हो गई है और वहां फिर लॉकडाउन लगाना पड़ा है। उससे सबक लेते हुए हमें विशेष एहतियात बरतने की आवश्यकता है। उन्होंने निर्देश दिए कि नये स्ट्रेन को लेकर प्रदेश की ओर से केन्द्र सरकार को आवश्यक सुझाव जल्द भेजे जाएं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बेहतरीन प्रबंधन और प्रदेशवासियों के सहयोग से राजस्थान में कोरोना की स्थिति काफी नियंत्रण में है। रिकवरी रेट बढ़कर अब तक की सर्वाधिक 96.31 प्रतिशत हो गई है। कुछ जिलों में पॉजिटिव केस शून्य होने के साथ ही अन्य जिलों में भी स्थिति बेहतर है। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री ने स्कूलों में 9 से 12वीं तक की कक्षाएं, विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय की अन्तिम वर्ष की कक्षाओं, कोचिंग सेन्टर तथा सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों को 18 जनवरी से खोले जाने के निर्देश दिए। साथ ही, वैक्सीनेशन की प्रक्रिया के कारण मेडिकल कॉलेज, डेन्टल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज एवं पैरामेडिकल कॉलेज 11 जनवरी से खोलने के भी निर्देश दिए।

इन सभी शिक्षण संस्थानों में प्रत्येक कक्षा में कुल क्षमता की 50 प्रतिशत उपस्थिति प्रथम दिन तथा शेष 50 प्रतिशत उपस्थिति दूसरे दिन रहेगी। शिक्षकों को संक्रमण की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा जरूरी प्रशिक्षण दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी संस्थानों में सोशल डिस्टेंसिंग एवं मास्क सहित अन्य हैल्थ प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखा जाए तथा इनका संचालन केन्द्र के दिशा-निर्देशों एसओपी के तहत किया जाना सुनिश्चित करें।

श्री गहलोत ने कहा कि प्रदेश में वैक्सीनेशन की तैयारियां मिशन मोड में पूरी की जाएं। वैक्सीनेशन के लिए स्वास्थ्यकर्मियों का पूरा डाटाबेस जल्द से जल्द अपलोड किया जाए। उन्होंने कहा कि वैक्सीन को लेकर केवल प्रमाणिक एवं पुख्ता जानकारी ही मीडिया में प्रसारित होनी चाहिए। अप्रमाणित जानकारियों से लोगों के बीच अनावश्यक भ्रांतियां फैल सकती हैं।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ. रघु शर्मा ने कहा कि कोरोना के नये स्ट्रेन को लेकर प्रदेश में विशेष सतकता बरती जा रही है। चिकित्सा विभाग यूके से आए यात्रियों की कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग एवं स्क्रीनिंग करवाने के साथ ही इनके सैम्पल टेस्ट के लिए दिल्ली स्थित आईसीएमआर लैब में भेज रहा है।

प्रमुख शासन सचिव गृह श्री अभय कुमार ने कहा कि प्रदेश में पॉजिटिव केसों की संख्या घटकर काफी कम हो गई है। ऐसे में यूके सहित

अन्य देशों से आने वाले लोगों की सघन मॉनिटरिंग किया जाना संभव है ताकि नये स्ट्रेन के संक्रमण को रोका जा सके।

शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य श्री सिद्धार्थ महाजन ने बताया कि प्रदेश में 29 नवम्बर को एक्टिव केसेज की संख्या सर्वाधिक 28,758 थी, जो 4 जनवरी को घटकर 8189 रह गई। इसी तरह प्रतिदिन पॉजिटिव केस की संख्या जो 24 नवम्बर को 3314 तक पहुंच गई थी, 4 जनवरी को घटकर 457 रह गई है। उन्होंने प्रदेश में वैक्सीनेशन के लिए की जा रही तैयारियों से भी अवगत कराया।

राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. राजाबाबू पंवार ने कहा कि नये स्ट्रेन को लेकर प्रदेश में सतर्कता बरतना जरूरी है। उन्होंने बताया कि हमारे देश में संभवतः लोगों का इम्यूनिटी लेवल अच्छा होने के कारण नये स्ट्रेन का खतरा यहां कम होगा।

एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. सुधीर भण्डारी ने कहा कि कोरोना के नये स्ट्रेन को देखते हुए इससे प्रभावित देशों से आवागमन को कम से कम रखा जाना चाहिए। साथ ही, ऐसे यात्रियों की एन्ट्री पॉइन्ट पर ही प्रभावी स्क्रीनिंग की जाए। उन्होंने बताया कि नये स्ट्रेन की जांच की सुविधा फिलहाल देश में 8 संस्थानों में उपलब्ध है। तीन सप्ताह में राजस्थान में भी जांच की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।

चिकित्सा विशेषज्ञ डॉ. अशोक पनगड़िया ने कहा कि राज्य सरकार के निरन्तर प्रयासों से प्रदेश में कोरोना का संक्रमण नियंत्रित हो सका है और यहां मृत्य दर काफी कम रही है। उन्होंने वैक्सीनेशन के लिए स्वास्थ्यकर्मियों को जरूरी प्रशिक्षण दिए जाने पर भी जोर दिया। एसएमएस मेडिकल कॉलेज के अन्य विशेषज्ञ चिकित्सकों ने भी नये स्ट्रेन, वैक्सीनेशन और हैल्थ प्रोटोकॉल के सम्बन्ध में विचार व्यक्त किए। ●

प्रदेश में प्रथम चरण में 4.5 लाख हैल्थ वर्कर्स को लगाई जाएगी

कोरोना वैक्सीन

चिकित्सा मंत्री डॉ. रघु शर्मा ने बताया कि प्रदेश में 16 जनवरी से प्रारंभ होने वाले कोरोना वैक्सीनेशन के प्रथम चरण में करीब 4.5 लाख हैल्थकेयर वर्कर्स को सम्मिलित किया गया है, जिन्हें कोविशील्ड कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। उन्होंने बताया कि 282 सैशन साइट पर प्रथम चरण का वैक्सीनेशन होगा। वैक्सीनेशन के लिए चिकित्सा विभाग ने सभी तैयारियां पूर्ण कर ली हैं।

डॉ. शर्मा ने स्वास्थ्य भवन स्थित सभागार में आयोजित प्रेस ब्रीफिंग में वैक्सीनेशन के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कोविड वैक्सीन का भंडारण एयर कनेक्टिविटी वाले तीन जिलों जयपुर, उदयपुर व जोधपुर में किया जाएगा। यहां वैक्सीन को 2 से 8 डिग्री के मध्य रखने की व्यवस्था की गई है।

चिकित्सा मंत्री ने बताया कि राज्य में कोविड वैक्सीन स्टोर के 3 राज्य स्तरीय व 7 संभाग स्तरीय व 34 जिला स्तरीय वैक्सीन स्टोर हैं। उन्होंने बताया कि सामुदायिक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर 2,444 कोल्ड चैन प्वाइंटस कार्यशील हैं। प्रत्येक जिले में एक वैक्सीन वैन भी उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि वैक्सीनेशन के दौरान किसी भी प्रतिकूल प्रभाव से बचाव के लिए वैक्सीनेशन केंद्रों पर 104 व 108 एंबुलेंस की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी।

डॉ. शर्मा ने बताया कि प्रथम चरण वैक्सीनेशन के लिए 5,626 वैक्सीनेशन दलों को प्रशिक्षित किया गया है। प्रथम चरण में 3689 राजकीय चिकित्सा संस्थानों एवं 2969 निजी क्षेत्र के चिकित्सा संस्थानों पर वैक्सीनेशन के लिए चिन्हित किया गया है। इनमें से 3736 चिकित्सा संस्थानों को सतत् स्थल के रूप में कोविन सॉफ्टवेयर अपलोड कर दिया गया है।

चिकित्सा मंत्री ने बताया कि सभी वैक्सीनेशन सतत स्थलों पर टीकाकरण के पश्चात होने वाले संभावित प्रतिकूल प्रभाव के इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। साथ ही कोविड वैक्सीनेशन से सम्बन्धित भारत सरकार से प्राप्त प्रचार, प्रसार सामग्री के मुद्रण एवं वितरण की व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि वैक्सीनेशन की तैयारियों के लिए पूर्व में ही जनप्रतिनिधियों (विधायक, प्रधान, सरपंच), चिकित्सकों, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, स्वास्थ्य मित्र एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और आशा सहयागिनियों का भी जिला, ब्लॉक एवं सेक्टर स्तर पर आमुखीकरण कर दिया गया है।

चिकित्सा मंत्री ने बताया कि वैक्सीनेशन के लिए मुख्य सचिव द्वारा सभी जिला कलक्टर एवं अन्य जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ तैयारियों की समीक्षा के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस की जा चुकी है। साथ ही राज्य स्तर पर शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की अध्यक्षता में स्टेट टास्क फोर्स की बैठक भी आयोजित की गई थी।

प्रेस ब्रीफिंग के दौरान राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मिशन निदेशक श्री नरेश कुमार ठकराल, निदेशक आरसीएच डॉ. लक्ष्मण सिंह ओला व विभाग के अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे। ●

वैक्सीन का बेहतरीन प्रबंधन : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार के बेहतरीन प्रबंधन से प्रदेश में कोरोना की स्थिति अब काफी नियंत्रण में है। मृत्यु दर लगातार कम हो रही है, रिकवरी रेट बढ़ रही है और केस डबलिंग टाइम जो नवम्बर में 58 दिन हो गया था, अब बढ़कर 214 दिन हो गया है। यह सब सुखद संकेत हैं, लेकिन जब तक कोरोना पूरी तरह नहीं चला जाता तब तक हमें इसी मुस्तैदी के साथ काम करना होगा। उन्होंने कहा कि अब वैक्सीनेशन की तैयारियों को और तेज करने की आवश्यकता है। इसके लिए उन्होंने राज्य स्तर से लेकर ब्लॉक स्तर तक चिकित्सा एवं अन्य संबंधित कार्मिकों को गहन प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए।

श्री गहलोत ने मुख्यमंत्री निवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि वैक्सीन के परिवहन के साथ-साथ प्रशिक्षण एवं लोगों को इसके लिए मोटिवेट करने पर विशेष जोर दिया जाए। उन्होंने वैक्सीनेशन के लिए सेंटर्स पर तमाम सुविधाएं विकसित करने के भी निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वैक्सीनेशन को लेकर आमजन में जागरूकता के लिए एक प्रभावी कम्यूनिकेशन प्लान बनाया जाए। साथ ही व्यापक प्रचार-प्रसार कर लोगों को वैक्सीन तथा इसके प्रोटोकॉल के संबंध में आवश्यक जानकारी दी जाए। उन्होंने कहा कि दुनिया के कई देशों में वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। देश में जैसे ही वैक्सीनेशन शुरू होता है, कोरोना की तरह हमें टीकाकरण प्रबंधन में भी उसी भावना और मनोयोग के साथ पूरी तैयारी से जुटना है।

श्री गहलोत ने कहा कि वैक्सीनेशन करने एवं मोटिवेशन के लिए अलग-अलग टीमें तैयार कर उन्हें गहन प्रशिक्षण दें। खासकर से चिकित्साकर्मी जो टीकाकरण के काम से सीधे जुड़े हैं, उन्हें इसके हर पहलू की जानकारी दी जाए ताकि किसी भी स्तर पर चूक की कोई गुंजाइश नहीं रहे। उन्होंने विभिन्न देशों में वैक्सीन के अनुभव का भी गहन विश्लेषण करने के निर्देश दिए और कहा कि प्रदेश की परिस्थितियों में उनके प्रभाव का अभी से आकलन किया जाए। श्री गहलोत ने कोरोना को लेकर प्रभावी जागरूकता अभियान के लिए सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग तथा स्वायत्त शासन विभाग के प्रयासों को सराहा।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के शासन सचिव श्री सिद्धार्थ महाजन ने बताया कि शत-प्रतिशत आरटी-पीसीआर टेस्ट के बावजूद पॉजिटिविटी रेट का लगातार गिरना अच्छा संकेत है। अब संक्रमण की दर 3.75 प्रतिशत ही रह गई है। दिवाली के आस-पास जयपुर में जहां प्रतिदिन केसों की संख्या 700 तक पहुंच गई थी, वह अब घटकर मात्र 140 के आस-पास रह गई है। संक्रमित केसों में गिरावट की ऐसी ही स्थिति प्रदेश के अन्य शहरों में भी दिखाई दे रही है। इसी तरह ऑक्सीजन एवं वेंटीलेटर्स की मांग भी काफी कम हो गई है। आरयूएचएस अस्पताल में 1200 बेड की क्षमता के विरूद्ध अब कोरोना के मात्र 137 मरीज भर्ती हैं। उन्होंने बताया कि वैक्सीनेशन एवं इसकी गाइडलाइन को लेकर प्रशिक्षण व्यापक स्तर पर प्रारम्भ कर दिया है।

राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. राजाबाबू पंवार ने सार्स वन, एच1 एन1 तथा अन्य वायरस के अनुभवों का जिक्र करते हुए वायरस की प्रकृति के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हर वायरस की बर्थ सर्किल के साथ-साथ डेथ सर्किल भी होती है और एक समय बाद उसका प्रभाव कम होता जाता है।

एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. सुधीर भण्डारी ने बताया कि एसएमएस तथा इससे संबद्ध अस्पतालों में 15 रोल मॉडल वैक्सीनेशन सेंटर्स विकसित किए जा रहे हैं। इन्हीं के अनुरूप प्रदेश के अन्य चिकित्सालयों में भी टीकाकरण केंद्र बनाए जा सकते हैं।

चिकित्सा विशेषज्ञ डॉ. वीरेन्द्र सिंह ने कहा कि सर्दी बढ़ने पर इस बीमारी के बढ़ने की आशंका व्यक्त की गई थी, लेकिन केसों की संख्या लगातार कम होना यह संकेत भी देता है कि हम हर्ड इम्यूनिटी के नजदीक हो सकते हैं। चिकित्सा विशेषज्ञ डॉ. पीआर गुप्ता, डॉ. एमएल गुप्ता, डॉ. अशोक अग्रवाल, डॉ. रामबाबू शर्मा, डॉ. अभिषेक अग्रवाल, डॉ. धर्मेश कुमार ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विचार व्यक्त किए।

बैठक में मुख्य सचिव श्री निरंजन आर्य, पुलिस महानिदेशक श्री एमएल लाठर, प्रमुख शासन सचिव गृह श्री अभय कुमार, चिकित्सा शिक्षा सचिव श्री वैभव गालरिया, स्वायत्त शासन विभाग के शासन सचिव श्री भवानी सिंह देथा, सूचना एवं जनसम्पर्क आयुक्त श्री महेन्द्र सोनी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

एवियन इन्फ्लूएंजा

से पक्षियों के मरने की घटनाओं पर विशेष निगरानी रखें

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने देश के विभिन्न राज्यों तथा प्रदेश के विभिन्न जिलों में एवियन इन्फ्लूएंजा से कौओं की मौत तथा पक्षियों के मरने की अन्य घटनाओं के मद्देनजर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि घना बर्ड सेंचुरी, विभिन्न अभयारण्य, सांभर झील सहित अन्य वेटलैण्डस और तमाम ऐसे स्थान जहां पक्षी अधिक पाए जाते हैं, वहां की घटनाओं पर विशेष निगरानी रखी जाए। किसी भी पक्षी की मौत होने पर उसका सैम्पल जांच के लिए लैब में भेजा जाए और वैज्ञानिक विधि से मृत पक्षियों का निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।

श्री गहलोत ने मुख्यमंत्री निवास पर इस सम्बन्ध में पशुपालन, चिकित्सा, वन तथा अन्य सम्बन्धित विभागों के साथ समीक्षा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 16 जिलों में कौओं सहित अन्य पक्षियों के मरने की घटनाएं चिंता का विषय है। इनमें से चार जिलों झालावाड़, कोटा, बारां तथा जयपुर में मृत कौओं में एवियन इन्फ्लूएंजा वायरस की पुष्टि हुई है। इस वायरस की रोकथाम के लिए प्रभावी उपाय सुनिश्चित किए जाएं। पशु चिकित्सक एवं पक्षी विशेषज्ञ इन घटनाओं का बारीकी से विश्लेषण करने के साथ ही इन्हें रोकने के पर्याप्त इन्तजाम रखें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे यहां पक्षियों से लोगों का विशेष जुड़ाव रहता है। लापरवाही बरतने तथा प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने पर यह वायरस इंसान को भी प्रभावित कर सकता है। इसे देखते हुए खास सावधानी बरते जाने की आवश्यकता है। उन्होंने आमजन से अपील की है कि यदि वे अपने घर की छतों या आस-पास मृत पक्षी को देखें, तो उसे हाथ लगाने के स्थान पर सुरक्षित निस्तारण के लिए सूचना पशुपालन विभाग के द्वारा स्थापित राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष के दूरभाष नम्बर 0141-2374617 तथा जिलों में स्थापित नियंत्रण कक्षों पर दें।

श्री गहलोत ने कहा कि फिलहाल राजस्थान में मुर्गियों में इस रोग के फैलने की कोई सूचना नहीं है। फिर भी पशुपालन विभाग के अधिकारी पोल्ट्री संचालकों को जागरूक करें और विशेष सतर्कता बरतने के लिए प्रेरित करें।

शासन सचिव पशुपालन डॉ. आरूषी मलिक ने बताया कि राजस्थान के साथ-साथ हिमाचल प्रदेश और मध्यप्रदेश में कौओं में तथा केरल में मुर्गियों में एवियन इन्फ्लूएंजा के मामले सामने आए हैं। केवलादेव अभयारण्य, सांभर झील, खींचन सहित तमाम ऐसे स्थान जहां प्रवासी पक्षी अधिक आते हैं। वहां विशेष सावधानी बरती जा रही है। प्रदेश में अभी तक 625 पक्षियों के मरने की सूचना प्राप्त हुई है, जिनमें 122 के सैम्पल भोपाल स्थित प्रयोगशाला में भिजवाए गए हैं। जिनमें से 29 कौओं में एवियन इन्फ्लूएंजा वायरस की पुष्टि हुई है।

उन्होंने बताया कि पोल्ट्री संचालकों के साथ वीसी रखी गई है। जयपुर में टेस्टिंग सुविधा विकसित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि सभी जिला कलक्टरों को भारत सरकार की गाइडलाइन भेजी जा चुकी है।

प्रमुख शासन सचिव वन एवं पर्यावरण श्रीमती श्रेया गुहा ने बताया कि वन विभाग ऐसी घटनाओं को लेकर वन क्षेत्रों में पूरी सतर्कता एवं चौकसी बरत रहा है। विभाग के कर्मचारी भी पशुपालन विभाग को पूरा सहयोग कर रहे हैं। प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हॉफ) श्रीमती श्रुति शर्मा, प्रधान मुख्य वन एवं वन्य जीव संरक्षक श्री मोहन लाल मीणा सहित अन्य अधिकारियों ने भी विचार व्यक्त किए।

इस अवसर पर चिकित्सा मंत्री डॉ. रघु शर्मा, पशुपालन मंत्री श्री लालचन्द कटारिया, प्रमुख शासन सचिव पशुपालन श्री कुंजीलाल मीणा, शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य श्री सिद्धार्थ महाजन, सूचना एवं जनसम्पर्क आयुक्त श्री महेन्द्र सोनी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे।

भील राजा बांसिया की प्रतिमा का अनावरण

आदिवासी समाज का गौरवपूर्ण इतिहास प्रेरणादायी

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कहा कि प्रदेश के आदिवासी क्षेत्र के महापुरुषों ने देश की आजादी तथा सामाजिक चेतना जागृत करने में बड़ी भूमिका निभाई है। इस अंचल के गौरवपूर्ण इतिहास पर हम सभी को गर्व है। राज्य सरकार आदिवासी समाज के त्याग एवं बलिदान की गौरव गाथाओं को जन-जन तक पहुंचाने तथा इस अंचल के विकास में कोई कमी नहीं रखेगी।

श्री गहलोत 14 जनवरी को मुख्यमंत्री निवास से वीडियो कांफ्रेंस के जरिए बांसवाड़ा नगर परिषद परिसर में भील राजा बांसिया की प्रतिमा के अनावरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि मानगढ़ धाम पर गोविन्द गुरू के नेतृत्व में जुटे सैकड़ों आदिवासी भाई-बहनों ने देश के लिए जो शहादत दी, उसे कोई नहीं भूल सकता। मावजी महाराज की शिक्षाओं तथा नानाभाई खांट, कालीबाई, मामा बालेश्वर दयाल, भीखाभाई भील, हरिदेव जोशी, हरिभाऊ उपाध्याय सहित अन्य महापुरूषों के योगदान को हम सभी आज भी बड़े गर्व से याद करते हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जब-जब भी हमारी सरकार बनी आदिवासी समाज को केन्द्र में रखकर फैसले किए गए। उसी का परिणाम है कि यह क्षेत्र शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, सड़क, चिकित्सा सहित अन्य क्षेत्रों में विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है। बांसवाड़ा में इंजीनियरिंग कॉलेज एवं गोविन्द गुरू जनजातीय विश्वविद्यालय, डूंगरपुर में मेडिकल कॉलेज जैसी उच्च शिक्षण संस्थाएं स्थापित की गईं। यहां के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्धता से राज्य सरकार काम कर रही हैं।

श्री गहलोत ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू एवं स्व. राजीव गांधी का आदिवासी भाइयों से आत्मीय जुड़ाव रहा। उन्होंने आदिवासी समाज के सामाजिक एवं सांस्कृतिक उत्थान के लिए कई कदम उठाए। मनरेगा योजना का बड़ा लाभ इस क्षेत्र को मिला है। सिंचाई परियोजनाओं की दिशा में इस क्षेत्र में काफी काम हुआ है। डूंगरपुर-बांसवाड़ा-रतलाम रेल परियोजना के लिए हमारी पिछली सरकार के समय कदम उठाया गया, लेकिन दुर्भाग्य से यह काम आगे नहीं बढ़ सका। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से इस परियोजना पर काम शुरू करने के लिए आग्रह किया है ताकि यह आदिवासी क्षेत्र रेल माध्यम से जुड़ सके।

नगरीय विकास मंत्री श्री शांति धारीवाल ने कहा कि भील राजा बांसिया की प्रतिमा से नई पीढ़ी को प्रेरणा मिलेगी। उन्होंने कहा कि बांसवाड़ा में 320 करोड़ रूपए से पेयजल एवं सीवरेज की महत्त्वाकांक्षी योजना पर जल्द काम शुरू किया जा रहा है। इसका लाभ यहां की करीब एक लाख की आबादी को मिलेगा।

जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्यमंत्री श्री अर्जुन सिंह बामनिया ने कहा कि टीएसपी क्षेत्र के युवाओं को कोचिंग तथा शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ने के बेहतर अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बांसवाड़ा के संस्थापक राजा बांसिया की प्रतिमा के साथ-साथ समाई माता पहाड़ी क्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के लिए राज्य सरकार काम कर रही है।

सांसद श्री कनकमल कटारा, विधायक श्री हरेन्द्र निनामा, श्री कैलाश मीणा, श्रीमती रमिला खड़िया, जिला प्रमुख श्रीमती रेशम मालवीय तथा नगर परिषद सभापति श्री जैनेन्द्र त्रिवेदी ने भी समारोह को संबोधित किया। इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री निरंजन आर्य, प्रमुख शासन सचिव जनजातीय क्षेत्र विकास श्री शिखर अग्रवाल सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। स्वायत्त शासन विभाग के शासन सचिव श्री भवानी सिंह देथा ने स्वागत उद्बोधन दिया।

खनन क्षेत्र का पूरी प्रतिबद्धता के साथ विकास करेगी सरकार

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान में अपार खनिज सम्पदा मौजूद है, जिसका समुचित दोहन न केवल राजस्थान बल्कि हमारे देश की तस्वीर बदल सकता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश को खनन के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता, तकनीक, पारदर्शिता और इन्वेस्टमेन्ट फ्रेंडली नीति के साथ काम करेगी। उन्होंने इससे सम्बन्धित मुद्दों के त्वरित निस्तारण के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में वन विभाग, खान विभाग और राजस्व विभाग के अधिकारियों की एक टास्क फोर्स गठित करने के भी निर्देश दिए।

श्री गहलोत ने मुख्यमंत्री निवास पर राजस्थान में खनन क्षेत्र के विकास की संभावनाओं पर वेदांता समूह के चेयरमैन श्री अनिल अग्रवाल एवं अन्य अधिकारियों के साथ चर्चा की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि खनन के क्षेत्र में राजस्थान को आगे बढ़ाने के लिए राज्य सरकार लगातार सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ फैसले ले रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में खनिज अन्वेषण को गति देने के लिए राज्य मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट का गठन किया गया है। अब हम जल्द ही एक बेहतर खनिज नीति लाने जा रहे हैं। इससे राजस्थान में खनन के क्षेत्र में निवेश के लिए अनुकूल वातावरण मिलेगा। निवेशकों को हमारी नीतियों और फैसलों की जानकारी मिल सके और वे विकास की यात्रा में हमारे भागीदार बन सकें, इसके लिए एक प्रभावी अभियान भी चलाया जाएगा।

श्री गहलोत ने कहा कि राजस्थान में दूसरे राज्यों के मुकाबले कहीं अधिक खनिज सम्पदा मौजूद है, लेकिन समुचित दोहन नहीं होने के कारण राजस्व प्राप्ति में इसका हिस्सा काफी कम है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में खनन क्षेत्र का विकास होने पर राजस्व में बड़ी वृद्धि के साथ-साथ रोजगार के अवसरों में भी बढ़ोतरी हो सकेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में खनिजों के एक्सप्लोरेशन को वैज्ञानिक और तकनीकी दक्षता के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि खनन कम्पनियों को रिसोर्सेज से सम्बन्धित आंकड़ों की पर्याप्त जानकारी उपलब्ध कराएंगे और हमारा प्रयास है कि प्रदेश में ऑक्शन की प्रक्रिया डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से पारदर्शी तरीके से पूरी की जाए। उन्होंने कहा कि लीज आवंटन और ऑक्शन से संबंधित प्रक्रियाओं की मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के स्तर पर प्रभावी मॉनिटरिंग की जाएगी।

श्री गहलोत ने खनन श्रमिकों को सिलिकोसिस जैसी घातक बीमारी से बचाने के लिए वेदांता समूह को अनुसंधान कर रिपोर्ट तैयार करने का सुझाव दिया। इस विषय में किये गये अनुसंधान का लाभ देशभर के खनन श्रमिकों को मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि इस बीमारी से बड़ी संख्या में श्रमिकों की जान चली जाती है। राज्य सरकार सिलिकोसिस पीड़ित श्रमिकों के कल्याण के लिए अक्टूबर, 2019 में ही सिलिकोसिस नीति लागू कर चुकी है।

खान मंत्री श्री प्रमोद जैन भाया ने वेदांता समूह की कम्पनी केयर्न एनर्जी द्वारा बाड़मेर में तेल एवं गैस उत्पादन के कार्य की सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में विभिन्न खनिजों के रूप में भरपूर संपदा मौजूद है।

वेदांता समूह के चेयरमैन श्री अनिल अग्रवाल ने कहा कि राजस्थान खनिजों के रूप में धन उपजाने वाली धरती है। यहां जिंक से लेकर सिल्वर, लेड, कॉपर और सोने के साथ-साथ गैस, तेल, लाइमस्टोन और पोटाश जैसे खनिज भरपूर मात्रा में हैं।

श्री अग्रवाल ने कहा कि विदेशों से आयात होने वाले लगभग सभी खनिज राजस्थान में उपलब्ध हैं। इन खनिज भण्डारों के पर्याप्त दोहन से ऐसे आयात में होने वाले खर्च का 63 प्रतिशत राजस्व राजस्थान को मिल सकता है। उन्होंने राज्य सरकार से इस क्षेत्र के विकास के लिए नये स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने, आईआईटी और आईआईएम सहित इस क्षेत्र के विशेषज्ञ संस्थानों से युवाओं को आकर्षित करने, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं की मदद लेने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि राजस्थान में पर्यटन क्षेत्र में निजी निवेशकों की 'ना लाभ-ना हानि' के सिद्धान्त पर भागीदारी इस क्षेत्र में बड़ा बदलाव ला सकती है।

श्री अग्रवाल ने कुपोषण की समस्या को दूर करने के लिए प्रदेश के आंगनबाड़ी केन्द्रों को नंदघर के रूप में विकसित करने की योजना को आगे बढ़ाने की इच्छा भी जाहिर की। उन्होंने बताया कि वर्तमान में प्रदेश के 11 जिलों में लगभग 1100 नंदघर विकसित किए गए हैं, जहां छोटे बच्चों को पोषाहार उपलब्ध कराने के साथ ही इन केन्द्रों से जुड़ी महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में राजस्थान में कोरोना के कुशल प्रबंधन की सराहना भी की।

विभिन्न क्षेत्रों में हुए अभूतपूर्व कार्य

अजमेर जिले के प्रभारी एवं कृषि मंत्री श्री लालचन्द कटारिया तथा चिकित्सा व जनसम्पर्क मंत्री डॉ. रघु शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार दो साल में प्रदेश के हर वर्ग की उम्मीदों पर खरी उतरी है। सरकार ने जन घोषणा पत्र में जो वादे किए थे । उनमें से आधे से अधिक वादे पूरे किए जा चुके हैं। हम समाज के प्रत्येक वर्ग को केन्द्र में रखकर जन हितैषी काम कर रहे हैं। पूरे देश ने देखा है कि मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में राजस्थान सरकार ने कोरोना महामारी से बचाव के लिए शानदार प्रबन्धन किया है। हमने चिकित्सा के क्षेत्र में बेहतरीन काम तो किया ही, साथ ही मानवता की सेवा के लिए ना किसी को भूखा सोने दिया और ना ही किसी प्रवासी श्रमिक को पैदल चलने दिया। राजस्थान सरकार ने सड़कों पर पैदल चलने वाले श्रमिकों को शेल्टर होम में ठहराया और उन्हें उनके गंतव्य स्थान तक भी पहुंचाया। किसानों की कर्ज माफी सहित कई ऐसे निर्णय हैं जो राज्य सरकार ने तय समय सीमा में पूरे किए हैं।

प्रभारी एवं कृषि मंत्री श्री लालचन्द कटारिया तथा चिकित्सा व जनसम्पर्क मंत्री डॉ. रघु शर्मा ने राज्य सरकार के दो साल पूरे होने पर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के रीट कार्यालय भवन में पत्रकारों से बातचीत की। इस अवसर पर चिकित्सा मंत्री डॉ. रघु शर्मा ने कहा कि

राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में दो वर्षों में कोरोना प्रबंधन सहित विभिन्न क्षेत्रों में अभूतपूर्व कार्य किया है। प्रदेश में कोरोना बीमारी की शुरूआत में कोविड-19 की जांच का अभाव था। उस समय सैंपल जांच के लिए बाहर भेजे जाते थे। राज्य सरकार ने आपदा को अवसर में बदलते हुए अपनी टेस्टिंग क्षमता और चिकित्सा व्यवस्था को जबरदस्त रूप से सुदृढ़ किया। आज राजस्थान में प्रतिदिन 60 हजार टेस्टिंग करने की क्षमता है। इसे शीघ्र ही एक लाख टेस्ट प्रतिदिन करने तक विस्तारित किया जाएगा। राज्य में आरटीपीसीआर तकनीक से जांच की जा रही है। यह जांच विश्वसनीय है। लॉकडाउन एवं अनलॉक की प्रक्रिया के दौरान राजस्थान में हैल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया गया है। संक्रमण रोकने का भीलवाड़ा एवं रामगंज मॉडल सबके लिए प्रेरणादायक रहा। ●

जनजातीय विद्यार्थियों के छात्रावासों व विद्यालयों के लिये

6.63 करोड़ की लागत से डिजीटल लर्निंग डिवाइस खरीदे जायेंगे

मुख्य सचिव श्री निरंजन आर्य की अध्यक्षता में जनजाति उपयोजना के प्रभावी निर्माण, क्रियान्वयन एवं मॉनिटरिगं हेतु गठित राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति की वीडियो कॉन्फ्रेसिगं के जरिये बैठक आयोजित की गई । बैठक में मुख्य सचिव ने जनजातीय विद्यार्थियों के 36 आवासीय छात्रावासों व 398 विद्यालयों के लिये 6.63 करोड़ की लागत से डिजीटल लर्निंग डिवाइस खरीदे जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इससे न केवल ऑन-लाईन कक्षा का प्रसारण हो सकेगा बल्कि तैयार लर्निंग सामग्री भी विद्यार्थियों को उपलब्ध हो सकेगी ।

प्रमुख शासन सचिव, टीएडी, श्री शिखर अग्रवाल ने अवगत करवाया कि यह राशि वर्ष 2020-21 में कोविड महामारी की वजह से जनजातीय विद्यार्थियों की कैरियर काउन्सिलिंग, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को भारत भ्रमण न करवा पाने, आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों के छात्र-छात्राओं की अनिवार्य विषयों की विशेष कोचिंग व खेलमय योग प्रशिक्षण, संगीत, नृत्य व वाद्य यंत्र प्रशिक्षण आयोजित न होने के कारण बच गई है । इस पर मुख्य सचिव ने इस राशि के डायवर्जन की अनुमति दे दी ।

श्री आर्य ने जनजातीय कृषकों को छोटी-छोटी जोत में खेत की जुताई करने, बीज की बुवाई करने, खरपतवार नियन्त्रण व फसल की कटाई करने में उपयोग किये जाने वाले सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मेकेनाईजेशन के अन्तर्गत कृषि यन्त्र में पावर टिलर पर 15 करोड़ 77 लाख के अनुदान के प्रस्ताव को अनुमोदित किया।

उन्होंने वर्ष 2020-21 की अन्तिम तिमाही में जनजातीय छात्रावासों के 40 वार्डन आवासों एवं 35 शौचालय एवं बाथरूम के निर्माण को भी अनुमोदित किया। ●

जयपुर शहर में 436 लाख रुपये से होगा

सौन्दर्यीकरण एवं पौधारोपण

नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री श्री शांति धारीवाल की स्वच्छ शहर की संकल्पना को साकार करते हुए जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा 436 लाख रुपये की लागत से शहर में विभिन्न स्थानों पर सौन्दर्यीकरण एवं पौधारोपण के कार्य करवाये जा रहे हैं।

जेडीए क्षेत्राधिकार में स्थित पार्कों में गुलदाउदी एवं पिटुनिया के पौधे लगाने के लिए 10 लाख रूपये, जोन-1 में पार्कों के वार्षिक रख-रखाव एवं विकास कार्य हेतु 2.78 लाख रुपये, जेडीए क्षेत्राधिकार में विभिन्न कार्यों के लिए 20.74 लाख, मानसरोवर मैट्रो स्टेशन से जयपुर जंक्शन एवं अजमेर एलिवेटेड रोड के नीचे मीडियन में द्विवार्षिक रख-रखाव एवं संधारण हेतु 39.18 लाख रुपये, आर्मी एरिया एवं सिरसी रोड पर मीडियन के संधारण कार्य हेतु 26.72 लाख रुपये की लागत से सौन्दर्यीकरण एवं संधारण कार्य करवाये जा रहे हैं। प्रिंस रोड, क्वीन्स रोड, संजय नगर कच्ची बस्ती, सी जोन-बाईपास अजमेर रोड से वैशाली नगर में मीडियन व ग्रीन बैल्ट के द्विवार्षिक रख-रखाव एवं वृक्षारोपण हेतु 36.93 लाख रुपये, महल रोड से अक्षय पात्र से विधाणी क्रॉसिंग तक वानिकी एवं सौन्दर्यीकरण के द्विवार्षिक कार्य हेतु 13.57 लाख रुपये, टोंक रोड पर सांगानेर फ्लाईओवर से सीतापुरा फ्लाई ओवर तक सड़क के मीडियन व ग्रीन बैल्ट के द्विवार्षिक रख-रखाव हेतु 25.71 लाख रुपये, वाटिका रोड से टोंक रोड से वाटिका में जेडीए योजना तक पौधों के रख-रखाव हेतु 12.26 लाख रुपये की लागत से कार्य करवाये जा रहे हैं।

जेडीए द्वारा सिविल लाईन क्षेत्र, एलिवेटेड रोड मीडियन एवं स्टेच्यू सर्किल के विकास एवं द्विवार्षिक रख-रखाव के कार्यों के लिये 45.78 लाख रुपये, वुडलैंड पार्क एवं बी-2 बाईपास के ग्रीन बैल्ट के द्विवार्षिक रख-रखाव हेतु 31.68 लाख रुपये, जेडीए क्षेत्राधिकार में पौधों की कटाई-छटाई, पौधारोपण के लिये 74.56 लाख रुपये एवं जवाहर सर्किल के संधारण कार्य हेतु 95.97 लाख रुपये स्वीकृत किये गये हैं।

कोरोना महामारी को मात देकर

देश के सामने नजीर बना राजस्थान

दुनिया और देश के तमाम राज्यों की तरह राजस्थान में भी कोरोना महामारी ने अपने पैर पसारने की हर संभव कोशिश की लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की माइक्रो प्लानिंग और चिकित्सा मंत्री डॉ रघु शर्मा की सतर्कता के चलते कोरोना अपने मंसूबों पर कामयाब नहीं हो पाया। मुख्यमंत्री और चिकित्सा मंत्री के अथक प्रयासों का ही परिणाम रहा कि प्रदेश में रिकवरी रेट 96.65 फीसदी तक जा पहुंची। वहीं मृत्यु दर 0.86 फीसदी तक ही रही। प्रदेश में जांचों का दायरा भी 66 हजार के करीब पहुंच गया है। कोरोना से लड़ाई के पहले दिन से ही चिकित्सा विभाग मजबूत खड़ा नजर आया। कोरोना काल में चिकित्सकीय सेवाओं के आधारभूत ढांचे को भी मजबूती दी गई। कोरोना महामारी को मात देकर देश के सामने नजीर बने राजस्थान में किए गए नवाचारों पर **चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ. रघु शर्मा का दृष्टिकोण।**

गोविंद पारीक, संयुक्त निदेशक एवं हेतप्रकाश व्यास, जनसम्पर्क अधिकारी द्वारा किये गए साक्षात्कार के महत्त्वपूर्ण अंश।

राजस्थान में कोरोना संक्रमितों के ठीक होने की दर 96 प्रतिशत से अधिक जा पहुंची है, यह सब कैसे संभव हो पाया ?

मार्च, 2020 में जब राजस्थान में कोरोना का पहला केस आया। उस वक्त राज्य में कोविड जांच की सुविधा भी नहीं थी और सैंपल जांच के लिए पुणे की लैब में भेजे जाते थे। मुख्यमंत्री के निर्देश पर राज्य में ही कोविड जांच की सुविधा उपलब्ध कराने का निर्णय हुआ। अब राजस्थान करीब 66 हजार के लगभग कोविड जांच प्रतिदिन करने की क्षमता रखता है और आने वाले दिनों में यह संख्या एक लाख प्रतिदिन तक पहुंच जाएगी। सरकार ने जांच के लिए प्राइवेट सेक्टर को भी अनुमति दी। वर्तमान में राजस्थान में निजी लैब में जांच कराने की दर 800 रुपए है, जो कि देश भर मे सबसे कम है। राज्य में केवल आरटीपीसीआर किट से जांच की जा रही है, जो कि सर्वाधिक विश्वसनीय है।

रामगंज व भीलवाड़ा मॉडल को पूरे देश में सराहा गया। यह कैसे संभव हुआ और स्वास्थ्य के क्षेत्र में नई प्राथमिकताएं क्या है ?

कोरोना एक ऐसी महामारी है, जिसका सामना पूरी दुनिया कर रही है। हमारा लक्ष्य रहा है कि महामारी के मुकाबले के दौरान जनहानि ना हो और कोई भूखा नहीं सोए, इन लक्ष्यों को लेकर राज्य सरकार ने निर्णय किए। विशेष बात यह रही कि मुख्यमंत्री ने समाज के हर वर्ग से बात की और एक्सपर्ट की राय के साथ ही महामारी का सामना किया। दूसरी और माइग्रेंट लेबर की समस्या हो या फिर स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने का सवाल, सभी बिंदुओं पर तुरंत निर्णय लिए गए और अब भी वह सतर्कता जारी है। इसलिए हमेशा कहा है कि 'राजस्थान सतर्क' है। भीलवाड़ा मॉडल इसलिए सफल रहा क्योंकि वहां करीब 18 लाख लोगों को सर्वे में शामिल किया, कंटेनमेंट जोन बनाया, बॉर्डर सील किए गए इसलिए हम सफल रहे। वहीं रामगंज मॉडल इसलिए सफल रहा क्योंकि हमने एक अन्य उपाय किया। हमने यहां क्वारंटीन फैसिलिटी डवलप की। इसके अलावा जनगणना के हिसाब से इस क्षेत्र को 30 भागों में बांटा और प्रतिदिन इन 30 भागों की रैंडम सैंपल लेकर टेस्ट किए। लोगों को क्वारंटीन फैसेलिटी दी और संक्रमण पर काबू पाया।

हैल्थ के क्षेत्र में राजस्थान में सर्विस ऑफ डिलीवरी हमेशा से चुनौती रहा है, इस क्षेत्र में आपने क्या प्रयास किए है ?

राजस्थान में कोरोना की शुरुआत के समय टेस्टिंग की सुविधा शून्य थी लेकिन राजस्थान में तेजी से टेस्टिंग फैसिलिटी डवलप की गई। इसके अलावा वेंटिलेटर, बेड, ऑक्सीजन की प्रत्येक अस्पताल में उपलब्धता पर ध्यान दिया गया। मेडिकल कॉलेज से संबंधित अस्पतालों में ऑक्सीजन जनरेशन के प्लांट एवं लिक्विड ऑक्सीजन के प्लांट लगाने का कार्य प्रारंभ किया गया। वहीं आईसीयू को लगातार अपडेट किया गया। नतीजन हमारा रिकवरी रेट लगातार सुधरता गया। दवाओं का जो कॉम्बिनेशन कोविड मरीजों को दिया गया वह काफी हद तक कामयाब रहा। वहीं रेमडेसिविर व टोसिलीजूमेब इंजेक्शन जिसकी कीमत करीब 40 हजार रुपए थी उसको निःशुल्क उपलब्ध कराया गया। सैंकड़ों लोगों का प्लाज्मा थैरेपी के जरिए इलाज किया गया। इसलिए कह सकते हैं कि राजस्थान के डॉक्टर्स ने जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल सेट किया है उसी का नतीजा रहा कि राजस्थान में कोरोना से होने वाली मृत्यु दर पूरे देश में सबसे कम है।

चिकित्सा से संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ मानव संसाधन को पूरा करने के लिए क्या कार्य किए गए ?

राजस्थान भौगोलिक दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है। इसलिए चुनौतियां इंफ्रास्टक्चर के साथ-साथ चिकित्साकर्मियों की कम

संख्या को लेकर भी थी। इसलिए हमने इस ओर लगातार कार्य किया है, हमने 735 चिकित्सकों की प्रथम फेज में भर्ती की। इसके बाद हाल ही करीब 2000 डॉक्टरों की भर्ती प्रक्रिया पूर्ण की है। करीब 12,500 एएनएम व जीएनएम की भर्ती की। वहीं आने वाले दिनों में 7,810 सीएचओ को भी नियुक्ति दी जाएगी। इसके अलावा तकनीकी कार्मिकों की भर्ती की प्रक्रिया जारी है। वहीं आयुर्वेद ने भी इस दौर में बड़ा कार्य किया। इसमें 900 से अधिक आयुर्वेद चिकित्सकों एवं कंपाउडरों की भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ की है। वहीं 'पोस्ट कोविड केयर' क्लीनिक और 'डे केयर सेंटर' भी शुरू किए गए हैं।

कोरोना काल में कोरोना के अलावा बीमारियों से ग्रस्त मरीजों को राहत पहुंचाने के लिए सरकार के क्या प्रयास रहे ?

लॉकडाउन और कर्फ्यूग्रस्त क्षेत्रों के लोगों को अन्य बीमारियों के लिए चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए मोबाइल ओपीडी वैन शुरू की गई। 550 मोबाइल ओपीडी वैन अब तक राज्य के 30 लाख से ज्यादा मरीजों को चिकित्सा परामर्श और उपचार कर चुकी हैं। आमजन को जांच एवं दवा वितरण की सेवाएं मोबाइल वैन के जरिए दी जा रही हैं। वैन उपखंड मुख्यालयों के साथ अन्य महत्त्वपूर्ण स्थानों पर सुबह 8 से 2 बजे तक चिकित्सा उपचार सेवाएं उपलब्ध कराती हैं। कोई भी व्यक्ति इस सेवा के अंतर्गत निःशुल्क उपचार ले सकता है। वैन में नियुक्त चिकित्सक व पैरामेडिकल स्टाफ जुकाम, बुखार जैसी सामान्य बीमारियों के अलावा मधुमेह, हाइपरटेंशन जैसी बीमारियों की दवाएं उपलब्ध करवा रहे हैं।

जो मरीज कोरोना की वजह से घर से बाहर ही नहीं निकल पा रहे थे, उनके लिए भी सरकार ने कोई ऑनलाइन सेवा शुरू की ?

चिकित्सा विभाग द्वारा लॉकडाउन में आमजन को ऑनलाइन टेली-कंसल्टेंसी सेवा (चिकित्सकीय परामर्श सुविधा) उपलब्ध कराने के लिए लॉन्च पोर्टल esanjeevaniopd.in अब लोगों की जरूरत बनता जा रहा है। इस सुविधा से मरीज घर बैठे गुणवत्तापूर्ण चिकित्सकीय सेवाएं निःशुल्क प्राप्त कर रहे हैं। अब तक इस सुविधा का लाभ हजारों लोग ले चुके हैं। कोई भी व्यक्ति सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक 30 चिकित्सकों के माध्यम से सामान्य बीमारियों के लिए टेली कंसलटेंसी सेवाएं प्राप्त कर सकता है। प्रदेश में चिह्नित 100 चिकित्सा संस्थानों पर इस वेब पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन टेली-कन्सल्टेशन सेवाएं मरीजों को दी जा रही हैं।

'मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना' से किस तरह लोग लाभान्वित हो रहे हैं ?

प्रदेशवासियों को 2 अक्टूबर 2011 को 'मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना' तो मिल गई लेकिन इलाज के दौरान जांच में होने वाला खर्चा उनके लिए सबसे बड़ी चिंता बनकर उभरा। सरकार ने आमजन की पीड़ा को महसूस करते हुए प्रदेश भर में 7 अप्रैल 2013 से 'मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना' का आगाज चरणबद्ध तरीके से करना शुरू कर दिया। शुरुआत में इस दायरे में कम जांचें थी लेकिन धीर-धीरे इसमें अन्य महंगी जांचों को भी जोड़कर इसे और अधिक मजबूत किया गया। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के अन्तर्गत मेडिकल कॉलेजों से जुड़े अस्पताल 933, जिला, उप जिला एवं सेटेलाइट-817, सीएचसी-627, पीएचसी-410, सब सेंटर-49 में निःशुल्क दवाएं उपलब्ध करवाई जा रही है। एक वर्ष में 11 करोड़ से ज्यादा मरीजों को राजकीय चिकित्सालयों में परामर्श दिया गया।

प्रदेश सरकार के दो वर्ष हाल ही में पूर्ण हुए हैं, सरकार की क्या उपलब्धियां रही हैं ?

सरकार में आने से पहले हमने अपने घोषणा पत्र में राजस्थान की जनता से 500 वादे किए थे। इन दो वर्ष में जिसमें कोरोना का वर्ष भी सम्मिलित है, जो कि विषम परिस्थिति थी। फिर भी सरकार ने विकास की गति को रुकने नहीं दिया और हमारी सरकार ने करीब 252 वादे दो वर्ष में पूर्ण किए। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत अपने पहले कार्यकाल से ही चुनावी घोषणा पत्र को सरकार की कार्ययोजना का हिस्सा बनाकर वादों को पूर्ण करने का काम करते आ रहे हैं और हम इसी पर आगे बढ़ रहे हैं। फिर चाहे किसानों की कर्जमाफी हो या अन्य वादे।

कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन सामने आया है, प्रदेश इसको लेकर कितना सतर्क है ?

कोरोना के प्रति हम पहले दिन से ही सतर्क हैं। लोगों को लगातार जागरूक किया गया और जनजागरूकता अभियान के तहत एक करोड़ से अधिक निःशुल्क तौर पर मास्क का वितरण भी किया गया। सरकार ने फैसला लेकर त्यौहारों पर विशेष सतर्कता बरती और कोरोना की सभी गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराया। मास्क को लेकर कानून बनाने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य रहा। कुछ दिनों पहले ब्रिटेन सहित कुछ यूरोपियन देशों में कोरोना का नया स्ट्रेन मिलने की सूचना भी मिली है। हालांकि राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में नए स्ट्रेन ने दस्तक दे दी है। राज्य सरकार इस बारे में पूर्णतया सजग और सतर्क है। सरकार की आमजन से यही अपील है कि वे पूर्व की भांति सजग रहें और सावधानी बरतते हुए जीवनशैली को रखें। हम सावधान रहेंगे तो ही कोरोना हारेगा।

आगामी दिनों में कोरोना वैक्सीन जरूरतमंदों तक पहुंचाने के लिए सरकार की क्या व्यवस्था है ?

राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजनाओं में टीकाकरण काफी समय से होता रहा है। राजस्थान ने टीकाकरण का लक्ष्य 89 फीसदी तक पूरा किया है। कोविड वैक्सीन के लिए राज्य सरकार ने प्रदेश के 7 जिलों में 18 सेंटर्स पर 2 जनवरी को कोरोना वैक्सीनेशन का ड्राई रन (मॉक ड्रिल) किया है। इन सभी सेंटर्स पर वैक्सीनेशन के पश्चात होने वाले संभावित सामान्य प्रतिकूल प्रभावों एवं कोविड प्रोटोकॉल नियमित रूप से फोलो करने के बारे में जानकारी दी गई। प्रदेश के चयनित सेंटर्स पर कुल 424 लाभार्थियों पर ड्राई रन किया गया। अब 8 जनवरी को संपूर्ण प्रदेश में 33 जिलों के 102 सेंटर्स पर ड्राई रन किया गया है। हमारा यह कोविड वैक्सीन को लेकर रिहर्सल था, जो कि सफल रहा। 16 जनवरी से प्रथम चरण में होने वाले टीकाकरण में 4.5 लाख लोगों को टीका लगाया जाएगा। सरकार ने सभी जरूरी तैयारियां पूरी कर ली हैं।

रिफाइनरी से होगा प्रदेश का विकास

- गुलाब बत्रा

अपार बालुका राशि से आच्छादित राजस्थान का पश्चिमी हिस्सा शताब्दियों पहले सागर की विशाल तरंगों की क्रीड़ा का साक्षी रहा। कालचक्र में इस इलाके की वन संपदा बालुका राशि के दबाव एवं गर्मी के प्रभाव से पेट्रोलियम पदार्थों के रूप में परिवर्तित होती गई। भू-विज्ञानियों ने इस काले सोने की खोज का मार्ग प्रशस्त किया। आधुनिक तकनीक की मदद से प्रकृति की कला की इस सौगात ने प्रदेश की समृद्धि के द्वार खोल दिए हैं।

अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे थार मरुस्थल के सीमांत जिले बाड़मेर-जैसलमेर और अब बीकानेर-नागौर तक तेल एवं प्राकृतिक गैस की खोज एवं दोहन का कार्य प्रगति पर है। वेनेजुएला में भू-विज्ञानियों के अनुसंधान से प्राप्त निष्कर्ष से थार मरुस्थल में लगभग 70 करोड़ वर्ष पहले की चट्टानों में तेल एवं गैस के विपुल भंडार की संभावना जताई गई है। जोधपुर स्थित जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय की जे.एन.वी.यू. जियोलॉजी एलुमनाई एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री अयोध्या प्रसाद गौड़ के अनुसार थार रेगिस्तान में हाइड्रो कार्बन की कहानी अपने प्रारम्भिक चरण में है। बाड़मेर-जैसलमेर-बीकानेर के अलावा बिलाड़ा-जोधपुर फार्मेशन में भी खनिज तेल एवं गैस की संभावना वाले क्षेत्र चिह्नित किए गए हैं।

थार मरुस्थल के गर्भ में छिपे अकूत खजाने के दोहन से अर्जित खनिज तेल का शोधन करने के लिए मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने सीमावर्ती बाड़मेर जिले में रिफाइनरी लगाने का सपना संजोया था। उन्होंने 2 मई, 2012 को ओ.एन.जी.सी. के अधिकारियों से चर्चा के दौरान एच.पी.सी.एल. के सहयोग से नौ मिलियन टन क्षमता की रिफाइनरी स्थापित किए जाने की इच्छा व्यक्त की। एच.पी.सी.एल. प्रबन्धन ने दिल्ली में 6 मार्च, 2013 को पहले बाड़मेर जिले के लीलाणा में रिफाइनरी लगाने की स्वीकृति दी और एक सप्ताह पश्चात् 14 मार्च, 2013 को जयपुर में मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की उपस्थिति में रिफाइनरी लगाने सम्बन्धी समझौता पत्र (एम.ओ.यू.) पर हस्ताक्षर किए गए। राजस्थान के तत्कालीन खान एवं पेट्रोलियम विभाग के शासन सचिव श्री सुधांश पंत ने और हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (एच.पी.सी.एल.) के निदेशक (रिफाइनरी) श्री के. मुरली ने समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए। बाड़मेर जिले में खनिज तेल कुओं की खुदाई के दौरान मिले तेल और इसके विपुल भण्डार के अनुमान के मद्देनजर रिफाइनरी की संभावना बलवती हुई। मुख्यमंत्री श्री गहलोत की पहल पर तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने बाड़मेर में खनिज तेल के व्यावसायिक उत्पादन का श्रीगणेश किया। दरअसल तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (ओ.एन.जी.सी.) ने राजस्थान सरकार को बाड़मेर जिले में तेल शोधक कारखाना (रिफाइनरी) लगाने का प्रस्ताव दिया था। रिफाइनरी की क्षमता और राज्य सरकार की हिस्सेदारी तथा एच.पी.सी.एल. के साथ हुए समझौते पर मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की पहल पर यूपीए चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी ने 23 सितम्बर, 2013 को रिफाइनरी का शिलान्यास किया।

तीसरी बार राज्य की बागडोर संभालने वाले मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने रिफाइनरी एवं पेट्रोलियम हब के अपने ''ड्रीम प्रोजेक्ट'' को पूरा करने का संकल्प दोहराया। यही नहीं, उन्होंने स्वयं इस परियोजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मॉनिटरिंग अपने हाथ में लेने की पहल की है।

राज्य विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट भाषण में मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि रिफाइनरी एवं पेट्रोकेमिकल कॉम्पलेक्स के निर्माण को समय पर पूरा कराने पर सरकार का फोकस हैं। इस परियोजना की कुल लागत 43 हजार 129 करोड़ रुपये है। इस हेतु गठित एच.पी.सी.एल. राजस्थान रिफाइनरी लि. कम्पनी में एच.पी.सी.एल. की 74 प्रतिशत एवं राजस्थान सरकार की 26 प्रतिशत भागीदारी है। इस रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स से प्रदेश में रोजगार के अवसरों में पर्याप्त बढ़ोत्तरी होगी। हमारा प्रयास रहेगा कि एच.पी.सी.एल. से नियमित फॉलो-अप एवं समन्वय करके जल्दी से जल्दी रिफाइनरी निर्माण कार्य को पूर्ण करवाएं। सात संकल्पों के सर्वकल्याणकारी बजट मे सातवां संकल्प कौशल व तकनीक प्रधान रखा गया है। बजट भाषण में यह भी कहा गया कि राज्य में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस के उत्पादन को बढ़ाने के लिए अन्वेषण की गतिविधियां बढ़ानी होंगी। दस पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन लाइसेंस (पी.ई.एल.) दिए हैं एवं आगामी वर्ष में तीन पी.ई.एल. ओर स्वीकृत किए जाएंगे। अन्वेषण एवं उत्पादन से सम्बन्धित कार्यों को शीघ्रता से संपादित करने के लिए बाड़मेर जिले में उप निदेशक (पेट्रोलियम) कार्यालय खोला जाएगा तथा विशेषज्ञों की सेवाएं ली जाएंगी। रिफाइनरी परियोजना में रोजगार के अवसर बढ़ाने हेतु जोधपुर व पचपदरा में हाइड्रोकार्बन सेक्टर की विभिन्न स्किल्स में प्रशिक्षण देने के लिए डेडीकेटेड कौशल केन्द्र स्थापित किए जाएंगे।

मुख्यमंत्री ने रिफाइनरी के निर्माणाधीन कार्यों का अवलोकन करते हुए पचपदरा में आयोजित बैठक में बिन्दुवार समीक्षा की। निर्माण कार्यों की तकनीकी गुणवत्ता पर विशेष ध्यान रखने के निर्देश के साथ उन्होंने भरोसा दिया कि आवश्यक संसाधनों की आपूर्ति में किसी तरह की कमी नहीं आने दी जाएगी। पचपदरा में रिफाइनरी के लिए राजस्व विभाग ने दस हजार बीघा से अधिक जमीन आवंटित की है जिस पर निर्माण कार्य प्रगति पर है। राज्य सरकार द्वारा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा केन्द्र सरकार के रसायन, पेट्रोरसायन विभाग को भेजे गए विस्तृत प्रस्ताव से रिफाइनरी की स्थापना से पश्चिमी राजस्थान के उज्ज्वल भविष्य की भावी तस्वीर की चमक दिखाई देने लगी है। इसके अन्तर्गत रिफाइनरी के लगभग 250 वर्ग किलोमीटर के परिक्षेत्र में पेट्रोकेमिकल्स एण्ड पेट्रोकेमिकल इन्वेस्टमेंट रीजन (पीसीपीआईआर) विकसित किए जाने का मार्ग प्रशस्त हो गया है।

इस परिक्षेत्र में बड़े उद्योगों की स्थापना के लिए करीब एक सौ वर्ग किमी के दायरे में प्रोसेसिंग एरिया चिह्नित किया गया है जिसमें लगभग एक लाख करोड़ रुपये का निवेश आने का अनुमान लगाया गया है। पी.सी.पी.आई.आर. की स्वीकृति मिलने पर बाड़मेर का यह परिक्षेत्र अपनी बेहतर स्थिति के फलस्वरूप गुजरात, ओड़िसा, तमिलनाडु, आन्धप्रदेश के पीसीपीआईआर के समकक्ष आ सकता है। इससे कई गुना रोजगार की उपलब्धता के साथ विमान रेल, सड़क सम्पर्क के विस्तार सहित निर्यात के नये द्वार खुलेंगे। रिफाइनरी के निकट अमृतसर, जामनगर एक्सप्रेस के द्वारा कांडला बंदरगाह तक आसान पहुंच होगी।

राजस्थान के एक दर्जन से अधिक जिलों के करीब डेढ़ लाख वर्ग किलोमीटर परिक्षेत्र के भूगर्भ में पेट्रोलियम पदार्थों की उपलब्धता का अनुमान लगाया गया है। इन्हें मुख्य रूप से चार पेट्रोलियम बेसिन मे विभक्त किया गया है। इनमें बाड़मेर सांचोर बेसिन प्रमुख है जिसमें बड़े पैमाने पर खनिज तेल के साथ प्राकृतिक गैस का भी दोहन हो रहा है। जैसलमेर बेसिन में गैस दोहन से विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। बीकानेर-नागौर बेसिन में इन दोनों जिलों सहित श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू जिले सम्मिलित हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम ओएनजीसी को तीन साल के लिए आवंटित ब्लॉक में बीकानेर जिले मे 2118 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में तेल एवं प्राकृतिक गैस की खोज की जानी है। बीकानेर-नागौर ब्लॉक के सियासर क्षेत्र में ऑयल इण्डिया पिछले एक साल से तेल गैस की खोज में जुटी है। विंध्यान बेसिन में हाड़ौती अंचल के कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ तथा भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ शामिल हैं।

बी एच 6 मानक की देश की इस पहली रिफाइनरी से सवा सौ से अधिक प्रकार के उत्पाद मिलेंगे जिनसे लगभग पांच सौ छोटे-मोटे उद्योग लगने की संभावना जताई गई है। बहरहाल बाड़मेर रिफाइनरी देश के 15 राज्यों में 26वीं रिफाइनरी का दर्जा हासिल करेगी।

हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार पश्चिमी राजस्थान ने देश के सबसे महत्त्वपूर्ण हाइड्रोकार्बन ब्लॉक्स के रूप में अपनी पहचान बनाई है। खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस के नए क्षेत्रों की खोज में पश्चिमी राजस्थान अग्रणी स्थान पर है। इस परिक्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियों को उत्खनन के लिए सर्वाधिक ब्लॉक्स की पेशकश की गई है।

निजी क्षेत्र में बाड़मेर-सांचोर बेसिन भारत का सबसे बड़ा तेल उत्पादक बेसिन माना गया है। नई अन्वेषण नीति के फलस्वरूप बाड़मेर जिले में सात नये ब्लॉक्स में लगभग दो हजार करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है। बाड़मेर जिले में पहले निजी क्षेत्र की कंपनी केयर्न एनर्जी, फिर केयर्न इंडिया और वेदांता समूह से जुड़ाव के पश्चात् केयर्न ऑयल एण्ड गैस, वेदांता लि. अब जैसलमेर में भी तेल एवं गैस खोज का कार्य आरम्भ करेगी। कम्पनी ने वर्ष 2004 में जब मंगला तेल क्षेत्र की खोज की तो इसे भूगर्भ तेल विस्तार की दृष्टि से विश्व के सबसे बड़े तेल क्षेत्र के रूप जाना गया। इसी तरह पिछले 25 वर्षों के इतिहास में भारत की यह पहली विशाल तेल खोज मानी गई। वर्ष 2009 में मंगला वाणिज्यिक उत्पादन आरम्भ हुआ। हाल ही में इसकी 11वीं वर्षगांठ पर मुख्यमंत्री ने बधाई संदेश में कहा कि प्रदेश में ऑयल एवं गैस की खोज और उत्पादन में विशेषतौर से पश्चिमी राजस्थान की जीवन रेखा बनकर उभरा है।

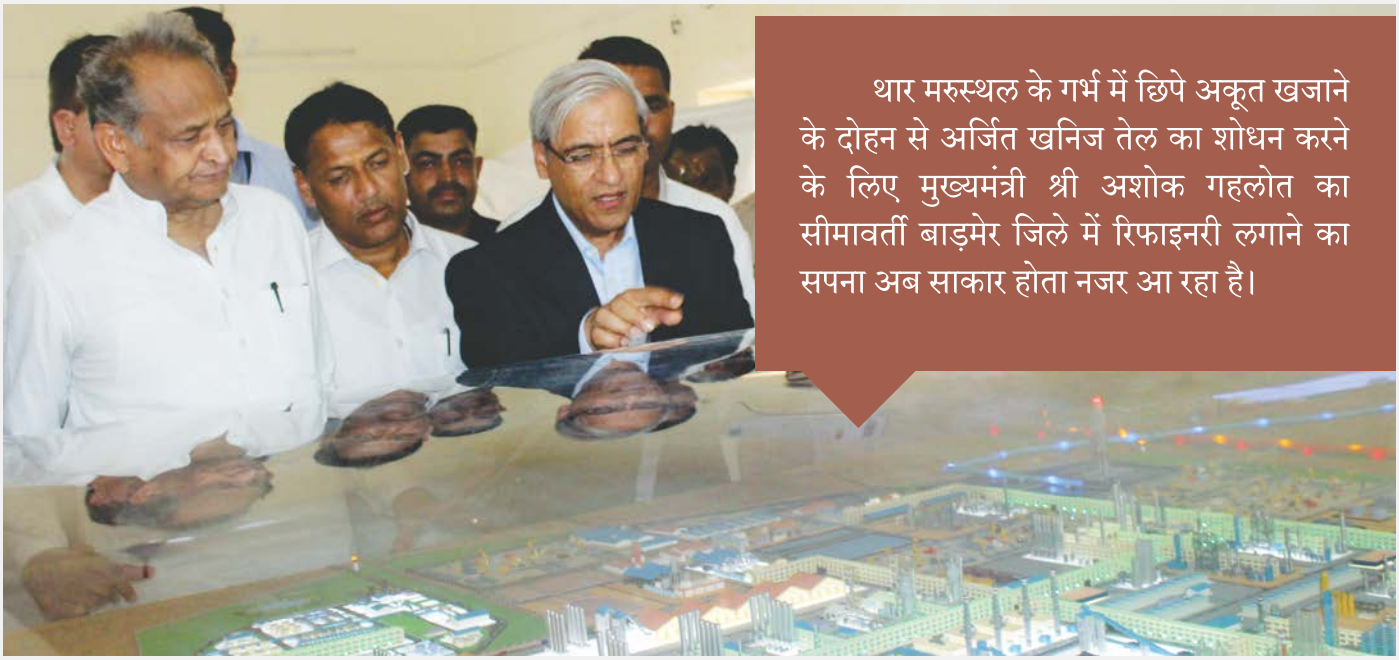

थार मरुस्थल के गर्भ में छिपे अकूत खजाने के दोहन से अर्जित खनिज तेल का शोधन करने के लिए मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत का सीमावर्ती बाड़मेर जिले में रिफाइनरी लगाने का सपना अब साकार होता नजर आ रहा है।

पिछले ग्यारह वर्षों में करीब साठ हजार करोड़ के निवेश से मरुधरा की तस्वीर और तकदीर बदल रही है। एक ओर आर्थिक विकास के नये द्वार खुले हैं और दूसरी तरफ हजारों करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की बचत हो रही है। मुख्यमंत्री ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि खनिज तेल का अधिक उत्पादन बढ़ाने के लिए एनहांस ऑयल रिकवरी एवं एनकेलाइन सर्फेक्टेंट पॉलीमर जैसी अन्तरराष्ट्रीय स्तर की आधुनिकतम तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। मंगला सहित भाग्यम और ऐश्वर्या तेल क्षेत्र में भी इसी तकनीक का उपयोग हो रहा है। विश्व में केवल बाड़मेर में बड़े पैमाने पर यह तकनीक अपनाई गयी है। विशेष प्रकार के रसायन की सहायता से भूगर्भ की चट्टानों से खनिज तेल को बाहर निकाला जाता है।

बाड़मेर में खोजे गए 38 तेल क्षेत्र के फलस्वरूप यह देश में अग्रणी है। अब तक लगभग तीन सौ कुओं की खुदाई की गई है। अगले वर्ष तक तीन हजार वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र को सम्मिलित कर कुओं की संख्या पांच सौ होने का अनुमान है। केयर्न के 38 तेल क्षेत्रों में से अब तक 16 में अनुमानित 161 करोड़ बैरल के भंडार में से 51 करोड़ बैरल तेल निकाला जा चुका है। 22 तेल क्षेत्रों में तत्सम्बन्धी प्रक्रिया पूरी होने एवं अनुमति मिलने पर उत्खनन किया जाएगा।

प्राकृतिक गैस दोहन में भी राजस्थान छलांग लगाने की स्थिति में है। गुड़ामलानी स्थित राजेश्वरी तेल क्षेत्र में रागेश्वरी गैस टर्मिनल का विस्तार कार्य पूरा होने पर प्रतिदिन 75 करोड़ घनफिट प्राकृतिक गैस उत्पादन का मार्ग प्रशस्त हो गया है।

इसमें से 50 लाख घनफिट प्राकृतिक गैस नये गैस क्षेत्रों और 25 करोड़ घनफिट गैस मंगला तथा अन्य छोटे तेल क्षेत्रों से संलग्न गैस के रूप मे प्राप्त की जाएगी। राजेश्वरी क्षेत्र में तीन ट्रिलियन घनफिट गैस का भंडार उपलब्ध है। वर्तमान में राजेश्वरी से औसतन साढ़े पांच करोड़ घन फीट गैस उत्पादित हो रही है।

अपने खनिज तेल भण्डारों के फलस्वरूप राजस्थान तीसरी से प्रथम श्रेणी का दर्जा प्राप्त कर चुका है। तेल दोहन की दृष्टि से राजस्थान मुम्बई हाई, असम एवं गुजरात की बराबरी पर आ गया है। निजी क्षेत्र में तेल उत्पादन के साथ ही सरकारी क्षेत्र में भी खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस की खोज तथा उत्खनन प्रगति पर है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार ऑयल इंडिया ने अगले चार वर्षों में बीकानेर-नागौर बेसिन में 15 नए कुओं की खुदाई से प्रदेश में रोजाना 150 बैरल के स्थान पर 700 बैरल तेल उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसी तरह जैसलमेर जिले में डेढ़ दर्जन कुंओं से प्रतिदिन सात मिलियन मीट्रिक स्टैंडर्ड क्यूविक मीटर प्राकृतिक गैस का उत्पादन किया जा रहा है।

सीमावर्ती जैसलमेर जिला सौर ऊर्जा के साथ पवन ऊर्जा उत्पादन में भी तेजी से आगे बढ़ा है। थार मरुस्थल की इस सुनहरी नगरी को अब पंखा नगरी भी कहा जाने लगा है। पश्चिमी अन्तर्राष्ट्रीय सीमा को सौर ऊर्जा से रोशन करने के उद्देश्य से अल्ट्रा मेगा रिन्युअल एनर्जी पॉवर पार्क विकसित किया जाएगा। इसके लिए लगभग आठ हजार मेगावाट क्षमता के सौर एवं पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। बाड़मेर जिले में तेल एवं गैस भंडारों के समुचित दोहन तथा रिफाइनरी के साथ पेट्रोलियम केमिकल्स एवं पेट्रोकेमिकल्स हब की स्थापना से भावी परिदृश्य का अनुमान लगाया जा सकता है। विश्व हाइड्रोकार्बन मानचित्र पर अपनी गौरवपूर्ण उपलब्धियों से बाड़मेर ने विशिष्ट पहचान बना ली है। राजस्थान सरकार की राजस्व आय में तेजी से वृद्धि के साथ इस सीमांत जिले की अर्थव्यवस्था में नये आयाम जुड़ रहे हैं।

खनिज तेल के साथ अर्थव्यवस्था को गति देने में पश्चिमी राजस्थान अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आने वाले वर्षों में तेल परिशोधन (रिफाइनिंग) क्षमता को भी दोगुना करने की योजना क्रियान्वित की जा रही है।

प्रदेश में नए आयाम स्थापित कर रही है तकनीकी शिक्षा

- गजाधर भरत

प्रदेश के युवाओं को रोजगार के अवसर सुलभ कराने के उद्देश्य से तकनीकी शिक्षा राज्य (स्वतंत्र प्रभार) मंत्री डॉ. सुभाष गर्ग के नेतृत्व में सत्र 2020-21 से 18 पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में विद्यमान शाखाओं की क्षमता को बढ़ाकर व्यवसायोन्मुखी नवीन ब्रांच-रोबोटिक्स, मैकेट्रॉनिक्स, साइबर फोरेंसिक इन्फोर्मेशन तथा तीन अभियांत्रिकी महाविद्यालयों में आर्टिफिसियल इन्टेलीजेन्स एण्ड डाटा साइंस, मशीन लर्निंग व इन्टरनेट ऑफ थीन्गस प्रारंभ किए गये हैं। अल्पावधि के कोर्स जैसे-ऑटोकैड, रेफ्रिजरेशन, अनुरक्षण आदि विषयों के कोर्स भी प्रारंभ किये गये हैं। तकनीकी शिक्षा को रोजगारपरक बनाने की दिशा में औद्योगिक क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ सीआईआई के प्रतिनिधियों तथा एआईसीटीई के साथ साझा प्रयास जारी हैं। समस्त पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में आई.आई.आई. (इन्डस्ट्री इन्स्टीट्यूट इन्ट्रेक्शन) सेल में स्टूडेंट एडवाइजरी एवं गाइडेंस ब्यूरो प्रारंभ किए गये हैं।

''आनंदम'' - एक अनूठी पहल

युवा पीढ़ी को मानवीय मूल्यों और आदर्शों के प्रति शिक्षित किए जाने की महत्ती आवश्यकता है। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने महात्मा गांधी के ट्रस्टीशिप के सिद्धांत से प्रेरित हो कर समस्त विद्यार्थियों के लिये आनंदम नाम से एक नया अनिवार्य विषय उच्च व तकनीकी शिक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल किया है। यह विषय यंत्रवत् व मशीनी शिक्षा के पुस्तकीय ज्ञान पर आधारित न हो कर वास्तव में कार्य करने से सम्बधित है। आनंदम में विद्यार्थी सामुदायिक सेवा के सामूहिक परियोजना कार्य करेंगे और विभिन्न सामुदायिक समस्याओं के वास्तविक हल खोजेंगे। यह राज्य की अनूठी पहल है और राजस्थान ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य है।

नैनो टेक्नोलॉजी, रोबॉटिक्स व ऑटोमेशन के सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस

टेक्वीप-3 योजनान्तर्गत प्राप्त निधि का उपयोग मार्च 2019 तक मात्र 18 प्रतिशत हुआ था जो अब 78 प्रतिशत पहुंच गया है। कार्यक्रम

युवा पीढ़ी को मानवीय मूल्यों और आदर्शों के प्रति शिक्षित किए जाने की महत्ती आवश्यकता है। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने महात्मा गांधी के ट्रस्टीशिप के सिद्धांत से प्रेरित हो कर समस्त विद्यार्थियों के लिये आनंदम नाम से एक नया अनिवार्य विषय उच्च व तकनीकी शिक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल किया है।

के अन्तर्गत मार्च 2019 की विभाग की उपलब्धि 32 प्रतिशत से बढ़कर 69 प्रतिशत हो गई है। गेट-2020 परीक्षा में सफलता गत वर्ष की तुलना में 6 प्रतिशत बढ़ कर राज्य फोकस स्टेट्स की श्रेणी में आ गया है। राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा में टेक्वीप-3 के अंतर्गत लगभग 3 करोड़ की लागत से नैनो टेक्नोलॉजी, रोबॉटिक्स एवं ऑटोमेशन के सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस की स्थापना की जा रही है। राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा द्वारा लगभग 1.5 करोड़ के 64 कॉलेब्रेटिव रिसर्च प्रोजेक्ट सम्बद्ध महाविद्यालयों को मेरिट के आधार पर आवंटित किये गए है। 40 हजार ई-लेक्चर्स यूट्यूब चैनल्स के माध्यम से विद्यार्थियों को एक्सेस कराने के साथ ही अकादमिक डिग्री, अंकतालिकायें, प्रमाण पत्र इत्यादि दस्तावेज ऑनलाइन ही सहज उपलब्ध कराये जा रहे हैं।

सर्वपल्ली राधाकृष्णन भवन

स्वायत्त शासन मंत्री श्री शान्ति धारीवाल के मुख्य आतिथ्य में तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री डॉ. सुभाष गर्ग ने हाल ही में 4 दिसम्बर को राजस्थान तकनीकी शिक्षा विश्वविद्यालय, कोटा परिसर में 2 करोड़ की लागत से तैयार सर्वपल्ली राधाकृष्णन् भवन का ऑनलाइन उद्घाटन किया। विश्वस्तरीय कैफेटेरिया तथा पुस्तकालय निर्माण की और अग्रसर यह तकनीकी सदन निश्चित रूप से प्रदेश में तकनीकी शिक्षा को नया विस्तार देने में अहम् भूमिका निभायेगा।

नवाचारों से बढ़ा राजस्थान पुलिस के प्रति विश्वास

–गोविन्द पारीक

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पहल पर राजस्थान पुलिस में किये गये नवाचारों के परिणामस्वरूप आमजन में पुलिस के प्रति विश्वास निरन्तर बढ़ रहा है एवं पुलिस की छवि को पब्लिक फ्रेन्डली बनाने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं। आमजन अपनी पुलिस सम्बन्धी समस्या लेकर पूरे विश्वास के साथ पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाने के लिए आ सके, ऐसा भयमुक्त वातावरण बनाया जा रहा है। थानों में पारदर्शिता लाने के लिए आगामी दो वर्षों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की कार्यवाही भी प्रगति पर है।

राजस्थान पुलिस के ध्येय वाक्य ''आमजन में विश्वास, अपराधियों में भय'' के अनुरूप अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। राजस्थान पुलिस द्वारा अपराधों पर लगाम लगाने के लिए प्रदेश की जनता की सक्रिय सहभागिता पर विशेष बल दिया जा रहा है। फरार अभियुक्तों की धरपकड़ तथा अपराधियों के विरुद्ध की जा रही सख्त कार्यवाही के भी सार्थक परिणाम नजर आने लगे हैं।

पुलिस को पब्लिक फ्रेन्डली बनाने के लिए कम्युनिटी लाइजन ग्रुप में कम्प्युनिटी के प्रभावशाली तथा समर्पित लोगों को शामिल कर इसे प्रभावी बनाने के लिए व्यापक प्रयास किये जा रहे हैं। स्टूडेन्ट पुलिस कैडेट योजना को एक हजार विद्यालयों में प्रारम्भ किया गया है। इसके लिए जिला शिक्षा अधिकारियों तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकों का समन्वित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा चुका है। राजस्थान पुलिस द्वारा प्रारम्भ पुलिस मित्र योजना के तहत 24 श्रेणियां जैसे- अपराध नियंत्रण, जनजागरुकता, यातायात नियंत्रण, मानवाधिकार, पर्यावरण संरक्षण, साम्प्रदायिक सद्भाव, रात्रि गश्त एवं महिला अधिकार जागरूकता आदि में से किन्हीं 3 गतिविधियों में रुचि रखने वाले नागरिक को पुलिस मित्र बनने के पात्र हैं। इस योजना के तहत नवम्बर, 2020 तक कुल 29 हजार 434 पुलिस मित्र बनाये जा चुके हैं। अपराधों की रोकथाम व पुलिस के कार्यों में पुलिस का सहयोग करने के उद्देश्य से राजस्थान पुलिस द्वारा ग्राम रक्षक सूचीबद्ध किये गये हैं। प्रत्येक राजस्व ग्राम में शारीरिक एवं मानसिक रूप से उपयुक्त स्थानीय ग्रामवासी को ग्राम रक्षक के रूप में सूचीबद्ध किया जा रहा है। नवम्बर, 2020 तक राज्य में 33 हजार 847 ग्राम रक्षक सूचीबद्ध किये जा चुके हैं।

प्रदेश में प्रारम्भ निर्बाध पंजीकरण की व्यवस्था से महिलाओं और बालिकाओं सहित समाज के कमजोर वर्ग की सुगमता से सुनवाई सुनिश्चित की जा रही है। निर्बाध पंजीकरण की नीति से दर्ज अपराधों की संख्या में वृद्धि हुई है लेकिन इस नीति से परिवाद दर्ज कराने का हौसला और पुलिस की कार्यवाही में विश्वास निरंतर बढ़ रहा है। इसका प्रमाण है दुष्कर्म के प्रकरणों में पूर्व में 30 प्रतिशत से भी ज्यादा प्रकरण कोर्ट के माध्यम से दर्ज होते थे लेकिन अब इनकी संख्या लगभग 13 प्रतिशत रह गयी है। थाने में एफआईआर दर्ज नहीं होने पर एसपी कार्यालय में एफआईआर दर्ज कराने की व्यवस्था शुरू कर दी गयी है। अब तक 199 प्रकरणों का पंजीकरण एसपी ऑफिस में किया जा चुका है। न्याय दिलाने के लिए त्वरित और गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान पर विशेष बल दिया जा रहा है। दुष्कर्म के प्रकरणों में औसत अनुसंधान समय लगभग 278 दिन से घटकर लगभग 113 दिन हो गया है।

पुलिस थानों पर आने वाले परिवादियों को सौहार्द्रपूर्ण वातावरण उपलब्ध कराते हुए उनकी समस्या सुनने व निवारण करने की दिशा में प्रत्येक पुलिस थाने पर एक स्वागत कक्ष बनाने का निर्णय लिया गया। अब तक 572 जगह स्वागत कक्ष निर्माण की स्वीकृति प्राप्त हुई है, जिसमें से 240 स्वागत कक्ष का कार्य पूर्ण हो चुका है एवं 248 कक्ष निर्माणाधीन हैं। परिवादों को सीधे सी.सी.टी.एन.एस. में पंजीकृत करने के थानों को निर्देश जारी करने के साथ-साथ परिवादियों को राजकॉप सिटीजन एप के माध्यम से सीधे दर्ज कराने की भी सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इस प्रकार सी.सी.टी.एन.एस में परिवादों को सीधे ही पंजीकृत कर 01जुलाई, 2019 से 31 अक्टूबर, 2020 तक 6,77,288 परिवाद पंजीकृत कर 3,12,499 से अधिक प्रकरणों का तत्परता से निस्तारण किया गया। आमजन की सुविधा के लिए प्रत्येक जिले में वाट्सअप

हैल्पलाइन 01 जनवरी, 2020 से चालू की गई, जिसके तहत 31 अक्टूबर, 2020 तक प्राप्त 3255 शिकायतों में से 99.67 प्रतिशत प्रकरणों का निस्तारण किया गया है।

टॉप-10 योजना के तहत थाना, वृत्त, जिला, रेंज व राज्य स्तर पर 10-10 सक्रिय एवं वांछित अपराधियों के चिन्हिकरण व उन्हें गिरफ्तार कर कार्रवाई करने की योजना लागू की गई। वर्ष 2019 में इस योजना में लगभग 3114 अपराधियों को चिह्नित कर गिरफ्तार किया गया है एवं 01 जनवरी, 2020 से 30 नवंबर, 2020 तक 1,456 अपराधियों को चिह्नित कर गिरफ्तार किया गया है।

कोविड-19 के तहत लॉकडाउन के दौरान पुलिस, एसडीआरएफ, आरएसी आदि बलों द्वारा कानून-व्यवस्था ड्यूटियों के साथ-साथ चिकित्सा विभाग की सर्वे टीम के साथ डोर- टू-डोर सर्वे किया व कोरोना के दौरान बनाये गये क्वारंटीन सेन्टरों व आइसोलेशन केन्द्रों पर ड्यूटियां की। नागरिकों को घर-घर तक राशन सामग्री पहुंचाने में प्रशासन की सहायता की गई।

राज्य में मॉब लिंचिंग, ऑनर किलिंग/खाप पंचायत जैसे अपराधों पर अंकुश लगाने हेतु विशेष कानून लागू करने हेतु नवीन बिल लाया जाकर पास किए गए हैं, जो वर्तमान में राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु लंबित हैं। राज्य एवं जिला स्तर पर गंभीर व जघन्य अपराधों के अनुसंधान एवं ट्रायल के निकट पर्यवेक्षण हेतु Heinous Crimes Monitoring Unit (HCMU) स्थापित की गई है। युवा वर्ग में नशे के प्रचलन को कम करने हेतु प्रदेश में हुक्का बार पर पूर्ण प्रतिबंध हेतु कानून में संशोधन किया गया है।

महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों की रोकथाम एवं उनकी सुरक्षा हेतु महिला गरिमा हेल्प लाइन, वाट्सअप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, राजकोप सिटीजन एप, सीसीटीवी कैमरों व अभय कमाण्ड सेन्टर से सतत निगरानी, एनजीओ से सहायता, महिला पुलिस पेट्रोलिंग यूनिट, One Stop Crisis Centre for Women (OSCCW) (28 जिलों में कार्यरत) Know your Student - Know your Police (KYS-KYP), महिला एवं बाल डेस्क तथा महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र। महिलाओं की सहायतार्थ एवं सुरक्षा हेतु राज्य के जिला अलवर एवं श्रीगंगानगर में एम.पी.वी. (महिला पुलिस कार्यकर्ता) योजना का पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चयन किया गया है। अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के लोगों के विरूद्ध होने वाली घटनाओं की शिकायत दर्ज कराने हेतु नि:शुल्क टोल फ्री नम्बर 18001806025 उपलब्ध है। नवाचारों एवं संवेदनशीलतापूर्वक की गई कार्रवाई का परिणाम है कि बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों के अनुसंधान का औसत समय 313 दिन से घटकर 126 दिन हो गया है। महिला डेस्क के सुदृढ़ीकरण हेतु राज्य के 500 पुलिस थानों का चयन किया जाकर प्रत्येक थाना हेतु एक लाख रुपये स्वीकृत किये गये हैं। महिलाओं एवं बालिकाओं को विषम परिस्थितियों में आत्मनिर्भर बनाने हेतु 01 जनवरी, 2020 से राज्य के समस्त जिलों में महिला शक्ति आत्मरक्षा केन्द्रों का शुभारंभ किया गया है। महिलाओं को आत्मरक्षा हेतु प्रशिक्षण नि:शुल्क दिया जा रहा है। 15 नवम्बर 2020 तक कुल 28 हजार 541 महिला/छात्राओं को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। महिला अत्याचार/बलात्कार के प्रकरणों में जागरुकता लाने, महिलाओं की सुरक्षा एवं उनके सम्मान, लैगिंक समानता विधिक जानकारी व महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति सजग रखने हेतु 13 अक्टूबर, 2020 से दिनांक 12 जनवरी, 2020 तक एक माह का विशेष अभियान ''आवाज'' (AAWAJ- Action Against Women Related Crime and Awareness for Justice) अभियान चलाया गया।

विशेष प्रवृत्ति के अपराधों की रोकथाम हेतु SOG में 2 विशेष अनुसंधान इकाइयाँ सृजित करने की घोषणा की गई। आर्थिक अपराधों के लिए Serious Fraud Investigation Unit (SFIU) एवं साइबर अपराधों के लिए Cyber Crime Investigation Unit (CCIU) की स्थापना की गई है। साथ ही इन यूनिटों के लिए तकनीकी विशेषज्ञों की सेवाएं प्राप्त करने की स्वीकृति भी जारी की गई है। जिला पुलिस अधीक्षक के निकटतम सुपरविजन में DST (District Special Team) का गठन किया गया है, जिनका पर्यवेक्षण राज्य स्तर पर अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, ए.टी.एस. एवं एस.ओ.जी. द्वारा किया जा रहा है।

राज्य सरकार से 5439 कांस्टेबल पदों की स्वीकृति प्राप्त होने पर विज्ञप्ति जारी कर ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित कर लिखित परीक्षा का आयोजन किया जा चुका है। लिखित परीक्षा का परिणाम जारी करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। उप निरीक्षक पुलिस भर्ती 2016 के विज्ञापित 511 पदों के विरूद्ध नियुक्ति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। कांस्टेबल से पुलिस निरीक्षक एवं मंत्रालयिक संवर्ग में कुल 6517 कर्मचारियों को पदोन्नति प्रदान की गई है एवं 87 पुलिसकर्मियों को उत्कृष्ट एवं उल्लेखनीय सेवाओं के लिए विशेष पदोन्नति दी गई है। अलवर जिले में से नवीन भिवाड़ी जिले का गठन, थानागाजी में नवीन वृत्त कार्यालय का सृजन व चूरू जिले में सुजानगढ़ में नवीन अपराध अन्वेषण शाखा की स्थापना की गई है । राजस्थान सरकार द्वारा राज्य में पुलिस थानों में पदस्थापित कांस्टेबल को अनुसंधान हेतु अधिकृत किया गया है। केन्द्रीय गृहमंत्री द्वारा राजस्थान पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, जोधपुर को अराजपत्रित अधिकारियों के लिए सम्पूर्ण भारत में सर्वश्रेष्ठ ट्रॉफी प्रदान की गई। केन्द्रीय गृहमंत्री द्वारा राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर को उत्तरी क्षेत्र में राजपत्रित अधिकारियों के लिए सर्वश्रेष्ठ ट्रॉफी प्रदान की गई। यह राजस्थान पुलिस की प्रशिक्षण व्यवस्था की उत्कृष्टता का दृष्टिगोचर है। विगत 2 वर्षों में किये गये नवाचारों से स्पष्ट है कि राजस्थान पुलिस निरन्तर उत्कृष्टता की ओर अग्रसर है एवं पुलिस को व्यापक रूप से पब्लिक फ्रेंडली बनाया जा रहा है।

राष्ट्रीय मतदाता दिवस–25 जनवरी

आस्था और विश्वास की गाथा

सशक्त मतदाता सशक्त लोकतंत्र

डॉ. सुधीर सोनी

भारत ! यह एक देश का नाम ही नहीं , अपितु पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा और विश्वास की गाथा है। विरासत, संस्कृति , सरोकारों और मनुष्यता की पूरी परंपरा और परिधि का नाम भी भारत है । विश्व पटल भर कहीं भी भारत का नाम पुकारा जाता है तो पूरे विश्व में यह नाम नवोन्मेष और सार्थकता का प्रतीक बनता है । समेकित विकास के सभी पक्ष , जीवन की गुणवत्ता के विविध आयाम , आम आदमी को खास बनाने के संसाधन मुहैया कराने वाली धरती की कहानी लोकतंत्र की व्यापकता से जुड़ी है । इस लोकतंत्र का सबसे खास पक्ष है चुनाव और मतदान । मतदान के माध्यम से आम आदमी अपनी भूमिका का उचित निर्वहन कर समाज और देश को नव आयाम देता है। यही वजह है कि भारत निर्वाचन आयोग ने अपने मतदाता जागरूक अभियान का हिस्सा ''सशक्त मतदाता, सशक्त लोकतंत्र'' से जोड़ा है ।

15 अगस्त, 1947 को गुलामी के अंधेरे से निकल कर प्रकाश की दिशा में अपना पहला कदम बढ़ाने वाला यह देश आज अपनी जींजीविषा और साधना के बल पर पूरे विश्व का मार्ग प्रशस्त कर रहा है । संविधान से लेकर मनुजता के सरोकारों की क्रियान्विति तक हर ओर समय की मांग के अनुरूप परिस्थितियों एवं परिप्रेक्ष्यों को परिष्कृत किया गया है । आज बदलते विश्व के साथ भारत में सामाजिक – सांस्कृतिक , आर्थिक – नैतिक , ऐतिहासिक – व्यावहारिक पहलुओं में भी निरंतर परिवर्तन आ रहे हैं । इन पक्षों में जहां हमें बदलते समय की मांग के अनुरूप अपने वर्चस्व को स्थापित करना है वहीं अपनी परंपरा व जड़ों के शाश्वत मूल्यों को भी बनाए रखना है । इन सभी पहलुओं में महत्त्वपूर्ण भूमिका है चुनाव की । पाँच वर्षों के अंतराल से होने वाले चुनावों के कारण ही देश को विविध नेतृत्व और नीतियों से परिचित होने का अवसर मिलता है । आवश्यकता इस बात की है कि देश का आम आदमी अपने लिए ऐसी सरकार चुने जो उसे सम्मानपूर्वक जीने के अधिकार के साथ आगे बढ़ने के विविध परिप्रेक्ष्य भी उपलब्ध करवा सके ।

भारत को विश्व के विविध आंदोलनों और महत्त्वपूर्ण घटनाओं से जुड़े रहने के कारण एक ऐसी नीति पर चलना होता है जो नीति एक ओर देश के उन्नयन के लिए सार्थक मार्ग प्रस्तुत करती हो और दूसरी ओर विश्व समुदाय के साथ भी कदम मिलाकर चल सके। देश की आजादी के साथ ही भारत को लोकतंत्र के रूप में चुनाव मिला किंतु दूसरी ओर उसके लिए बड़ी चुनौती थी कि वे भारत को गुलामी के पक्षों से उबार कर एक नई राह का अन्वेषण करें और आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक परिधियों से जोड़कर आम भारतीय को एक नई पहचान दिलाएं ।

भारत गांवों का देश है और गांवों की मुख्य पहचान खेती से है। अपनी आजादी के साथ ही भारत ने सशक्त मतदाता , सशक्त लोकतंत्र की दिशा में कार्य करना शुरू कर दिया । देश के विविध राजनीतिक दलों ने आगामी समय और संकल्पना को लेकर देश के मतदाताओं के सामने

अपनी – अपनी कार्ययोजनाएं प्रस्तुत की थी। भारत के आम मतदाता ने उनमें से अपने सपनों के अनुरूप भारत के भविष्य को चुना ।

भारत वह जगह है जहां के कण–कण में कला और संस्कृति के विविध पक्ष अपनी अभिनव पहचान के साथ कहीं भी देखे जा सकते हैं। इतिहास के विविध पन्नों को यहां आमजन के सामने जीवंत महसूस किया जा सकता है। इतिहास के उन गलियारों में जहाँ शौर्य, बलिदान, क्षमता, भक्ति, कला और संस्कृति के न जाने कितने अध्याय आज भी वक्त को अपने वजूद में आकार दिए हुए हैं उन्हें लोकतंत्र ने आकार दिया और आजाद भारत की एक नई तस्वीर दुनिया के सामने प्रस्तुत की। भारत की वैश्विक पहचान को भी लोकतंत्र ने दुनिया में स्थापित किया। भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखना उसका प्रमुख लक्ष्य था। लोकतंत्र की सबसे बड़ी चुनौती थी '' इक्कीसवीं सदी के भारत का निर्माण'' और इसी चुनौती को मतदाता सक्षमता के साथ सबसे दृढ़ आधार के रूप में निभाया गया। आजादी के बाद भारत की घरेलू और विदेश नीति को आकार देने में उनकी सक्रिय भूमिका रही। दृढ़ निश्चय और कर्मठता की मिसाल के रूप में भारत ने पोकरण में परमाणु बम का परीक्षण कर पूरी दुनिया के सामने अपनी सामरिक शक्ति का लोहा मनवाया, किंतु मानवता और विश्व शांति के लिए उसका जज्बा कम नहीं हुआ । परमाणु की ताकत को मनुष्यता के विकास की मुहिम का रंग देना भारत की अभिनव पहल थी । इस परीक्षण से भारतीय सेना का परचम और लहराया । साथ ही शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति ने देश को नव आयाम भी दिया ।

विविध बहुपक्षीय और द्विपक्षीय मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए देश के राजनेताओं ने हमेशा अपने कौशल और वाक्पटुता का परिचय दिया । भारत के प्रधानमंत्री के रूप में विविध नेता ऐसे राजनेता बनकर उभरे जो विश्व के प्रति अपनी उदारवादी सोच और लोकतांत्रिक मूल्यों एवं आदर्शों के लिए प्रतिबद्ध थे । उनका मानना था कि देश का सार्थक विकास तभी हो सकता है जब समाज और आम आदमी को सशक्तीकरण के व्यापक आयाम मिलें। वे सामाजिक समानता के समर्थक भी रहे। वे चाहते थे कि भारत एक दूरदर्शी, विकसित, मजबूत और समृद्ध राष्ट्र के रूप में आगे बढ़े । इस प्रयोजन हेतु उनका सबसे व्यापक प्रयोग था भारतीय लोकतंत्र में आम आदमी की पहुँच और उसका सबसे बड़ा मार्ग था निर्वाचन । किसी भी व्यक्ति का वोट महज एक अभिव्यक्ति नहीं है बल्कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी मुहिम में उसकी सहभागिता भी है ।

कभी वक्त इतिहास लिखता है और वही वक्त कभी अपनी पीढ़ियों के लिए इतिहास के हर पृष्ठ को समाज के सामने ले आता है ताकि पीढ़ियां जान सकें कि जिस कंगूरे पर वे गर्व कर रहे हैं उसकी नींव की ईंट ने कितने बलिदान अपने अंधियारे में छिपा रखे हैं । परिस्थितियां कैसी भी रही हों लेकिन भारत ने कभी हार नहीं मानी है । भारत को विश्वास है कि उसके सपूतों के बलिदान और त्याग व्यर्थ नहीं जाएंगे । आपाधापी और स्वार्थ के इस समाज में भले ही कुछ वक्त को भुला दिया गया हो लेकिन भारत के चप्पे – चप्पे पर लिखी कहानियों को कोई कैसे भुला सकता है ।

नए उदित होते और स्वर्णिम भारत को देखें तो इसकी विशेष पहचान के पीछे हमारे लोकतंत्र का ही हाथ है । भारत ने अपने लोकतंत्र की अवधारणा को ही समेकित विकास की अवधारणा बनाया। ''सबका साथ, सबका विकास'' के ध्येय वाक्य से प्रेरित होकर राजनीति में एक नव अध्याय की शुरुआत हुई। भारत में समावेशी, विकास के लिए प्रतिबद्ध, भ्रष्टाचार मुक्त शासन की शुरुआत हुई। अंत्योदय के उद्देश्य को साकार करने और समाज के सबसे वंचित छोर के व्यक्ति के लिए विकास के विविध आयामों को उपलब्ध कराने का निश्चय किया गया है। प्रमुख रूप से गरीबी मिटाने का उसका दृढ़ संकल्प है। इसका श्रेय विविध सरकारों द्वारा आम आदमी के हित के लिए किए गए फैसलों को जाता है। मतदान की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि जब यह भयमुक्त वातावरण में सरोकारों और विश्वास के साथ किया जाता है तो यह विश्वसनीय नेतृत्व के माध्यम से समाज को एक नव आयाम प्रदान करता है। आवश्यकता इस बात है कि लोकतंत्र में दृढ़ निष्ठा रखते हुए भारत के नागरिक अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं एवं स्वतंत्र, निष्पक्ष व शांतिपूर्ण निर्वाचनों की गरिमा को बनाए रखने तथा प्रत्येक निर्वाचन में निर्भय होकर मतदान करने की एतद्द्वारा प्रतिज्ञा लेते हैं तो हम देश को निर्विवाद रूप से न केवल सक्षम नेतृत्व प्रदान करते हैं बल्कि देश के सुनहरे भविष्य की नींव भी रखते हैं।

समाज और सभ्यता के लिए प्रेरक रहे हैं लोकतंत्र के विविध प्रयास, जो वैज्ञानिक तौर पर भले ही प्रयोग हों लेकिन वे मूलत: हमारे स्वप्न हैं जो हमें निरंतर एक वृहद दुनिया से जोड़ने का कारण बनते हैं । तमाम परिप्रेक्ष्य दर्शाता है कि यह स्वप्न और सत्य की साधना के बाद विकसित होने वाली परिधि का परिणाम है ।

समाज में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को लोकतंत्र में यह अधिकार है कि वे अपने जीवन को बेहतर पक्षों की ओर ले जाएं । अपनी मेहनत , लक्ष्य और लोक कल्याणकारी सरकार की नीतियों के माध्यम से वंचितों को उनका वाजिब हक दिलाने के साथ उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जा सकता है । लोग समाज की मुख्यधारा से जुड़ते हैं तो वे राष्ट्रनिर्माण की दिशा में अपना अभिनव योगदान दे सकते हैं । जब व्यक्ति अपने छोटे से घर में अपने स्वामित्व के साथ रहेगा तो उसमें जीवन के प्रति एक आस्था रहेगी । वह छोटा ही सही पर अपने घर में बड़े सपनों के साथ जी सकेगा । मानव संसाधन, तकनीकी विकास, वैज्ञानिक विकास, संस्कृति और परंपरा साथ में पूरी दुनिया को बेहतर आयाम देने की मुहिम इन सभी परिप्रेक्ष्यों को लेकर बदलता भारत न केवल विश्व का नेतृत्व करने को तैयार है बल्कि वैश्विक समाज को बेहतर मंच देने की मुहिम में अपना महत्त्वपूर्ण योगदान दे रहा है। ●

अपना पोषण - अपना आंगन

62 हजार आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से विकसित की गई पोषण वाटिकाएं

- कविता जोशी

राज्य सरकार ने निरोगी राजस्थान का संकल्प लिया है। बच्चे व महिलाएं परिवार की धुरी हैं और उनके पोषण पर ही समाज का स्वास्थ्य निर्भर करता है। इसका ध्यान रखते हुए प्रदेश के लगभग 62 हजार आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से सम्पूर्ण प्रदेश में आंगनबाड़ी केन्द्र के बच्चों, गर्भवती धात्री महिलाओं व किशोरियों के पोषण के लिए स्वादिष्ट व ताजी सब्जियां उपलब्ध कराने एवं कुपोषण से बचाव के लिए पोषण वाटिकाएं विकसित की गई हैं।

महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्रीमती ममता भूपेश ने निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएं, गांधीनगर, जयपुर में अमरूद, चीकू, नींबू, बील, आंवला, केला, अनार फलदार पौधों का आरोपण कर पोषण वाटिका का शुभारंभ किया।

पोषण अभियान के तहत प्रदेश के सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों पर न्यूट्री गार्डन विकसित किए गए। इन वाटिकाओं में भौगोलिक स्थिति और स्थान की उपलब्धता के अनुरूप फलों, सब्जियों, औषधियों एवं छायादार पौधों को लगाया गया। पोषण अभियान के नवाचार घटक के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा इन पोषण वाटिकाओं के विकास के लिए पौधों की खरीद एवं देखरेख के लिए 27 लाख 85 हजार के बजट का प्रावधान है। ग्रामीण क्षेत्रों में महात्मा गांधी नरेगा के समन्वय से व्यापक योजना तैयार कर न्यूट्री गार्डन (पोषण वाटिकाएं) तैयार किए गए हैं और शहरी क्षेत्रों में जहां चारदीवारी से घिरे हुए परिसर हैं, स्थान के अभाव में बड़े गमलों में पौधों को विकसित कर नवाचार के साथ वहां ग्रीन नेट रूफटॉप, वाटर हार्वेस्टिंग, टांका, सॉकपिट, ड्रिपसिस्टम जैसे नवाचार किए गए हैं।

इन पोषण वाटिकाओं से प्राकृतिक पोषण होगा और पोषण में पोषक तत्वों की बायो एवेबिलिटी भी अधिक होगी। पोषण वाटिकाओं के विकास में हर पौधे की अहमियत को ध्यान रख कर पौधारोपण किया

गया है। पोषण वाटिका की लाइव फेंसिग के लिए संतरें, करोंदे, मेहन्दी, नींबू जैसे पौधे रोंपे गए। जिन्हें सामान्यत: पशु नहीं खाते हैं। फलदार पौधों के चयन में पौष्टिकता का ध्यान रखा गया है। एक वर्ष में ही फलों की आवक हो जाए यह ध्यान में रखते हुए केला, पपीता, अनार, बेर के साथ-साथ आंवला, किन्नू, अमरूद, जामुन, बील के पौधे लगाए गए। वहीं मौसमी सब्जियों की पौध एवं क्यारियां तैयार की गई हैं, जिनमें लौकी, तोरई, टमाटर, पालक, धनिया, खीरा, ककड़ी, चौलाई, भिण्डी व मटर के पौधों को लगाया गया है। वहीं औषधीय पौधों में तुलसी, नीम, गिलोय, एलोवेरा, सहजन के पौधों का आरोपण कर पौष्टिकता एवं

औषधिय गुणों से भरपूर पोषण वाटिकाएं विकसित की गई हैं। पोषण वाटिकाओं के निर्माण में इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि जहां तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण पौधों के झुलसने की सम्भावना हो वहां पर क्यारियों के बीच में कुछ बाजरे जैसे पौधे भी लगाए जा सकें जिससे पौधों को नुकसान भी ना हो। इसी तरह कुछ जगहों पर गन्ना, ककड़ी, खरबूजा, तरबूज भी लगाए जाएंगे और बारहमासी सब्जियों को भी प्राथमिकता के आधार पर लगाया जाएगा।

पोषण वाटिकाओं के विकास के साथ ही ऑर्गेनिक वेस्ट को भी खाद के रूप में उपयोग किए जाने हेतु जगह की उपलब्धता के अनुरूप एक बड़ा गड्ढा बनाकर उसमें वेस्ट फल, फूल, पत्तियों, सब्जियों के छिलके एवं खाद्य अवशेष डालकर काम में लिया जाएगा। बारिश के पानी को रिचार्ज पिट या टांके में एकत्र करने के अतिरिक्त क्यारियों में भी काम में लिया जा रहा है।

इस योजना के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में महात्मा गांधी नरेगा तथा एन.आर.एल.एम. आदि योजनाओं के कन्वर्जेंस व समस्त क्षेत्रों हेतु पोषण से वित्तीय प्रावधान उपलब्ध हैं, जिससे जहां भी पोषण वाटिका का विकास संभव हो, वहां आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को सीधे ही उसके विकास के लिए राशि दी जाएगी। इसके अतिरिक्त दो दिवस के लिए श्रम विभाग द्वारा निर्धारित श्रमिकों को भी न्यूनतम राशि दी जा सकती है जिससे विकास कार्य करवाया जा सकें। इसके लिए जिला स्तर पर समस्त उपनिदेशक समेकित बाल विकास सेवाएं, महिला एवं बाल विकास जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा समस्त सीडीपीओ ब्लॉक स्तर पर बीडीओ से सम्पर्क कर महात्मा गांधी नरेगा तथा एन आर.एल.एम. आदि योजनाओं के कन्वर्जेंस से राशि लेकर सीडीपीओ अपने स्तर पर चयनित केन्द्रों पर ट्री गार्ड, ग्रीननेट, ड्रिप सिस्टम आदि क्रय कर सकते हैं। पोषण वाटिकाओं के उत्पादों का उपयोग आंगनबाड़ी लाभार्थियों, आंगनबाड़ी कर्मी के साथ जन समुदाय के लिए भी किया जाएगा।

जैसलमेर में चिकित्सा सेवाओं का विस्तार

- डॉ. दीपक आचार्य

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं तथा सुविधाओं के विस्तार एवं विकास में सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों के परिणाम सीमावर्ती जैसलमेर जिले में दिखाई दे रहे हैं। यहां लोक स्वास्थ्य रक्षा की दिशा में हो रहे कार्यों की बदौलत अब सकारात्मक बदलाव आ रहा है।

जैसलमेर में जिला प्रशासन की पहल पर आमजन की सेहत की सार-संभाल और चिकित्सा सेवाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए अथक प्रयास निरन्तर जारी हैं। इन्हीं प्रयासों के अन्तर्गत जैसलमेर जिला मुख्यालय स्थित जिले के सबसे बड़े अस्पताल श्री जवाहर जिला अस्पताल में न केवल मरीजों के लिए बल्कि उनके साथ आने वाले परिजनों के लिए भी जरूरी सेवाओं और सुविधाओं के लिए माकूल प्रबन्ध किए जा रहे हैं।

रंग लायी पहल

जिला अस्पताल के नवीनीकरण और चिकित्सा सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए किए गए प्रयासों के बाद अस्पताल का रंग-रूप निखर उठा है। मरीजों के बेहतर इलाज के लिए चिकित्सा स्टाफ के प्रबन्धों के साथ ही सेवाओं में व्यापक सुधार आया है। चिकित्सालय परिसर से लेकर विभिन्न वार्डों तक में सुकून का अनुभव होने लगा है। इसे न केवल मरीज बल्कि उनकी सेवा-सुश्रूषा और कुशलक्षेम पूछने आने वाले परिजन भी महसूस करने लगे हैं।

वरदान साबित हुआ यह निरीक्षण

जिला कलक्टर के जिले द्वारा इस सबसे बड़े अस्पताल के औचक निरीक्षण से यहां की जमीनी हकीकत से प्रशासन रूबरू हुआ। अस्पताल के सुधार, विकास एवं सेवाओं के विस्तार के लिए ठोस योजना का क्रियान्वयन किया गया। निरीक्षण में सामने आयी कमियों, समस्याओं, जरूरतों आदि पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर इसकी कार्ययोजना बनाई गई और पर्यवेक्षण के लिए अधिकारियों की टीम लगाई गई। अस्पताल को नवीन स्वरूप देने के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के डवलपमेंट पार्टनर यूएनएफपीए के जिला समन्वयक को जिम्मेदारी सौंपी।

सामूहिक श्रमदान से साफ-सफाई ने रखी कायापलट की नींव

चिकित्सालय का कायाकल्प करने की शुरुआत जिला

कलक्टर ने अस्पताल परिसर में साफ-सफाई के लिए सामूहिक श्रमदान से की। इसके बाद लगातार अस्पताल के विकास एवं सेवाओं-सुविधाओं के विस्तार में एक के बाद एक नवीन आयाम जुड़ते चले गए। इन्हीं लगातार प्रयासों का ही नतीजा है कि आज जिला चिकित्सालय नए रंग-रूप में निखर कर सामने है, जिसे देखकर ही सुकूनदायी अहसास होता है।

जिला प्रशासन, यूएनएफपीए और अस्पताल प्रशासन की सहभागिता से इस अस्पताल की तमाम व्यवस्थाओं को आदर्श स्वरूप दिए जाने के प्रयास लगातार जारी है।

हर तरफ दिख रहा सकारात्मक सुखद परिवर्तन

अस्पताल का कायापलट करने वाली कार्ययोजना के अनुरूप चिकित्सालय की नियमित साफ-सफाई एवं स्वच्छता भरा माहौल दिखने लगा है। वार्ड की शय्याओं, द्वारों, खिड़कियों, फर्श, छतों, वार्ड एवं अस्पताल के परिसरों के रंग-रोगन, जल व्यवस्था की दृष्टि से 3-3 हजार लीटर जल संग्रहण टंकियों की स्थापना, कचरा एवं बायोवेस्ट संग्रहण तथा निस्तारण के लिए विशेष डिजाइनयुक्त 15 वेस्ट बिन्स, रिवोल्विंग डस्टबिन, हैण्डवाश के लिए उपयोग की हिदायतों की

जानकारी देने के साथ ही स्थापित वॉशबेसिन, सीएसआर में प्राप्त धनराशि से टॉयलेट व्यवस्था में सुधार व रिनोवेशन, ड्रैनेज तंत्र में व्यापक सुधार, उद्यान विकास, वार्ड सुधार, प्रसूति कक्ष को नवीन स्वरूप देने जैसे ढेरों काम होने के बाद अस्पताल का स्वरूप निखर उठा है।

जिला अस्पताल में लम्बे समय से तकनीकी कारणों से खराब पड़ी सीटी स्कैन मशीन के ठीक होने से इसका उपयोग जारी है। इससे मरीजों को जांच की सुविधा प्राप्त हो रही है।

इन सभी गतिविधियों के मूर्त रूप लेने के उपरान्त अस्पताल में स्वच्छता के साथ ही परिसर संक्रमण से मुक्त हुआ है। अस्पताल की सहयोगी सेवाओं को सम्बल मिला है। सेहत के लिए जरूरी सभी उपायों को अपनाया जा रहा है। चिकित्सा स्टाफ की क्षमताओं के अभिवर्द्धन के लिए बहुआयामी गतिविधियों पर बल दिया जा रहा है।

प्रतीक्षालयों ने दी राहत

जिला अस्पताल में प्रतीक्षालय का अभाव अरसे से महसूस किया जा रहा था। मरीजों के साथ आने वाले परिजनों के लिए अस्पताल परिसर में बैठने के अभाव में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। जिला मुख्यालय पर यह एकमात्र बड़ा सरकारी अस्पताल है, जहां 300 किलोमीटर दूर तक के मरीज इलाज कराने आते हैं। इनके रिश्तेदारों और परिजनों के साथ ही सामान्य मरीजों के लिए खास प्रबन्ध नहीं थे। इस वजह से गर्मी और बरसात के दिनों में लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था।

अस्पताल निरीक्षण के दौरान लोगों की इस पीड़ा को जिला प्रशासन ने समझा और तत्काल इस दिशा में कार्य करने के लिए रूपरेखा बनाई गई। इसके उपरान्त एक माह से भी कम अवधि में जिला अस्पताल परिसर में करीब 200 लोगों की बैठक व्यवस्था के लिए तीन अलग-अलग स्थानों पर हवा व रोशनीयुक्त एवं छायादार प्रतीक्षालय बनवाकर आरामदायी कुर्सियां लगाई गई हैं। नियमित रूप से साफ-सफाई का प्रबंध किया गया है। पास ही प्याऊ भी उपलब्ध है। दूरदराज से आने वाले मरीजों, उनके परिजनों एवं सामान्य मरीजों के लिए यह प्रतीक्षालय राहत भरे और सुकूनदायी साबित हो रहे हैं।

खेत तलाई योजना ने बदली खेती-किसानी
असिंचित क्षेत्र में किसान ले रहे तीन फसलें

- हरिओम सिंह गुर्जर

असिंचित क्षेत्र के किसानों को सिंचाई का पानी उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई खेत तलाई योजना कोटा जिले के लाडपुरा, खैराबाद एवं इटावा क्षेत्र के किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। सिंचाई सुविधा के अभाव में जो किसान दो फसलें नहीं ले पा रहे थे, वे अब खेत तलाई में पानी की उपलब्धता के आधार पर खरीफ के साथ ही रबी सीजन में गेहूं, सरसों, चना और मैथी जैसी फसलों का उत्पादन कर रहे हैं, वहीं पशुओं के लिए पर्याप्त मात्रा में चारा उपलब्ध होने से दुग्ध उत्पादन भी बढ़ा है। खेत तलाई स्कीम राज्य के उन जिलों में लागू है जहां भू-जलस्तर काफी नीचे चला गया है या नहरी सिंचाई सुविधा उपलब्ध नहीं है।

इस योजना से किसानों की आय में लगातार बढ़ोतरी हो रही है तथा सिंचाई के पानी के लिए वे आत्मनिर्भर हो रहे हैं। कृषि विभाग द्वारा किसानों को जागरूक कर वर्षा के अतिरिक्त पानी को खेत तलाई बना कर संग्रहण करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। जिले में अब तक 100 किसानों द्वारा खेत तलाई बनाई जाकर सिंचाई के पानी के उपयोग में लिया जा रहा है। खेत तलाई योजना के सार्थक परिणाम आने से कोटा में हर साल किसान आवेदन कर रहे हैं। पहले इस योजना से जुड़ने के लिए जहां 0.5 हैक्टेयर भूमि की आवश्यकता थी वहीं अब इसे घटा कर 0.3 हैक्टेयर कर दिया गया है जिससे अधिक से अधिक किसान इस योजना का लाभ उठा कर अधिक पैदावार प्राप्त कर रहे हैं।

होने लगी बंपर पैदावार

लाडपुरा पंचायत समिति क्षेत्र के गलाना गांव निवासी किसान रामविलास शर्मा ने 2019 में योजना में आवेदन कर खेत तलाई का निर्माण कराया था। फार्म पॉण्ड उसके परिवार के लिए वरदान साबित हुआ है। लाडपुरा का यह क्षेत्र चम्बल सिंचित परियाजना से वंचित है ऐसे में खरीफ की फसलों के अलावा अन्य मौसम की फसलों का उत्पादन लेने के लिए सिंचाई के पानी की आवश्यकता होती है। खेत तलाई निर्माण से पानी सुरक्षित होने से वह खरीफ व रबी में बंपर पैदावार ले रहा है। रामविलास कहता है ''इस साल भी औसत से कम बारिश होने से आम किसानों को चना, सरसों जैसी फसलों की बुवाई करनी पड़ रही है, लेकिन जिन किसानों ने खेत तलाई का निर्माण कराया है उन्होंने गेहूं, सरसों, चना और मैथी की बुवाई की है।''

जल संरक्षण को मिल रहा है बढ़ावा

खेत तलाई (फार्म पॉण्ड) योजना से खेत का पानी खेत में ही रहता है। जिससे आस-पास के कुंए भी रिचार्ज हो जाते हैं। पानी बह कर नहीं जाता है। खेत की उर्वरता बनी रहती है। मिट्टी का कटाव नहीं होता है। पानी ज्यादा समय एक जगह ठहरने से जल संरक्षण को बढ़ावा मिलता है। किसान खेत तलाई के किनारों पर फलदार पौधे लगा कर अतिरिक्त आय बढ़ा सकता है। पौधे लगाने पर किसान को उद्यान विभाग द्वारा अनुदान भी दिया जाता है।

ऐसे तैयार किया जाता है फार्म पॉण्ड

खेत तलाई के लिए किसान कृषि विभाग में आवेदन कर सकता है। किसान के पास न्यूनतम 0.3 हैक्टेयर कृषि भूमि होना जरूरी है। आवेदन के बाद किसान को खेत तलाई खोदने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है। किसान द्वारा चिन्हित जगह पर 20X20X3 मीटर का गहरा गड्ढा बनाना होता है। जिसके लिए 63 हजार रुपये अनुदान तथा प्लास्टिक सीट बिछाने पर 90 हजार रुपये अनुदान दिया जाता है।

फव्वारा लगाना अनिवार्य

फव्वारा सिंचाई करने पर ही किसानों को खेत तलाई स्वीकृत किया जाता है। कृषि विभाग द्वारा इसके साथ डीजल इंजन पर दस हजार का अनुदान दिया जा रहा है। किसान चाहे तो उद्यान विभाग से सोलर सेट लगाने पर भी अनुदान प्राप्त कर सकता है। इसमें साठ प्रतिशत का अनुदान दिया जा रहा है। किसान को इस योजना के लिए ई-मित्र से ऑनलाइन आवेदन करना होता है। इसके लिए जमाबन्दी की नकल, नक्शा, आधार कार्ड एवं जन आधार कार्ड देने होते हैं।

कोरोना संकट के बीच जरूरतमंद
किसानों को राहत

– सोहनलाल

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की पहल पर कोरोना संकट के बीच बिना किसी शुल्क के किराए पर ट्रैक्टर एवं कृषि यंत्र उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई योजना जगन्नाथ बैरवा, मन्नी देवी, गंगा सिंह, सूरजकरण, पिन्नू कंवर जैसे प्रदेश के हजारों जरूरतमंद किसानों के लिए राहतकारी साबित हुई है। इसके तहत काश्तकारों को खेती के विभिन्न कामों के लिए एक लाख घण्टे से ज्यादा की मुफ्त सेवा मुहैया कराई गई है।

मार्च महीने में रबी फसल की कटाई और थ्रेसिंग का कार्य चल रहा था। इसी दौरान कोरोना महामारी की वजह से लॉकडाउन हो गया। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने ऐसी विपरीत परिस्थितियों में किसानों की मदद के लिए कई कदम उठाए। लघु एवं सीमान्त काश्तकारों के लिए विशेष मदद की जरूरत महसूस करते हुए राज्य सरकार ने बिना किसी शुल्क के ट्रैक्टर एवं कृषि यंत्र किराए पर उपलब्ध कराने की योजना शुरू की। इस पर कृषि मंत्री श्री लालचन्द कटारिया के निर्देशन में आयुक्त डॉ. ओमप्रकाश एवं अन्य विभागीय अधिकारियों ने कृषि यंत्र निर्माता टैफे कम्पनी से समन्वय कर इसे क्रियान्वित करवाया। काश्तकारों ने टैफे कम्पनी को एसएमएस भेजकर फसल कटाई, थ्रेसिंग एवं अन्य कृषि गतिविधियों के लिए आग्रह किया जिस पर कम्पनी ने अपने रजिस्टर्ड ट्रैक्टर एवं कृषि यंत्रों से सम्पर्क कर सेवा उपलब्ध करवाई।

इस योजना के तहत रबी फसल की कटाई थ्रेसिंग के बाद खरीफ फसलों की बुवाई के लिए जरूरतमंद पात्र किसानों की मांग अनुसार सेवा मुहैया कराई गई। अप्रैल से जुलाई के बीच 27 हजार 379 किसानों को 1 लाख 3 हजार 16 घंटे की सेवा देकर फायदा पहुंचाया। इस योजना से लाभान्वित जयपुर जिले की फागी तहसील के जयसिंहपुरा गांव के किसान जगन्नाथ बैरवा बताते हैं कि उन्होंने टैफे कम्पनी को एसएमएस भेजकर कल्टीवेटर के लिए आग्रह किया। कम्पनी ने ट्रैक्टर मालिक चेतन को उनके खेत पर भेजा जिसने 5 घंटे कल्टीवेटर चलाया। इसकी प्रति घंटे 650 रुपए रेट के हिसाब से कोरोनाकाल में उन्हें तीन हजार से ज्यादा की राहत मिली। ट्रैक्टर मालिक चेतन के अनुसार, उन्होंने इसी गांव की मन्नीदेवी के खेत पर चार घंटे और ज्ञानचंद बैरवा के 2 घंटे से ज्यादा की कल्टीवेटर सेवा दी। नजदीकी पाचला गांव के काश्तकार गंगासिंह ने इस योजना का फायदा उठाते हुए छह घंटे प्लाऊ करवाया, जिससे उनके 4500 रुपए का खर्चा बच गया। सूरजकरण के खेत में 7 घंटे तक बाजरा बुवाई से 5250 रुपए एवं महिला काश्तकार पिन्नू कंवर के 4 घंटे बाजरा बुवाई से 3 हजार रुपए की बचत हुई। इसी प्रकार सीकर जिले की फतेहपुर तहसील के नबीपुरा गांव के किसान रणवीर सिंह ने इस योजना के तहत अपने खेत में प्लाऊ करवाया। इन्हें 5 घंटे सेवा दी। प्रति घंटा 750 रुपए के हिसाब से इन्हें 3 हजार 750 रुपए का फायदा हुआ है।

विभागीय अधिकारियों की सक्रियता एवं किसानों की जागरूकता के चलते कई जिलों में इस योजना के बहुत ही उत्साहजनक परिणाम मिले हैं। सीकर जिले में सबसे ज्यादा 4516 किसानों को करीब 21 हजार घण्टों की सेवा मुहैया कराई गई है। इसी प्रकार जयपुर में 3470 किसानों को 13 हजार 178, अलवर में 3203 किसानों को 9979, भरतपुर में 1842 किसानों को 6568, झुंझुनूं में 1750 किसानों को 7933 घण्टे की सेवा दी गई। इसी तरह टोंक के 1683 काश्तकारों को 6363, जोधपुर के 1439 किसानों को 5948, नागौर के 1333 किसानों को 5441, बारां के 1244 किसानों को 3675, झालावाड़ के 1152 किसानों को 4363, अजमेर के 1151 किसानों को 3952, पाली के 1074 किसानों को 3039 तथा करौली के 1025 काश्तकारों को 3185 घण्टे की सेवा मुहैया कराई गई है।

सीमावर्ती अंचलों में बिजली सुविधाओं का विस्तार

रोशन हुई ढाणियां, बिजली सुधार ने पाए नए आयाम

– डॉ. दीपक आचार्य

बिजली सुविधाओं के विकास एवं विस्तार तथा संरचनात्मक सुदृढ़ीकरण के लिए राज्य सरकार द्वारा पिछले दो वर्ष से निरन्तर भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। इसी का परिणाम है कि राजस्थान में बिजली सेवाओं और सुविधाओं के विस्तार के साथ ही सीमावर्ती जैसलमेर जिले में भी विद्युत उपभोक्ताओं को राहत मिली है।

जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि. जैसलमेर द्वारा हाल के 2 वर्षो में बिजली के क्षेत्र में कई महत्त्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की गई हैं। विद्युत आपूर्ति एवं सुदृढ़ीकरण से संबंधित विभिन्न योजनाओं में जैसलमेर जिला अग्रणी रहा है।

घरेलू विद्युतीकरण (मय सौभाग्य योजना)

जिले में इस योजना में ऑफ ग्रिड मे 7 हजार 876 तथा ऑन ग्रिड में 4 हजार 760 परिवारों को विद्युत कनेक्शन जारी कर लाभान्वित किया गया। जिससे जीवनस्तर बढ़ा है और सुविधाओं का लाभ आमजन को सुकून देने की दिशा में निरन्तर विस्तार पाता जा रहा है।

नये 33/11 केवी सब स्टेशनों का निर्माण

जिले में इस योजना में कुल 15 सब-स्टेशन (हेम सिंह की ढाणी, कीता, कोडा, शिल्पग्राम, किशनघाट, जसकरणपूरा, खुईयाला, सरदार सिंह की ढाणी, काठोडा, भाकरानी, केरालिया, 155 आरडी, सुभाष नगर, भेंसडा, खीन्वजवास) बनाये गये हैं, जिसमे कुल 47.25

एमवीए क्षमता जोड़ी गयी है। इससे अच्छी गुणवत्ता का वोल्टेज प्राप्त होने लगा है।

पूर्व में स्थापित 33/11 केवी सब स्टेशनों का क्षमता विस्तार

जिले में इस योजना में कुल 19 सब-स्टेशनों की क्षमता विस्तार कर अतिरिक्त पावर ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं। इनमें लखा, मोहनगढ़, थईयात, सागाना, सांकडा, दवाड़ा, सांगड़, फतेहगढ़,

चेलक, भोपा, छोड़िया, सम, डेलासर, झिनझिनयाली, हरियासर, प्रतापपुरा, राजमथाई, बांधेवा एवं मसूरिया शामिल हैं। इनसे कुल 59.85 एमवीए क्षमता आवर्धन किया गया है, जिससे अच्छी गुणवत्ता का वोल्टेज प्राप्त हुआ है।

नये कृषि कनेक्शन हुए जारी

इस योजना में कुल 3 हजार 352 कृषि कनेक्शन जारी किये गये हैं। इससे कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है व किसानों का जीवनस्तर बढ़ा है।

137 फीडर सुधार कार्य

इस योजना में 33 केवी तथा 11 केवी के कुल 137 फीडर पर सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत सुधार किया गया है। इससे ग्रामीणों व किसानों को उच्च गुणवत्ता की विद्युत आपूर्ति की जा रही है।

जिले में बिजली समस्याओं व शिकायतों के त्वरित निदान के लिए विभिन्न स्तरों पर पुख्ता व्यवस्थाएं की गई हैं। जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जैसलमेर के अधीक्षण अभियन्ता नरेन्द्र कुमार जोशी बताते हैं जैसलमेर जिले में बिजली से जुड़ी योजनाओं के विस्तार की दिशा में हाल के 2 वर्ष में हुए कार्यों से उपभोक्ताओं को परंपरागत समस्याओं से राहत मिली है और जोधपुर डिस्कॉम की गतिविधियों ने रफ्तार पायी है।

दौसा : ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में लगभग 3020 ई-मित्र कियोस्क क्रियाशील

– रामजीलाल मीना

ई-मित्र कियोस्क राज्य सरकार को प्रभावी ढंग से एक मजबूत तकनीकी आधार प्रदान कर रहे है। नागरिकों की सेवा करना और उनके माध्यम से पारदर्शिता, जवाबदेही और दक्षता बनाना कंप्यूटरीकरण है। ई-मित्र जैसे नागरिक केंद्रित आवेदन केन्द्र जिले में शुरू किए हैं। इसमें भामाशाह, जीआईएस, राजसम्पर्क, ई-लर्निंग, ई-लाड्र्स, ईपीडीएस, ईऑफिस, एलडीएमएस, राजफैब, एसजेएमएस आदि इसमें शामिल हैं। इन पहलों के कारण अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हुए हैं। इसमें संतुष्टि, संचालन में सरकारी पारदर्शिता और दक्षता को बढ़ाया है।

आईटी कार्यान्वयन लगातार आवेदनों की संख्या, उनके आधार के मामले में अपना आधार बढ़ा रहा है। जटिलता और उपयोग ,विभिन्न वेब और मोबाइल एप्लिकेशन जिनमें राज्य के महत्वपूर्ण अनुप्रयोग हैं। राजस्थान संपर्क, ई-मित्र, भामाशाह, ईपीडीएस, बीएसबीवाई आदि की सेवाएं तेजी से बढ़ रही हैं। इसके लिए उद्देश्य, अनुप्रयोगों की गुणवत्ता और प्रदर्शन की जांच करने के लिए विभिन्न उपकरणों का उपयोग किया जा रहा है।

दौसा जिले में मजबूत तकनीकी आधार प्रदान करने के लिये ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में लगभग 3020 ई-मित्र कियोस्क (ग्रामीण क्षेत्र-2225 व शहरी क्षेत्र-795) क्रियाशील हैं। जिनके माध्यम से वर्तमान में लगभग 300 से अधिक सेवाएं आमजनों को दी जा रही है। जिले में ग्राम पंचायतों पर स्थित भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्रों पर 241 ई-मित्र प्लस मशीनों की स्थापना की जा चुकी है। ई-मित्र प्लस मशीन पर डिजिटल जमाबन्दी की प्रिन्ट, सामाजिक सुरक्षा पेन्शनर्स का भौतिक सत्यापन, मूल निवास, जाति, विकलांग प्रमाण पत्र, विवाह, जन्म-मृत्यु आदि प्रमाण पत्रों का प्रिन्ट, बायोमैट्रिक उपस्थिति, बिजली-पानी, मोबाइल,डीटीएच के बिल /रिचार्ज, सॉफ्ट वीसी इत्यादि की सुविधा उपलब्ध है। इसी प्रकार जिले के शहरी क्षेत्रों में 106 स्थानों पर ई-मित्र प्लस मशीनों की स्थापना की जा चुकी है। जिनमें PVC कार्ड प्रिन्टिग की सुविधा भी उपलब्ध है।

जिले में कुल ई-मित्र प्लस कियोस्क – 347

➢ **राजस्वान (RajSWAN)**

- जिले के 40 विभिन्न कार्यालयों को ऑप्टीकल फाईबर (Optical Fiber) से जोड़कर इन्टरनेट कनेक्टीविटी उपलब्ध करवायी जा चुकी है।

➢ **राजनेट (Raj Net)**

- जिले में ग्राम पंचायतों पर स्थित 227 भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्रों पर इन्टरनेट सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु राजनेट (RajNet) की स्थापना की जा चुकी है। 207 वर्तमान में क्रियाशील है।

➢ **बीबीएनएल (BBNL)**

- भारत ब्रॉडबैण्ड नेटवर्क लि. द्वारा ग्राम पंचायत स्तर तक उच्च क्षमता की गति के इन्टरनेट कनेक्टिविटी का कार्य किया जा रहा है। वर्तमान में 185 ग्राम पंचायतों में ऑप्टीकल फाईबर केबल से इन्टरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध करवायी जा चुकी हैं। शेष ग्राम पंचायतों का कार्य प्रगति पर है।

➢ **आधार**

- जिले में 97.64 प्रतिशत जनसंख्या का आधार कार्ड जारी किया जा चुका हैं एवं वर्तमान में आधार नामांकन एवं अद्यतन कार्य प्रगतिशील है। आधार नामांकन एवं अद्यतन का कार्य सरकारी कार्यालयों के परिसर में संचालित 20 आधार केन्द्रों पर किया जा रहा है। नये आधार ऑपरेटर बनने की प्रक्रिया विभाग द्वारा ऑनलाइन कर दी गयी है।
- 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों के आधार नामांकन हेतु 104 आधार टेबलेट क्रियाशील हैं।

➢ **वीडियो वॉल**

- किसी भी सरकारी योजना का लाभ व्यक्ति एवं समूह तक पहुंचाने के लिए एवं जनसामान्य को जागरूक किये जाने हेतु इलेक्ट्रोनिक ऑडियो-वीडियो वॉल की स्थापना जिला कलेक्ट्रेट, दौसा परिसर एवं जिले की सभी 6 पंचायत समितियों पर (कुल 7) की गयी है। जिसके माध्यम से नियमित रूप से सरकारी योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है।

➢ **आई.पी. फोन (IP Phone)**

- जिले एवं ब्लॉक मुख्यालयों के 82 कार्यालयों तथा जिले में ग्राम पंचायतों पर स्थित 234 भारत निर्माण राजीव गांधी

सेवा केन्द्रों पर सुगम संचार हेतु IP Phone की स्थापना की गयी है। जिले में कुल 316 IP Phone की स्थापना की गयी है।

➢ **स्काडा (SCADA)**

- जिले में ग्राम पंचायतों पर स्थित भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्रों पर विद्युत पावर की सप्लाई को Manage and Monitor करने हेतु 223 भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्रों पर स्काडा पैनल स्थापित किये गये हैं।
- क्रियाशील - 210 (201-JVVNL तथा 9-राजनेट UPs

➢ **आर.एफ टॉवर (R.F. Tower)**

- जिले के सभी ब्लॉक/ नगरपालिका मुख्यालयों पर राज वाई-फाई परियोजना अन्तर्गत R.F. Tower की स्थापना हेतु 8 जगह चिन्हित कर साईल टेस्टिंग सम्पल पूर्व में लिए जा चुके हैं। वर्तमान में 4 स्थानों महवा, छारेडा (लवाण), सिकराय एवं लालसोट में R.F. Tower स्थापित किये जा चुके है। शेष 4 स्थानों पर कार्य प्रगति पर है।

➢ **अभय कमाण्ड एंड कंट्रोल सेंटर**

- जिले के संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी CCTV कैमरों के माध्यम से करने के लिए अभय कमाण्ड एंड कंट्रोल सेंटर की स्थापना की जा चुकी है। जिले में कुल 196 खम्भों पर 409 कैमरे लगाये जाने प्रस्तावित हैं।
- वर्तमान में 257 कैमरे क्रियाशील हैं।

कुल 121 खंभों पर स्थापित 257 कैमरों में से 99 खंभों पर 229 कैमरें अभय कमाण्ड एंड कंट्रोल सेंटर में ऑनलाइन हैं तथा 22 खम्भों पर 28 कैमरें SD Card के जरिये ऑफलाइन रिकार्डिंग कर रहे हैं। ●

श्रीगंगानगर

भवन निर्माण श्रमिक कल्याण योजना

राज्य सरकार की आर्थिक मदद से बच्चों की उच्च शिक्षा की राह हुई आसान

- ऋतु सोढ़ी

राज्य सरकार द्वारा श्रमिकों के कल्याण के लिये चलाई जा रही भवन निर्माण श्रमिक कल्याण योजना के तहत बड़ी संख्या में श्रमिकों को लाभ मिला है। श्रमिक परिवार को आर्थिक सम्बल के साथ-साथ उनके परिवार एवं बच्चों की शिक्षा में यह योजना सहारा बनी है।

श्रीगंगानगर जिले के अर्जुन नगर वार्ड नम्बर 1 निवासी श्री सोमदत्त पुत्र श्री निरंजन लाल भवन निर्माण में निर्माण श्रमिक के रूप मिस्त्री का काम करता है। इनका भवन एवं अन्य निर्माण अधिनियम के तहत निर्माण श्रमिक का पंजीयन करवाया हुआ है। उन्होंने बताया कि उनकी एक पुत्री 21 वर्ष व दूसरी पुत्री 12 वर्ष एवं एक पुत्र 20 वर्ष व दूसरा पुत्र 18 वर्ष का है। उनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है, ऐसे हालात में जीवन यापन करना बहुत कठिन हो गया था। श्रम विभाग द्वारा उनके दोनों पुत्रों को निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजना के तहत कुल 18 हजार रुपये मिले, जिससे उन्हें उच्च शिक्षा प्रदान करवाने में वह सक्षम हुआ है। सोमदत्त ने राज्य सरकार की इस योजना की सराहना करते हुए कहा कि यह कल्याणकारी योजना हम जैसे श्रमिकों के लिये बहुत ही लाभप्रद है तथा बच्चों को शिक्षा दिलाने में कारगर साबित हुई है। ●

सीकर

लोगों को मिला सरकारी योजनाओं का फायदा

- पूरण मल

माही को पालनहार योजना से मिला सम्बल

राज्य सरकार द्वारा संचालित पालनहार योजना बच्चों का पालन-पोषण करने के साथ ही उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सहायक सिद्ध हो रही है। सीकर जिले के रोहिताश खटीक निवासी वार्ड नम्बर 12, पलसाना रोड़, खण्डेला ने बताया कि वर्ष 2012 में उसके इकलौते पुत्र हेमराज खटीक की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। पुत्र की मृत्यु के बाद उसके परिवार पर दु:ख का पहाड़ टूट पड़ा। उसकी पुत्रवधू भी कुछ समय बाद पुनर्विवाह करके चली गई। इसके उपरान्त उसकी पौत्री माही की समस्त जिम्मेदारी व परिवार के लालन-पालन का भार उस पर आ गया। ऐसी विपरीत परिस्थिति में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की योजनाओं की जानकारी उसे मिली। इसके पश्चात रोहिताश ने पालनहार योजना व पेंशन योजना के लिए आवेदन किया। कुछ ही समय में उसे दोनों योजनाओं का लाभ प्राप्त होने लगा जिससे वह अपने परिवार का पालन-पोषण करने के साथ-साथ अपनी पौत्री माही को अच्छी शिक्षा दिलाने में सक्षम हुआ। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की तरफ से प्रतिवर्ष 30 हजार रुपये की सहायता प्राप्त होने से आज वह अपना जीवन अच्छे तरीके से व्यतीत कर रहा है। उन्होंने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का तहेदिल से आभार व धन्यवाद ज्ञापित किया है। ●

बायोमैट्रिक से खाद्यान्न वितरण हुआ आसान

राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से पोस मशीन द्वारा बायो मैट्रिक सत्यापन से खाद्यान्न वितरण होने से लाभार्थी को उसका राशन सीधे तौर पर मिल रहा है। लाभार्थी सुरजाराम, राशनकार्ड संख्या 008209200151 (एपीएल) महरोली श्रीमाधोपुर ने बताया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से पॉश मशीन द्वारा जब से बायोमेट्रिक सत्यापन से खाद्यान्न वितरण शुरू हुआ है तब से उसे राशन सामग्री सीधे तौर पर मिल रही है। वह अब पूरे माह में कभी भी जाकर अपने हक का गेहूं आदि सुविधानुसार प्राप्त कर सकता है और मोबाईल पर मैसेज भी प्राप्त होने लग गया है जिससे उसे कीमत और मात्रा का ज्ञान भी हो जाता है। कोविड-19 के दौरान जब रोजगार एवं परिवार के भरण-पोषण की समस्या होने लगी तब खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत प्रत्येक माह दुगुना राशन नि:शुल्क मिलने लगा है जिससे उसकी खाद्यान्न समस्या का समाधान हल हुआ है। ●

विष्णु कंवर की आजीविका में वृद्धि

राजस्थान ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत स्वयं सहायता समूह बनाकर आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान की जा रही है। स्वयं सहायता समूह राजीविका से सहायता प्राप्त कर महिलाएं गांव में लघु, कुटीर उद्योग संचालित कर अपना भरण पोषण कर रही है। जिले की नीम का थाना तहसील के राणासर गांव की विष्णु कंवर ने बताया कि स्वयं सहायता समूह से जुड़ने से पहले उसके परिवार की स्थिति बहुत कमजोर थी। परिवार की वार्षिक आय बहुत ही कम थी जिससे परिवार का गुजारा नहीं होता था, फिर वह राजीविका से जुड़ी। उसके समूह का नाम शिव शंकर है, उसने एसएचजी के बी.के. का कार्य किया जिससे आमदनी बढ़ी। फिर उसने राजीविका में समूह सखी के पद पर कार्य किया जिससे आय में और बढ़ोतरी हुई। विष्णु कंवर ने बताया कि वह गांव के समूहों की देखभाल करके समूहों की मीटिंग में गई और उसने समूह से ऋण लेकर एक सिलाई मशीन खरीदी, जिससे सिलाई करके अपनी आजीविका बढ़ाई। गरीब महिलाओं को समूह से जुड़ने के लिए प्रेरित किया व राजीविका के उद्देश्यों के बारे में समझाया व महिलाओं को बचत करना सिखाया तथा रोजगार का प्रशिक्षण दिलवाया। कोरोना महामारी के चलते मैंने और मेरे समूह के सदस्यों ने मास्क बनाकर वितरण किया। आरपी के पद पर कार्य करते-करते मेरे परिवार की स्थिति अच्छी हो गई। उसने बताया कि राजीविका से जुड़कर ग्रामीण महिलाएं भी अपने जीवन-स्तर को इसी तरह आगे बढ़ा सकती है। राजीविका एक विभाग ही नहीं मेरा एक परिवार है जिसने मुझे हमेशा आगे बढ़ने के लिये प्रोत्साहित किया। ●

ड्रिप संयंत्र स्थापित कर 52 मैट्रिक टन खीरे का उत्पादन

जिले के दांतारामगढ़ तहसील के मण्ढा सुरेरा की विमला देवी पत्नी चन्द्राराम जाट ने अपनी आजीविका चलाने के लिए पिछले कई वर्षों से परम्परागत खेती के माध्यम से अपने परिवार का पालन पोषण कर रही थी। कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं के प्रचार-प्रसार से प्रभावित होकर विमला देवी ने कृषि विभाग द्वारा संचालित राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के माध्यम से अनुदान प्राप्त कर वर्ष 2019 में ग्रीन हाउस (4000 वर्गमीटर), सामुदायिक जल स्रोत, सोलर पम्प संयंत्र एवं ड्रिप संयंत्र स्थापित कर परम्परागत कृषि को छोड़ हाईटेक उद्यानिकी के माध्यम से संरक्षित खेती की और अग्रसर हुई। विभागीय अधिकारियों की देखरेख में खीरा किस्म टर्मीनेटर की बुवाई कर फसल ली। कृषक द्वारा अपनी मेहनत एवं लगन से कार्य करने के फलस्वरूप 52 मैट्रिक टन खीरे का उत्पादन लिया। उत्पादित खीरे को मार्केट में विक्रय कर राशि लगभग रुपये 9.00 लाख की कुल आय प्राप्त की। मण्ढ़ा सुरेरा में भूमिगत जल स्रोत के अभाव के कारण वर्षा जल ने खेती कार्य में फसलों के लिए अमृत के समान कार्य किया। खेती के व्यवसाय में अच्छी आय होने से पूरा परिवार खुशहाल हुआ एवं समाज में गौरवान्वित भी हुआ। मण्ढा सुरेरा में उद्यान विभाग के माध्यम से आज तक लगभग 08-10 ग्रीन हाऊस, शेडनेट हाउस का निर्माण करवाया जाकर कृषकों को लाभान्वित किया जा चुका है। ●

भढाढर में मॉडल तालाब से वर्षा जल का किया संरक्षण

ग्राम भढाढर के जोहड़े में कोई भी पानी एकत्रित होने का साधन नहीं था, जिसके कारण वर्षा ऋतु के दिनों में पानी बहकर व्यर्थ हो जाता था। ग्रामवासियों ने बताया कि इस जोहड़े में सरकार की योजना मॉडल तालाब से वर्षा के जल का संग्रहण किया जा सकता है तथा भविष्य में भी कई दिनों तक इस पानी को काम में लिया जा सकता है।

इसी उद्देश्य के साथ ग्राम पंचायत की ग्रामसभा में इस कार्य की परिकल्पना की गई तथा कार्य को महात्मा गांधी नरेगा योजना की वार्षिक कार्य योजना में सम्मिलित करते हुए स्वीकृत करवाया गया। सरपंच संजू देवी ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार ग्राम में एक मॉडल तालाब निर्माण का कार्य करवाया जाना था। ग्रामवासियों के सहयोग व महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत इस कार्य को सम्पादित करवाया गया, जिससे स्थानीय ग्रामीणों को पानी की समस्या से निजात मिली है।

मॉडल तालाब के निर्माण के सम्बन्ध में पास के किसान जगदीश बगड़िया ने बताया कि इस तालाब के निर्माण से पशुपालन कार्य में सहयोग मिला है तथा आस-पास के ग्रामीणों के पानी की समस्या का समाधान हो सका है साथ ही आस-पास के भू-जल स्रोतों में पानी का जलस्तर में भी सुधार हुआ है।

इस तालाब की लगभग 15000 लीटर बरसाती पानी एकत्रित होने की भराव क्षमता है व आस-पास के 100 घरों की आबादी लाभान्वित होगी।

स्थानीय ग्रामीण कैलाश कुमार ने बताया कि पूर्व में बरसात का पानी इधर-उधर बहकर खेतों में भर जाता था, जिससे फसलें खराब होती थी। 14.72 लाख रुपये की राशि से तालाब निर्माण होने से हमारी जमीनों में भू-जल लगभग 10 फिट बढ़ गया है तथा मवेशियों के भी पानी की समस्या नहीं रही है। ●

''कोई भी भूखा ना सोए''की सोच
व संकल्प को साकार कर रही है

इंदिरा रसोई योजना

–राजेन्द्रसिंह राठौड़

जोधपुर में इंदिरा रसोई योजना मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की ''कोई भी भूखा ना सोए'' की सोच व संकल्प को बेहतर तरीके से साकार कर रही है। जोधपुर शहर में उत्तर व दक्षिण नगर निगम क्षेत्र में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती पर नारी सशक्तीकरण की प्रतीक पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गाधी की स्मृति में शुरू की गई। इंदिरा रसोई योजना के तहत 16 स्थानों पर इंदिरा रसोई संचालित हो रही है। इंदिरा रसोई से अब तक छह लाख से अधिक लाभार्थियों को 8 रुपये प्रति थाली से गुणवत्ता पूर्ण भोजन कराया जा चुका है।

इन स्थानों पर संचालित है इंदिरा रसोई

जोधपुर शहर में नगर निगम दक्षिण में दीनदयाल उपाध्याय, सूरसागर, आश्रम स्थल भगत की कोठी, एम्स अस्पताल, 12 वी रोड चौराहा, रेलवे स्टेशन जाडेजी की बगीची, सुभाष चौक आश्रय स्थल, राइका बाग बस स्टैण्ड, प्रथम पुलिया आश्रय स्थल, सूरसागर कबीर नगर आश्रय स्थल, फीदूसर चौराहा, भोमियाजी का थान व नगर निगम उत्तर द्वारा अनाज मंडी, गोकुलजी की प्याऊ, बंगाली क्वाटर आश्रय स्थल, 9 मील मंडोर, पाबूपुरा आश्रय स्थल व मथुरादास माथुर अस्पताल परिसर में इंदिरा रसोई संचालित हो रही हैं।

जोधपुर में साढ़े तीन माह में 38 लाख का किया भुगतान

जोधपुर शहर में संचालित रसोई संचालको को गत साढ़े तीन माह में 38 लाख का भुगतान किया जा चुका है। इसमे नगर निगम उत्तर में 8 रसोई संचालकों को 19 लाख व नगर निगम दक्षिण की 8 रसोई के संचालको को 19 लाख का भुगतान किया जा चुका है। भुगतान की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन की जा रही है ताकि पारदर्शिता बनी रहे है।

क्वालिटी व शुद्धता का रखा जा रहा पूरा ध्यान

नगर निगम आयुक्त उत्तर व नगर निगम आयुक्त दक्षिण द्वारा अपने-अपने क्षेत्र में संचालित इंदिरा रसोइयों की व्यवस्थाओं पर सीधा ध्यान रखा जा रहा है।

कोरोना गाइडलाइन की हो रही है पालना

इंदिरा रसोई में कोरोना गाइडलाइन की पूरी तरह पालना करवायी जाती है। रसोई में भोजन करने आने वालों को मास्क पहनकर आना होता है व मास्क नहीं पहनकर आने पर उन्हें नगर निगम की ओर से मास्क उपलब्ध करवाया जाता है। उनके हाथों को सेनेटाइजर करवाकर भोजन के लिए बैठाया जाता है। सोशल डिस्टेंसिग कर ध्यान रख जाता है। नगर निगम द्वारा संचालित इन इंदिरा रसोई में सुबह का भोजन प्रात 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक व शाम का भोजन शाय 5 से रात्रि 8 बजे तक उपलब्ध रहता है भोजन के मेन्यू में दाल, सब्जी, चपाती व अचार शामिल है।

सम्मानपूर्वक बैठाकर कराते हैं भोजन

इंदिरा रसोई की स्थाई रसोइयों में सम्मानपूर्वक बैठाकर भोजन कराया जाता है। इसे एनजीओ के माध्यम से संचालित किया जा रहा है। इसका चयन जिला कलक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समन्वय एवं मॉनिटरिंग समिति द्वारा किया जाता है। इंदिरा रसोई में 12 रुपये प्रति थाली राजकीय अनुदान होता है।

इंदिरा रसोई में जनसहभागिता

इंदिरा रसोई में कोइे भी व्यक्ति एक या एक से अधिक समय पर खाना प्रायोजित कर लाभार्थियों को नि:शुल्क में खाना खिला सकते हैं। इसके लिए उसे किसी भी इंदिरा रसोई में जाकर पैसा जमा कराना होता है। इसके लिए सम्बंधित व्यक्ति के पास मोबाइल एवं ई-मेल पर मैसेज जाता है एवं प्रायोजित दिन के भोजन के समय प्रत्येक कूपन पर यह मैसेज लिखा आता है कि आज का भोजन सम्बंधित व्यक्ति द्वारा प्रायोजित है। इस योजना में जोधपुर में अनेक लोगों द्वारा लाभार्थियों को नि:शुल्क भोजन कराकर सक्रिय भागादारी निभायी जा रही है।

रसोई संचालकों को होता ऑनलाइन भुगतान

रसोई संचालकों को देय राजकोष अनुदान के मासिक भुगतान की विशेष व्यवस्था की गई है। रसोई संचालकों द्वारा पोर्टल पर सिंगल क्लिक से ऑनलाइन बिल जनरेट किया जाता है व यूआईडी पोर्टल के माध्यम से आधार ऑथन्टिकेट किया जाता है व बिल को ऑनलाइन ही बिना भौतिक हस्ताक्षर किए ऑनलाइन सॉफ्ट कॉपी में भुगतान के लिए भेज दिया जाता है। संचालक को ऑनलाइन सीधे ही बैक खाते में भुगतान हो जाता है।

इंदिरा रसोई में आईटी का बेहतर उपयोग

इंदिरा रसोई में आईटी का बेहतर ढंग से उपयोग होता है। रसोई में जो व्यक्ति भोजन करने आता है उसका फोटो खींचा जाता है व उसका नाम व मोबाइल नम्बर कम्प्यूटर में फीड कर वेब पोर्टल पर अपलोड किया जाता है। समय-समय पर स्वायत्त शासन निकाय के कॉलसेन्टर व आईटी व राज्य स्तरीय कॉलसेंटर से फोन कर भोजन की गुणवत्ता के बारे में भी सुझाव लिए जाते हैं।

समावेशी शिक्षा

–स्नेहलता शर्मा

समावेशी शिक्षा का मतलब ऐसी शिक्षा से है जिसमें सामान्य बालक और विशेष आवश्यकता वाले बालक-बालिकाओं को एक साथ अध्यापन कराया जाता हैं। शिक्षक द्वारा शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करते हुये दोनों ही प्रकार के बच्चों को अध्यापन कराते हैं, ऐसी शिक्षा को समावेशी शिक्षा कहते हैं। समावेशी शिक्षा का महत्व बढ़ रहा है। इस शिक्षा से दोनों प्रकार के बालक-बालिकाओं के एक साथ अध्ययन से समाज में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के प्रति सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहे हैं।

समावेशी शिक्षा पद्धति से एक साथ एक शिक्षण पद्धति से अध्यापन कराने से सामान्य बच्चों में विशेष बच्चों के प्रति सहनशीलता, भेदभाव में कमी, सहयोग की भावना की सोच विकसित हुई है। शिक्षक को समावेशी शिक्षा पद्धति में अध्यापन कराते समय विशेष बच्चों को वरियता देनी चाहिये जैसे:-उन्हें कक्षा की अगली लाइन में बैठाना, जिससे उन्हें ब्लैक बोर्ड देखने में आसानी हो साथ ही शिक्षक द्वारा अगली लाइन में बैठाने से विशेष बच्चों का ध्यान बराबर बना रहता हैं तथा उनसे बराबर प्रश्नोत्तर करने से भी वे सजग रहते हैं। शिक्षक को आवश्यकतानुसार टीचिंग एड के साधनों जैसे:- वर्कसीट, चित्र, उदाहरणों, कविता, कहानी, स्मार्ट क्लास, ऑडियो-वीडियो का उपयोग भी करना चाहिए। टीचिंग के साधन सभी बालक-बालिकाओं के लिये उपयोगी और रोचक होते हैं। खेल एवं वीडियो के माध्यम से पढ़ाया जाने वाला विषय जल्दी समझ में आता है। इससे कक्षा में बालक-बालिकायें भी सजग रहते हैं। संचार माध्यम प्रभावी होता है और इससे अनुशासन की भावना का स्वत: ही विकास होता है। समावेशी शिक्षण पद्वति में शिक्षक और बालक-बालिकाओं दोनो को अच्छा अध्ययन और अध्यापन का एहसास होता हैं। यह मनौवैज्ञानिक रिसर्च है कि खेल, शिक्षण और स्मॉर्ट कक्षा से सकारात्मक परिणाम दिखाई देते हैं।

दूसरी ओर अगर हम विशेष शिक्षा की बात करें तो विशेष शिक्षा में विशेष बच्चों के लिये विशेष स्कूल होते हैं, जहां केवल विशेष शिक्षकों द्वारा ही उन्हें पढ़ाया जाता हैं। विशेष पद्धति द्वारा विशेष बच्चों का सामाजिक विकास, भावनात्मक और आपसी सहयोगात्मक जैसी भावनाओं का पूर्ण विकास नहीं हो पाता है। सामान्य और विशेष बालक-बालिकाओं में दूरियां बढ़ती जाती हैं जो विशेष बच्चों के विकास में अवरोधक होती है। सामान्य बच्चे विशेष बच्चों को अपने समान नहीं मानते है। उनकी भावना उनके प्रति सहयोगात्मक भावना नहीं हो पाती है और वे उनसे पिछड़ने लगते हैं। समावेशी शिक्षा पद्धति से अच्छे परिणाम देखने को मिले रहे हैं उनके सकारात्मक परिणामों के आधार पर समावेशी शिक्षा पद्धति को लागू करने की मांग बढ़ रही है। अब विशेष स्कूलों के स्थान पर समावेशी शिक्षा पद्धति को महत्त्व मिल रहा है।

सामान्य शिक्षकों को भी भारतीय पुनर्वास परिषद् अधिनियम 1992 के अन्तर्गत विशेष शिक्षा में प्रशिक्षित करने की महत्ती आवश्यकता बतायी गयी है। जिससे सामान्य शिक्षकों को भी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान, अध्ययन और उनके भावनात्मक सोच को समझ कर अध्यापन में उनका सहयोग कर सके। इस भावनात्मक सहयोग से दोनों में सामंजस्य हो सकेगा और सामान्य शिक्षक उनकी भावनाओं को भली-भांति समझकर उसके अनुसार अध्ययन अध्यापन कार्य कर सकेंगे।

भारतीय पुनर्वास परिषद् की स्थापना संसद में वर्ष 1992 के अधिनियम के अन्तर्गत की गई। भारतीय पुनर्वास परिषद् का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। परिषद् द्वारा देशभर के विशेष शिक्षा एवं विशेष व्यक्तियों के कल्याणार्थ व्यक्तियों को प्रशिक्षण, संस्थानों को मान्यता देकर उनके प्रशिक्षणार्थियों को दिव्यांगता क्षेत्र में कार्य करने वाले प्रशिक्षित व्यक्तियों को अधिकृत करती है। साथ ही अप्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा दिव्यांगता क्षेत्र में कार्य करते हुये पाये जाने पर अधिनियमानुसार उन्हें दण्डित करने का कार्य भी करती है।

भारतीय पुनर्वास परिषद्, भारत सरकार का संवैधानिक निकाय है। यह भारत सरकार को दिव्यांगता क्षेत्र में नियम- कानून कायदे बनाने के लिये सहयोग व सुझाव देने का कार्य भी करता है।

सन् 2016 के अधिनियम द्वारा अब 21 प्रकार की दिव्यांगता निर्धारित की गई है। दिव्यांगता का निर्धारण 40 प्रतिशत से अधिक होने पर ही उन्हें केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा देय सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त होता है। 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता होने पर ही स्थानीय स्तर पर जिला अस्पतालों में दिव्यांगता प्रमाण-पत्र बनाये जाते हैं। दिव्यांगता चिकित्सा प्रमाण-पत्र के आधार पर वह कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिये अधिकृत हो जाते हैं।

हाल ही में राजस्थान के शिक्षा मंत्री श्री गोविन्द सिंह डोटसरा द्वारा दिव्यांग बालक-बालिकाओं को बिना चिकित्सा प्रमाण-पत्र के आधार पर निजी व राजकीय विद्यालयों में प्रवेश देने के निर्देश दिये गये हैं। इन निर्देश से दिव्यांगों के नामांकन में वृद्धि हुई है। साथ ही सरकार ने दिव्यांगों हेतु उच्च शिक्षा के नियमों में संशोधन किया है। इससे उच्च विशेष शिक्षा में भी विशेष शिक्षक उपलब्ध हो सकेंगे। राष्ट्रीय और राज्यस्तरीय शिक्षक सम्मान में दिव्यांग शिक्षकों एवं दिव्यांग विधार्थियों को अध्यापन कराने वाले विशेष शिक्षकों के मापदण्ड भी निर्धारित किये गये हैं। ●

पाली

बाड़मेर

चिकित्सकों ने पहले दिन टीका लगवाया।

मुख्यमंत्री ने अल्प समय में ही वैक्सीन तैयार करने पर इससे जुड़े सभी वैज्ञानिकों, विशेषज्ञों और अन्य कार्मिकों को बधाई देते हुए कहा कि सभी को उन पर गर्व है। कई ट्रायल और जांच के बाद आई यह वैक्सीन कोरोना पर विजय प्राप्त करने में मदद करेगी। अपनी जान जोखिम में डालकर कोरोना की जंग में दिन-रात जुटे स्वास्थ्य कर्मियों और अन्य कोरोना वॉरियर्स का टीकाकरण प्रारम्भ होने से आत्मविश्वास और मजबूत होगा। मुख्यमंत्री ने अपील की है कि वैक्सीन को लेकर लोग भ्रांतियों से बचें और इस अभियान को सफल बनाने में सहयोग करें।

श्री गहलोत ने इस अवसर पर टीकाकरण साइट्स पर उपस्थित चिकित्सकों, नर्सिंग कर्मियों एवं अन्य हैल्थ वर्कर्स से संवाद किया। मुख्यमंत्री ने अभियान के तहत पहला टीका लगवाने वाले एसएमएस मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉ. सुधीर भण्डारी, 93 वर्षीय विशेषज्ञ चिकित्सक डॉ. पी सी डांडिया, नर्सिंग अधीक्षक डॉ. विनोद मथुरिया तथा जोधपुर के एमडीएम अस्पताल में उपस्थित डॉ. जी एल मीणा से संवाद किया।

जलदाय मंत्री डॉ. बी डी कल्ला ने श्रीगंगानगर के सादुलशहर सीएचसी, नगरीय विकास मंत्री श्री शांति धारीवाल ने छबड़ा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ. रघु शर्मा ने जिला चिकित्सालय केकड़ी, परिवहन मंत्री श्री प्रतापसिंह खाचरियावास ने धौलपुर जिले के बाड़ी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, शिक्षा राज्य मंत्री श्री गोविंद सिंह डोटासरा ने जोधपुर के मथुरादास माथुर चिकित्सालय तथा चिकित्सा राज्य मंत्री डॉ. सुभाष गर्ग ने बांसवाड़ा जिले के आनंदपुरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर उपस्थित स्वास्थ्य कर्मियों के साथ संवाद किया। पहले चरण में प्रदेश के 4 लाख 80 हजार 977 तथा केंद्र सरकार के 6 हजार 755 स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन लगाई जाएगी। दूसरे चरण में फ्रंटलाइन वर्कर्स, तृतीय चरण में 50 वर्ष से अधिक के लोगों तथा चौथे चरण में 50 वर्ष से कम आयु के को-मोरबिड लोगों को टीका लगाया जाएगा। यह टीका पूरी तरह सुरक्षित है। टीकाकरण के लिए पंजीकरण अनिवार्य होगा तथा लाभार्थी को पहचान का दस्तावेज साथ लाना होगा।

कोटा

जालोर

कोविड टीकाकरण का राज्यस्तरीय शुभारम्भ

वैक्सीन अभियान में भी मिसाल पेश करेंगे : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य कर्मियों से किया संवाद

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा कोरोना के कुशल प्रबंधन से प्रदेश में कोविड रोगियों की संख्या सीमित होना और वैक्सीन की शुरुआत होना एक सुखद संयोग है। जिस तरह से राज्य सरकार ने सभी के सहयोग से कोरोना का बेहतरीन ढंग से मुकाबला किया है, उसी तरह इस टीकाकरण अभियान को सफल बनाकर मिसाल पेश की जायेगी। उन्होंने कहा कि वैक्सीन आने के बावजूद कोरोना को पूरी तरह समाप्त करने के लिए सभी लोगों को मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग रखने सहित अन्य हैल्थ प्रोटोकॉल की निरन्तर पालना सुनिश्चित करनी होगी।

मुख्यमंत्री ने 16 जनवरी को मुख्यमंत्री निवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कोरोना टीकाकरण के राज्य स्तरीय शुभारम्भ समारोह को संबोधित किया। प्रदेश में 167 साइट्स पर एक साथ टीकाकरण प्रारम्भ किया गया। एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. सुधीर भण्डारी के साथ ही साइट्स पर प्रमुख चिकित्सा संस्थानों के

अजमेर

बांरा

आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना

के नये चरण का शुभारम्भ

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि 30 जनवरी से प्रदेश में आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के नये चरण का शुभारम्भ होगा। प्रदेश के 1 करोड़ 10 लाख परिवारों को इस योजना का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री नि:शुल्क दवा योजना और मुख्यमंत्री नि:शुल्क जांच योजना के बाद स्वास्थ्य सुरक्षा की दृष्टि से यह योजना राज्य सरकार का एक बड़ा कदम है।

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के पैकेज की सूची में कोविड-19 और हीमोडायलिसिस को शामिल करने के लिए वित्त विभाग के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है। इन दो बीमारियों के मरीजों को स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार प्रतिवर्ष लगभग 50 करोड़ रुपये अतिरिक्त वहन करेगी।

लाभार्थी परिवार : भारत सरकार की प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में सामाजिक एवं आर्थिक जनगणना (SECC) के आधार पर 59.71 लाख पात्र लाभार्थी परिवार के सदस्य ही योजना में लाभ ले सकते हैं।

राज्य में पूर्व में संचालित भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत केवल राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के अन्तर्गत आने वाले लगभग 98 लाख परिवारों के सदस्य ही पात्र थे।

आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना में लाभार्थियों का दायरा बढ़ाते हुए सामाजिक एवं आर्थिक जनगणना (SECC)2011 के आधार पर पात्र लाभार्थी परिवारों एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के अन्तर्गत आने वाले परिवारों दोनों को सम्मिलित करते हुए लगभग **1 करोड़ 10 लाख परिवारों** को योजना का लाभ देय है। वर्तमान में उक्त में से 1 करोड़ 05 लाख लाभार्थी परिवार जनआधार डेटाबेस में जुड़े हुए है। शेष परिवारों का जनआधार रजिस्ट्रेशन करवाया जा रहा है।

प्रीमियम राशि का भार वहन : योजनान्तर्गत प्रीमियम राशि 1662 रुपये प्रति परिवार प्रति वर्ष निर्धारित की गयी है तथा जनआधार कार्ड से जुड़े उपरोक्त पात्र परिवारों में से 59.71 लाख सामाजिक एवं आर्थिक जनगणना (SECC) 2011 के परिवारों के प्रीमियम राशि का भार केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा 60 एवं 40 के अनुपात में वहन किया जायेगा। जिसमें भारत सरकार द्वारा निर्धारित केप राशि 1052 रुपये प्रति परिवार प्रति वर्ष ही वहन की जायेगी।

- इस प्रकार SECC परिवारों के कुल प्रीमियम राशि 992.38 करोड़ रुपये में से भारत सरकार द्वारा केवल 376.89 करोड़ रुपये की राशि वहन की जायेगी। शेष प्रीमियम राशि 615.49 करोड़ रुपये राजस्थान सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।
- शेष 45.51 लाख एनएफएसए परिवारों की प्रीमियम राशि 756.38 करोड़ रुपये का 100 प्रतिशत भार राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।
- इस प्रकार बीमा कम्पनी को देय कुल प्रीमियम राशि 1748.76 करोड़ रुपये में से राजस्थान सरकार का हिस्सा **(Rs.1748.76 - 376.89) = 1371.87** करोड़ रुपये होगा। अर्थात कुल प्रीमियम का केवल 21.55 प्रतिशत भाग ही भारत सरकार द्वारा वहन किया जायेगा। शेष 78.45 प्रतिशत हिस्सा राजस्थान सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।

राशि कवर बढ़ाना : नवीन योजना में बीमा कवर 3.30 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये तक किया गया है जिसमें सामान्य बीमारियों के लिए 50 हजार रुपये एवं गंभीर बीमारियों के लिए 4.5 लाख रुपये तक का इलाज दिया जायेगा।

पैकेज की संख्या में बढ़ोतरी : विगत योजना में कुल 1401 पैकेजेज का लाभ दिया जा रहा था जिसे बढ़ाकर 1572 कर दिया गया है।

फ्रॉड रोकना : योजनान्तर्गत **राज्य स्तरीय एंटी फ्रॉड यूनिट** का गठन किया गया है जो अस्पताल द्वारा सबमिट किये गये क्लेम्स की मॉनिटरिंग एवं भारत सरकार से प्राप्त ट्रिगर के आधार पर क्लेम ऑडिट करेगी। इस कार्य के लिए एक पृथक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट का भी गठन किया जा रहा है।

सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

#राजस्थान_सतर्क_है

कोरोना प्रबंधन की तरह ही टीकाकरण में भी मॉडल बनेगा राजस्थान

प्रिय प्रदेशवासियों,

पिछले लगभग 10 महिनों से दुनिया के साथ राजस्थान भी कोरोना महामारी से संघर्ष कर रहा है। मैं इस दौरान प्रदेशवासियों के अभूतपूर्व सहयोग व कोरोना वॉरियर्स के जज़्बे की खुले दिल से सराहना करता हूँ। यह आपका सहयोग ही था जिसकी बदौलत हम कोरोना से जंग में अब राजस्थान को पहले से काफी बेहतर स्थिति में ले आए हैं। लंबे समय तक चले लॉकडाउन तथा समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस की पालना कर आपने जो शानदार भूमिका अदा की, इसी का परिणाम है कि राजस्थान के प्रभावी कोरोना प्रबंधन मॉडल को देश में सराहना मिली।

बात चाहे लॉकडाउन की पालना की हो या 'नो मास्क-नो एंट्री' को जन आन्दोलन बनाने की हो, आपने हर ऐसे कदम की पालना में पूर्ण प्रतिबद्धता दर्शाई। कर्फ्यू की पालना करने तथा दीपावली पर पटाखों पर बैन की पालना करने जैसे निर्णयों को भी आपने स्वेच्छा से स्वीकार किया। इसके अलावा भीड़ से बचने, समारोह में सौ से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक जैसी सावधानियों की पालना, लॉकडाउन में जरूरतमंदों के लिए अस्थायी आवास और भोजन की व्यवस्था, माइग्रेंट लेबर के आवागमन जैसे मिशन, प्रदेशवासियों ने हर मुद्दे पर सेवा की मिसाल कायम की है।

साथियों, कोरोना की चुनौती अभी तक समाप्त नहीं हुई है। हाल ही में ब्रिटेन में एक नया स्ट्रेन आया है, यह काफी देशों में फैल चुका है। ब्रिटेन को दोबारा लॉकडाउन लगाने के लिए मजबूर होना पड़ा है। वायरस का यह नया प्रकार ज्यादा तेजी से फैलता है। हम सभी को आगे भी काफी सावधानी बरतने की जरूरत है ताकि अब तक की हमारी मेहनत बेकार न जाए। थोड़ी-सी लापरवाही भी खतरा बढ़ा सकती है।

नए वर्ष में कोरोना से बचाव के लिए प्रथम चरण में हैल्थ केयर वर्कर्स लिए वैक्सीनेशन अभियान शुरु होना एक सुखद अनुभूति है। राज्य सरकार ने टीकाकरण के लिए प्रभावी तैयारी सुनिश्चित की है ताकि वैक्सीनेशन कार्य में भी हम अग्रणी रह सकें। मुझे पूरा विश्वास है कि आप आगे भी सभी जरूरी सावधानियां अपनाते हुए सरकार को पूरा सहयोग करेंगे जिससे हम कोरोना के विरूद्ध निर्णायक जीत प्राप्त कर सकें।

सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।

(अशोक गहलोत)
मुख्यमंत्री

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग

Postal Regd. No. Jaipur City/413/2020-22
Registered with Registrar of Newspapers of India under R. No. 56175/1991

150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

#राजस्थान_सतर्क_है

माननीय मुख्यमंत्री
श्री अशोक गहलोत
के कर कमलों से

कोविड-19 टीकाकरण
अभियान का शुभारम्भ
स्वास्थ्य प्रतिरक्षा की दिशा में एक मजबूत कदम

कोविड-19 टीकाकरण अभियान के प्रमुख बिंदु

- प्रथम दिन 16 जनवरी 2021 को 33 जिलों में 167 लोकेशन पर एक साथ शुरुआत
- प्रथम चरण में जनवरी माह में केवल हेल्थकेयर वर्कर्स का ही टीकाकरण
- टीकाकरण के लिए लाभार्थी के रजिस्टर्ड मोबाइल पर दिनांक, समय व स्थान का संदेश आने पर ही पहुंचें, **यह टीका पूरी तरह से सुरक्षित है**
- टीकाकरण प्रत्येक सप्ताह में चार दिन होगा, इसके लिए पंजीकरण अनिवार्य है
- **चरणवार टीकाकरण प्राथमिकता क्रम-** (i) हेल्थकेयर वर्कर्स (ii) फ्रंट लाइन वर्कर्स (iii) 50 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोग (iv) 50 वर्ष से कम उम्र परन्तु को-मोर्बिड (अन्य बीमारियों से ग्रसित) व्यक्ति

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान

#DIPRRajasthan

प्रकाशक व मुद्रक – सूचना एवं जनसम्पर्क आयुक्त, महेन्द्र सोनी द्वारा सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के लिए, शासन सचिवालय, जयपुर (राजस्थान) से प्रकाशित सम्पादक– डॉ. लोकेश चन्द्र शर्मा • मैसर्स प्रिन्ट 'ओ' लैण्ड, सी–4, बाईस गोदाम, जयपुर से मुद्रित, 'राजस्थान सुजस'–पृष्ठ संख्या 60, मूल्य 20 रुपये/ 60,000 प्रतियां